सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 17 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 28 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

शून्यकाल में उठाइयेगा । माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । राजू बाबू, सारी बातें आ गई हैं, कृपया आप बैठिये । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : जी महोदय, मैं पूछने के लिए खड़ा हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल सारी बातें आ गई हैं, अब उसको आगे मत बढ़ाइये । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कल रख दी है । आपको हमने कल दो–दो बार मौका दिया था । कल क्वेश्चन ऑवर में और जीरो ऑवर में मैंने आपको समय दिया था । अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सारी बातें आ गई हैं, अब बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–38, श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या–138, विभूतिपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय बाबू, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सरासर, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना की मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और रामविलास पासवान जी के बारे में जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया ....

(व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार : महोदय, ये सत्ता पक्ष के लोग क्वेश्चन ऑवर को नहीं चलने देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

(व्यवधान जारी)

मार्शल, कृपया तख्ती हटा लें । माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिये । प्लीज बैठ जाइये । राजू जी, बात आ गई है, बैठ जाइये । अब डिस्टर्ब नहीं कीजिये, आप लोग बैठिये । प्लीज बैठ जाइये । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं । मार्शल, तख्ती हटा दें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–स्वीकारात्मक है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, 2–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–4081,

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, पत्रांक–4081, दिनांक–24.11.2025 के द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं, क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिये । राजू तिवारी जी से आग्रह है कि आपकी सारी बातें आ गई हैं, अब डिस्टर्ब नहीं कीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को एच॰आर॰एम॰एस॰ पोर्टल पर अद्यतन कार्रवाई करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा चुका है ।

साथ ही, विभागीय आदेश ज्ञापांक–3068, दिनांक–23.12.2024 द्वारा....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : राजू तिवारी जी, प्लीज आप बैठ जाइये । हमने कल आपको पूरा समय दिया है । क्वेश्चन ऑवर को डिस्टर्ब मत कीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, विभागीय आदेश ज्ञापांक–1816, दिनांक–12.11.2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोगों की बातें प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है । माननीय मंत्री का जवाब हो रहा है, जवाब सुनिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, पे–मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 01 अप्रैल, 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया है तथा यदि किसी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के अनुरूप निर्धारित किये जाने का निदेश दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, 3–इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है । महोदय, माननीय सदस्य का कोई पूरक हो तो बतायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में तीन तरह के शिक्षक काम करते हैं । एक तो जो नियोजित हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वह हैं, दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं और तीसरा जो है वह बी॰पी॰एस॰सी॰ शिक्षक हैं और इन तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है, शहरी एच॰आर॰ए॰ मिलता है और किसी को नहीं मिलता है और दोनों, दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी डिफरेंस किया हुआ है किसी को 10 प्रतिशत मिलता है, किसी को 08 प्रतिशत मिलता है, किसी को 04 प्रतिशत मिलता है तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो एच॰आर॰ए॰ देते हैं, उसमें समान रूप से कोई निर्णय लेकर आप 10 प्रतिशत अगर देते हैं तो सब के लिए क्या 10 प्रतिशत करना चाहते हैं या नहीं ? यह मेरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि तीन तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं लेकिन विसंगति किसी तरीके की न हो, चाहे वह पे का मामला हो, एच॰आर॰ए॰ का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता देय है उसमें न हो तो हमलोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप से देने के लिए हमलोगों ने कार्रवाई की है । विशेषकर एच॰आर॰ए॰ का इन्होंने प्रश्न उठाया तो उसमें पाँच तरह के रेट हैं । एक जो दिल्ली में रहते हैं वह 30 परसेंट ऑफ बेसिक पे है, बाकी टीयर–2, टीयर–3, टीयर–4, टीयर–5 में क्रमशः 20, 10, 7.5 और 05 प्रतिशत बेसिक पे का मिलता है तो अधिकांश जहां तक हमलोगों की समझ है, अधिकांश जगहों पर जीरों में है, यह जो वेतन विसंगति है या एच॰आर॰ए॰ का मामला है, अन्य को हमलोगों ने ठीक कर लिया है और कहीं–कहीं काम बाकी है, बहुत कम रह गया है जहां तक हमारी समझ है करीब 90 प्रतिशत समस्या का समाधान हो चुका है, आने वाले दिनों में 10 प्रतिशत का भी हमलोग कर लेंगे । संख्या बहुत है, 05 लाख 87 हजार से ज्यादा शिक्षक हैं तो

कहीं–कहीं पर कैल्कुलेशन में और खासकर विशिष्ट शिक्षकों के बहुत सारी कागजातों में भी कमी पायी जाती है लेकिन इसके, और हमलोग विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बात आ गई है । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, खड़े हों, नहीं तो हम आगे बढ़ जायेंगे ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइये । आपका स्पष्ट हो गया है, माननीय मंत्री जी जवाब स्पष्ट दिये हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, स्पेशिफिक जगह है जहां पर यह नहीं है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि 10 प्रतिशत बच गया है, 90 प्रतिशत हो गया है और 10 प्रतिशत जो बचा है सरकार उसके लिए प्रयासरत है । वह भी जल्दी कर लिया जायेगा ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा कहना है कि मैं आपको स्पेशिफिक बताना चाहूँगा विभूतिपुर के संदर्भ में चूंकि मैं वहां से आता हूँ, शिक्षक वहां हमसे मिलते हैं। महोदय, नरहन पंचायत के मध्य विद्यालय, नरहन उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय, नरहन, प्राथमिक विद्यालय, नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कापन, माधोपुर वार्ड नं॰–06 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, भरपुरा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिख कर दे दीजिये । अभी पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिला के अंदर जो है...

अध्यक्ष : ठीक है, आप लिख कर दे दीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, यह जो सवाल है वह पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहां के डी॰ई॰ओ॰ के स्तर पर और इसके साथ ही कई बार हाईकोर्ट के भी कई वेतन विसंगति का मामला जो है समस्तीपुर डी॰ई॰ओ॰ के पास में पड़ा हुआ है, उसको अविलंब माननीय मंत्री जी द्वारा दिखवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दिखवा लीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जी, महोदय ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–39, श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या–216, जहानाबाद)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है । साथ ही, विभागीय आदेश

ज्ञापांक–4207, दिनांक–22.11.2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब मिला है ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, हमने जवाब अभी देखा है । मैं सीधा पूरक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के तमाम राज्यकर्मी जितने भी हैं, उन सब के वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित वित्त विभाग निर्णय करता है, उन्हीं का संकल्प है उसके हिसाब से निर्णय होता है लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनके इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से सीधा पूछना चाहता हूँ कि बाकी राज्यकर्मियों की तरह ही उनका भी जो वेतन वृद्धि है 01 जुलाई और 01 जनवरी को होता है तो उसके अनुरूप करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस पर सहमति ली जाती है । दूसरा जो माननीय सदस्य ने अपना उठाया तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं तब उनको जो भी सरकारी सेवक को, जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा, उनको भी मिलेगा और जब से उन्होंने जो एक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और करीब 2.5 लाख जो पास किए हैं तो वे लोग भी सरकारी सेवक हो गए, उन्हें भी वे सारी सुविधाएं देय हैं जैसा कि पूर्व के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया तो उस वक्त भी हमने कहा था और इसीलिए हमलोगों ने चूंकि उनकी कैटेगरी अलग थी, इसलिए अलग से इसका निर्धारण करना पड़ा लेकिन उनके साथ किसी तरह का भेद–भाव और विसंगति का प्रश्न नहीं उठता है । धन्यवाद।

टर्न–2 / अंजली / 17.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आई0पी0गुप्ता ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है । शिक्षा विभाग का जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि वेतन वृद्धि दिनांक–01 जनवरी, 2026 से देय होगा । 01 जनवरी, 2025 को उन्होंने विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया । जेनरली जो भी वित्त विभाग से हैं उनको जुलाई, 01 से मिलना शुरू होता है, तो पूरा एक साल का इनका

वेतन वृद्धि समाप्त हो गया, जब कि राज्य के अन्य कर्मी अगर होते, तो उनको वेतन वृद्धि वित्त विभाग के हिसाब से होता । मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि वे बाकी कर्मियों की तरह ही जो उनका आदेश है, इसको निरस्त करके वित्त विभाग के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करवाना चाहते हैं कि नहीं और दूसरा, जो भी वेतन विसंगति है और जो एरियर भुगतान हो रहा है, तो उसको तत्काल रूप से एकदम मिशन के रूप में, क्योंकि हर जगह पर, इस पर अलग–अलग जगहों पर भ्रष्टाचार कर और पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि अब एरियर मिलेगा कि नहीं ?

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं सीधे दो पूरक प्रश्न पूछता हूं कि जो भी उनको एरियर पेमेंट होना है, तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अलग से पैसा दिए पेमेंट हो और दूसरा, वित्त विभाग के अनुरूप बाकी राज्य कर्मी के हिसाब से उनको वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, यह मैं सीधा जानना चाहता हूं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक एरियर का प्रश्न है, तो वह डी0बी0टी0 के माध्यम से चूंकि सरकारी सेवक हैं, एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर, ह्यूमन रिर्सोसेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत जो भी सॉफ्टवेयर है, जिसमें पूरे बिहार के सरकारी सेवकों को दिया जाता है, तो किसी को कोई चेक या अलग से कैश नहीं दिया जाता है, इसलिए अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है और हमारी नजर में नहीं है, तो डायरेक्ट डी0बी0टी0 के माध्यम से एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के थ्रू उन्हें दिया जाता है, एरियर कैलकुलेट करके सीधे उनको पेमेंट होता है और जहां तक इन्होंने तिथि का बताया है उसको हम देख लेंगे, लेकिन जहां तक है कि आप एक बार जब पास कर जाते हैं उसके बाद आपकी काउंसिलिंग होती है, चूंकि संख्या बहुत थी, ढाई लाख से ऊपर थी, तो काउंसिलिंग में उनको वक्त लगा, काउंसिलिंग के बाद ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, इसलिए इस तरह की बात हुई, फिर भी, चूंकि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है उस पर पुनः हम विचार करेंगे ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता जी । अनुमति आपको नहीं है । बैठिए । आप पहले बैठिए। गुप्ता जी, खड़े होइए । बैठिए । सारी बातें आ गई हैं । बिना अनुमति के नहीं बोलिए । संदीप सौरभ जी, बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ : बहुत जरूरी सवाल है महोदय...

अध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं । राहुल जी ने सारी बातें रख दी हैं । गुप्ता जी, आप खड़े होइए । प्लीज, आप खड़ा होइए ।

अल्पसूचित प्रश्न सं॰–40, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं॰–75, सहरसा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–अस्वीकारात्मक । भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, 2006 एवं D.O.No.-9-7/2017 Desk (MDM), Dt.-29.04.2019 के आलोक में राज्य के विद्यालयों में एन॰जी॰ओ॰ द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा समय–समय पर एन॰जी॰ओ॰ से भोजन आपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है जिसका अनुपालन राज्य द्वारा किया जाता है ।

राज्य के विभिन्न जिलों में एन॰जी॰ओ॰ द्वारा आच्छादित विद्यालयों के बच्चों को मेनू अनुसार निर्धारित भोजनावकाश अवधि में गुणवत्तापूर्ण गरमा–गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।

2–मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2115, दिनांक–08.08.2025 द्वारा रसोइया–सह–सहायक को माह अगस्त–2025 से उनके मानदेय में 1650/– रुपये की वृद्धि करते हुए 3,300/– रुपये मानदेय कर दिया गया है ।

3–वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है । भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य के विद्यालयों में एन॰जी॰ओ॰ एवं विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरा सवाल सरकार से यह था कि कलस्टर किचन के माध्यम से स्कूलों में जो खाना पहुंचाया जा रहा है, वह गुणवत्ताविहीन है और ठंडा खाना पहुंचाया जाता है, सरकार का जो जवाब है, वह अस्वीकारात्मक है । फिर भी दिया है, अब सरकार कहती है कि जिसका अनुपालन, ठीक है एन0जी0ओ0 सप्लाई कर रहा है, इसमें मेरे दो पूरक हैं महोदय ।

अध्यक्ष : पूछिए । पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : एक, सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण गरमा–गरम खाना पहुंचाया जा रहा है, यह जो गरमा–गरम है इसका टेंपरेचर नापने के लिए क्या सरकार के पास सेंट्रलाइज कोई थर्मामीटर है नंबर–1 ।

दूसरा, सरकार स्कूलों में रसोइया को बहाल करके रखी है, दो से सात है छात्रों की संख्या के अनुसार से, जब आपके पास रसोइया है, तो क्या सरकार यह जो कलस्टर किचन बाहर में बैठा कर रखी है एन0जी0ओ0 के माध्यम से, वही एन0जी0ओ0 हमारे पास जो रसोइया है उसको यूज करके स्कूल में ही खाना बना सकता है कि नहीं यही दो पूरक प्रश्न मेरा है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, तो उसके लिए अच्छी संस्थाओं से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाता है इस आलोक में हम कहना चाहेंगे जैसे चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग (सी0आई0एम0पी0) पटना से, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI) ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना, एल0एन0 मिश्रा इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ऑफ मैनजेमेंट इंस्टीट्यूट पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बोध गया, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कीटिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाई न्यूट्रिशन, आई0एच0एम0 बोध गया, तो इन संस्थाओं से हमलोगों ने 27 चेकिंग कराया है और इसके आधार पर कुछ महीनों में हमलोगों ने जो 6 केंद्रीयकृत, जो कुछ जगहों पर हैं, उसमें से मशरख तथा परसा, खगड़िया, बहादुरगंज, नवानगर तथा चकाई जमुई की अवधि विस्तार नहीं देकर के इन लोगों की अपूर्ति बंद करा दी है, उनको रद्द कर दिया है क्योंकि वहां पर गुणवत्ता में शिकायत मिली थी, हमलोगों ने इन इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी जांच कराया है और जहां तक रसोइयों की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनका मानदेय भी दोगुना हुआ और अधिकांश जगहों पर उन्हीं के द्वारा यह किया जा रहा है, लेकिन संख्या चूंकि छात्र–छात्राओं की कृपया माननीय महोदय और सदय यह जानना चाहेंगे तो हम बताना चाहेंगे कि अमूमन जिस दिन हमारा स्कूल चलता है तो एक करोड़ 3 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देते हैं और हमलोगों के पास रसोइया की संख्या करीब दो लाख है, तो इस वजह से कई जगहों पर या जरूरत पड़ जाती है कि हमलोगों को एन0जी0ओ0 के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई करें । कहीं भी रसोइयों के हित का हम लोगों नुकसान नहीं होने दिया है कि इसके कारण रसोइयों का नुकसान हो और अधिकांश जगहों पर वह बना रही हैं और इस तरीके से हमलोग कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण भोजन हमलोग दें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह । पूछ लीजिए । प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल एन0जी0ओ0 से नहीं है । हम सहरसा के 4 विद्यालयों में गए और सारे लोगों ने मुझे शिकायत की मैं चाहता हूं मंत्री जी संवेदनशील हो जाएं, इतना ही मकसद है । मैं आपकी व्यवस्था पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं बस इतना ही कहना है मुझे ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा के जिन जगहों पर इन्होंने जिक्र किया है, इसमें इन्होंने जेनरल क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लिखकर दे देंगे तो हम अलग से उसका जांच करा लेंगे ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं०–41 श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं०–111, गोरेयाकोठी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री देवेशकान्त सिंह ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, मैं पूछता हूं । महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त, अनुशासनिक कार्रवाई), संवर्ग नियमावली, 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त, अनुशासनिक कार्रवाई), संवर्ग नियमावली, 2025 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–1670, दिनांक–07.07.2025 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु निदेशित किया गया है, जिसके आलोक में सभी जिला द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की गई है और अब तक 5236 विद्यालय लिपिकों एवं 5 हजार राशि विद्यालय परिचारी अर्थात् कुल 5818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत भी हूं । लेकिन अभी भी तीन हजार से स्कूलों में, हाईस्कूल और जो माध्यमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें अभी भी क्लर्क की पोस्ट खाली है, स्कूल का काम बाधित होता है, चाहे हेडमास्टर कर रहे हैं, चाहे वहां परिचारी का काम आप किससे करा रहे हैं हमलोग तो....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : मैं पूरक ही पूछ रहा हूं कि आखिर किससे काम कराया जा रहा है, जहां खाली है वहां किससे कराया जा रहा है । हमलोग जिन स्कूलों के अध्यक्ष हुए हैं तो परिचारी की नियुक्ति नहीं होने के चलते स्कूल की सफाई इत्यादि बाधित है और काफी स्कूलों के हेडमास्टर या कोई मास्टर क्लर्क काम कर रहे हैं तो स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है । साथ ही, मैं यह जानना चाहूंगा कि रोस्टर अगर बना है, तो रोस्टर क्यिलरेंस प्राप्त कर लिया गया है तो इसका विज्ञापन किसी महीने में प्राप्त है कि नहीं, आखिर करना है तो कब तक कर लेंगे ? क्या डी0ई0ओ0 साहब ही कर लेंगे या कर्मचारी चयन आयोग से भी इनकी नियुक्ति का सरकार विचार रखती है, अगर रखती है तो सरकार बताए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, पहली बात जो भी परिचारी की नियुक्तियां होंगी वह कर्मचारी चयन आयोग से होगा । दूसरी बात है कि हमलोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की हैं, अभी इतनी नियुक्तियां चूंकि शिक्षकों की कमी है, तो इस वजह से TRE-4 में हमलोगों ने भी अपनी जो भी अनुशंसाएं हैं और जो भी

मांग हैं उनको बी0पी0एस0सी0 को दे दिया है, 45000 से ज्यादा है । उसको चरणबद्ध तरीके से हमलोग शुरू करेंगे आने वाले समय में परिचारी का इससे होगा । जहां तक इन्होंने साफ–सफाई के बारे में कहा, तो अधिकांश जगहों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ–सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश जी ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूछ लीजिए । एक बार पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

आप क्यों खड़े होते हैं बिना अनुमति के । हर चीज में खड़ा होना जरूरी है ।

(व्यवधान)

नहीं–नहीं । बिना आसन की अनुमति के खड़ा न हों । मौका देंगे आपको, संदीप जी, बैठिए । कभी–कभी उठना चाहिए ।

(व्यवधान)

हर क्वेश्चन में आप खड़ा हो जाते हैं । बोलिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, माननीय मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, टी0आर0ई0–4, मेरा कहना है कि क्लर्क की नियुक्ति के लिए क्या कर्मचारी चयन आयोग से कराना चाहते हैं कि नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है अधिकतम लोगों को रोजगार देना तो यह तो व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें सीधे विज्ञापन देकर परिचारी की बहाली, क्लर्क की बहाली भी जिस भी आयोग से या इनका अपना ही, जैसे–आधारभूत संरचना शिक्षा विभाग की है वैसे ही कोई व्यवस्था करके क्या इसको किसी माध्यम से तत्काल किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी परेशानी है ।

(क्रमशः)

टर्न–3 / पुलकित / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री देवेशकान्त सिंह : जब इंटर का फॉर्म, जब दसवीं का फॉर्म भराया जाता है, हर स्कूल में विवाद हो जाता है । फलाने मास्टर करेंगे, फलाना हेडमास्टर करेंगे । बहुत बार कोई मास्टर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है । स्कूलों में विवाद बढ़ता चला जा रहा है । स्कूल का ताला कौन खोलेगा, इस विषय पर बहस हो जाती है। मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी से होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुसार इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो उसके तहत यह

कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए । इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए । इसकी समय सीमा माननीय मंत्री जी निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा कि इसको अभी जो शिक्षक वाली जो बहाली होने वाली है, उसमें वक्त लगा क्योंकि रोस्टर क्लीयरेंस है । उसी तरह से अनुकंपा वाला, वह भी काफी समय से लंबित था, उसको हम लोगों ने बहुत सलीके से किया है और इसमें भी हम लोग कर्मचारी चयन आयोग से ही कराएंगे । क्योंकि अगर फिर एक बार आप स्थानीय स्तर पर इस तरह का आप अधिकार दे देंगे, तो उसमें फिर बहुत शिकायतें होंगी । इस वजह से हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन हम लोग की मंशा बहुत स्पष्ट है । शिक्षा विभाग ने तो सबसे ज्यादा नौकरियां दीं और आने वाले दिनों में भी हम लोग नौकरियां देंगे जहां पर रिक्तियां हैं । माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी जो चिंता है, वह हमें मालूम है उनकी चिंता पर हम लोग काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये, प्लीज । बिना अनुमति के मत बोलिये, मेरा आपसे आग्रह है । अब लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा ।

श्री जिवेश कुमार : स्कूल में शिक्षकों को पानी पिलाने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : उसी के लिए मंत्री जी ने कहा है जल्दी करेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : मैनपावर एजेंसी से कराये, मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है ।

अध्यक्ष : जिवेश जी, माननीय मंत्री ने जवाब दिया है । वह भी होगा ।

श्री जिवेश कुमार : इसमें कोई काम किया है । शिक्षा विभाग ने जोरदार नौकरी दी है लेकिन जो शिक्षक स्कूल में है काम करने वाला एक परिचारी.....

अध्यक्ष : वह भी होगा । हो गया है । सरकार तैयार है करने के लिए ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–42, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक ।

2–आंशिक स्वीकारात्मक ।

3–वस्तुस्थिति यह है कि रिट पिटिशन (सिविल) नं0–132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.03.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में त्रि–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया, गठित समिति द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक–3595, दिनांक 07.10.2025 द्वारा सभी जिलों में कार्यरत कुल 816

अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षकों का काउंसिलिंग कराया गया । काउंसिलिंग में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के CRR No का सत्यापन राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय से कराया जा चुका है ।

तत्पश्चात् रिट पिटिशन (सिविल) नं0–132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–25.11.2025 को न्यायादेश पारित करते हुए निदेशित किया गया कि वैसे अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षक को ही विशेष शिक्षक के पद पर समायोजन किया जाए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

उक्त के क्रम में काउंसिलिंग में सफल पाए गए कुल 788 शिक्षकों में से 125 शिक्षक, जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, को विशेष शिक्षक के पद पर समायोजन हेतु उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कराया गया ।

तद्पोरांत स्क्रीनिंग समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, राज्य निःशक्तता आयुक्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के आधार पर कुल 125 अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षकों को विशेष शिक्षक के रूप में नियमानुसार समायोजन की अनुशंसा की गई है । अनुशंसित अभ्यर्थियों का अर्हता प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन ससमय करा लिया जाएगा ।

साथ ही, राज्य सरकार द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल–7279 पद सृजित कर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं0–42/2025 के आलोक में विशेष विद्यालय, अध्यापक के पदो पर नियुक्ति हेतु एकल प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक–29.01.2026 को किया गया ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभाले, ठीक उसी समय ये हमारे नेत्रहीन छात्र, मूक–बधिर छात्र, इन लोगों की चिंता की गई और उस समय जो विशेष शिक्षकों का प्रावधान ही नहीं था, फिर भी विशेष शिक्षक, लगभग 805 विशेष शिक्षकों को सरकार ने उन्हें अनुबंध के आधार पर रखा। वह पिछले 10 साल से न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे थे कि हमें रेगुलर कर दिया जाए । अभी 2025 में माननीय न्यायालय ने आदेश किया और माननीय मंत्री जी ने इसकी वैकेंसी निकाली और लगभग 7279 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति निकली । महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब अच्छा है, मेरा इसमें केवल दो ही पूरक है कि जिन 788 शिक्षक जो 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं और उनमें पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण मात्र 663 शिक्षकों के लिए क्या कोई पात्रता परीक्षा फिर से करेंगे ? क्योंकि मात्र 125 शिक्षकों का ही समायोजन हो पा रहा है और किन्हीं कारणों से, जैसे शिक्षकों के लिए, सामान्य

शिक्षकों के लिए बार–बार सरकार अवसर दे रही है, तो एक अवसर क्या विशेष शिक्षकों के लिए, जो 20 साल से हमारे मूक–बधिर और नेत्रहीन छात्रों को पढ़ा रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, तो क्या जो 663 शिक्षक छूट रहे हैं, उनके लिए कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेंगे ? साथ ही साथ जिन 125 शिक्षकों का समायोजन हुआ है, उनकी वरीयता कब से निर्धारित होगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वरीयता का जहां तक प्रश्न है, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है और सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत हैं, तभी से होगी । दूसरी बात यह क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअल और फिर जब सरकारी सेवक हो जाते हैं, तो उसी समय जब आप सरकारी सेवक होते हैं, तभी से एक उसकी गणना की जाएगी । दूसरा, इन्होंने जो अपनी चिंता जाहिर की है कि उसमें शेष जो बचे हुए हैं, हालांकि एक बार काउंसलिंग करायी गयी थी, सफल नहीं हुए थे, इस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी । लेकिन चूंकि माननीय सदस्य की चिंता है इतने लोगों की, पुनः हम विचार उस पर जरूर करेंगे । धन्यवाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–43, श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र सं0–63, कटिहार)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न वित्त विभाग को हस्तांतरित है । अगली डेट में आपका प्रश्न आयेगा।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–44, डॉ॰ कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र सं0–170, बरबीघा)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : 1–अस्वीकारात्मक । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना शहर के परिवेशीय वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एक अध्ययन बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस से कराया जा रहा है । इसका दायरा मात्र पटना शहर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र तक ही है । सूचित करना है कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई अध्ययन का प्रारूप प्रतिवेदन में अन्य शहरों का उल्लेख नहीं है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से प्राप्त आंकड़ों के अनसार पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों की तुलना में राज्य के लगभग सभी शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी सूक्ष्म धूल कणों के स्तर में सुधार दर्ज की गई है ।

2– अस्वीकारात्मक । नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस वातावरण में सल्फर डॉइऑक्साइड से मिलकर सूक्ष्म धूल कणों (PM2.5) में बढ़ोतरी करती है । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा अभी इसका अध्ययन

किया जा रहा है । अंतिम अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसकी पुष्टि की जा सकेगी ।

3– उपर्युक्त प्रश्नों में दी गई जानकारी और सकारात्मक वायु गुणवत्ता रुझानों के आलोक में प्रश्न अस्वीकारात्मक है ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है परंतु उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसमें दो खंड है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : मैं पूरक ही पूछ रहा हूं । दोनों खंड में मेरा पूरक है । खंड एक में मेरा पूरक है कि पार्टिकुलर मैटर PM2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है । जवाब आया है कि PM2.5 की मात्रा में सुधार दर्ज किया गया है । इसका मतलब है कि हवा में PM2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है । मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हवा में PM2.5 की मात्रा कम करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

महोदय, दूसरा पूरक भी पूछ लेते हैं ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए, एक साथ अच्छा रहेगा ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : दूसरा पूरक है खंड दो के उत्तर से, उसमें भी हम संतुष्ट नहीं है। क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार वायु प्रदूषण से बचाव का कोई अग्रिम कार्यक्रम करना चाहती है ? जरा मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पटना शहर के परिवेशीय वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एक अध्ययन, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने भी किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस से कराया जा रहा है । इसका दायरा मात्र पटना शहर और इसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित है । सूचित करना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई अध्ययन का प्रारूप प्रतिवेदन में अन्य शहरों का उल्लेख नहीं है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों की तुलना में राज्य के लगभग सभी शहरों में जो PM2.5, सूक्ष्म धूल कणों के स्तर में सुधार दर्ज की गई है और यह जो अंतिम अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसकी पुष्टि की जा सकेगी । महोदय, इसका अध्ययन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–'क'–342, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र सं0–213, काराकाट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक ।

2–आंशिक स्वीकारात्मक । पर्यवेक्षण गृह, रोहतास में किशोर न्याय परिषद रोहतास, कैमूर एवं अन्य न्यायालयों से आदेशित विधि विवादित किशोर भी आवासित किये जाते हैं ।

पर्यवेक्षण गृह, रोहतास की वर्तमान संरचनात्मक संख्या क्षमता 50 किशोरों के आवासन के ही उपयुक्त है ।

3– वर्तमान में राज्य के 21 जिलों में 50 किशोरों के आवासन क्षमता वाले पर्यवेक्षण गृह संचालित है, जिनमें 38 जिलों के किशोरों को सम्बद्ध कर आवासित कराया जाता है । निकट भविष्य में अन्य जिलों यथा कैमूर एवं बेगूसराय में शीघ्र नए पर्यवेक्षण गृहों का संचालन प्रारम्भ होना संभावित है । किसी एक पर्यवेक्षण गृह में किशोरों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने की स्थिति में गृहों के सुगम संचालन के दृष्टिकोण से समय–समय पर किशोर न्याय परिषद के आदेशानुसार अन्य जिलों के पर्यवेक्षण गृहों में किशोरों को स्थानांतरित किया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग । अरूण बाबू उत्तर प्राप्त है ?

श्री अरूण सिंह : महोदय, उत्तर मिला है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, हम जवाब पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए । माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, हमारा सवाल था रोहतास के पर्यवेक्षण गृह में 80 से 100 बेड बढ़ाने का था । सरकार ने जो जवाब दिया है कि 50 बेड के पर्यवेक्षण गृह की हमने 21 जिलों में स्थापना की है । महोदय, कैमूर और बेगूसराय में नया हम बनाएंगे, क्योंकि रोहतास में अटैच था कैमूर और रोहतास का । हम सरकार से इतना ही जानना चाहते हैं कि रोहतास 19 ब्लॉक का जिला है और कैमूर छोटा जिला है । सभी जगह क्या समान रूप से 50 बेड का पर्यवेक्षण गृह बनाया जा रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में हमारा जो पर्यवेक्षण गृह है वह 21 जिला में है और 50 क्षमता का है । इसमें ये संख्या, चूंकि बच्चे जो भी आते हैं विधि विवादित, तो वे आते और जाते रहते हैं, परमानेंट तो रहते नहीं हैं। दूसरी बात अभी हम लोगों की पूरे राज्य में अगर संख्या देखेंगे, तो 1224 है । और 21 जिला में अगर है, तो 1050 है, कुछ ज्यादा है । इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं । कुछ जिला में क्षमता से कम भी बच्चे हैं, जैसे आपके रोहतास जिला में मात्र 48 है और पर्यवेक्षण गृह 50 क्षमता का है । इसको हम लोग आकलन करके और जिस जिला में ज्यादा बच्चे लगातार रह रहे हैं, वहां पर हम लोग क्षमता विस्तार करेंगे ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, मेरा कहना है कि जो पर्यवेक्षण गृह है, एक बड़े जिले और छोटे जिले का समान रूप से 50 बेड का ही पर्यवेक्षण गृह बनाना है ? क्योंकि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि 48 हमारे यहां हैं । हमारे पास न्यूज है कि 60 वहां अभी हैं, जिससे परेशानी होती है । इसीलिए हमने मांग की है और यह दिशा के मीटिंग में जिलाधिकारी ने जवाब दिया, यह कोई हम दूसरे जगह से नहीं लाए हैं । यह रोहतास जिला के दिशा की मीटिंग में जिलाधिकारी ने साफ...

श्री मदन सहनी, मंत्री : डी0एम0 जो रिपोर्ट भेजते हैं वही तो हम भी जवाब दे रहे हैं न । 48 है बच्चा वहां, और 50 की क्षमता है ।

श्री अरूण सिंह : हमारे पास भी रिपोर्ट है । आपके पास भी रिपोर्ट है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : हम बोल रहे हैं न कि जहां आवश्यकता होगी, हम लोग क्षमता का विस्तार करेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी दिखवा लेंगे । माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

टर्न–4 / हेमन्त / 17.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–1135, श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या–77, महिषी)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नरगा में 03 वर्ग कक्ष एवं 01 क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है, विद्यालय में नल–जल योजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। विद्यालय भवन में मरम्मति की आवश्यकता है। विद्यालय में नये वर्ग कक्ष निर्माण हेतु लगभग 2000 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है।

उक्त विद्यालय की मरम्मति, 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय का निर्माण, विद्युतीकरण तथा पेयजल की आपूर्ति हेतु जिला शिक्षा कार्यालय के पत्रांक 62, दिनांक 05.02.2026 द्वारा प्रबंध निदेशक, BSEIDC, पटना द्वारा स्वीकृति के उपरांत अगले 08 माह में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

श्री गौतम कृष्ण : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग से यह जानना चाहा था कि सहरसा जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के सत्तौर पंचायत में नवृसजित विद्यालय है, जो नरगा में संचालित होता है। उस विद्यालय का भवन बेहद जर्जर है, किसी दूसरे के यहां वह विद्यालय संचालित है, जहां शौचालय एवं पेयजल की सुविधा भी सही से नहीं है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए न।

श्री गौतम कृष्ण : माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया है..

अध्यक्ष : अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं..

श्री गौतम कृष्ण : उत्तर सही नहीं है और दूसरी बात है कि मैंने दो विद्यालयों का जिक्र किया था, एन0पी0एस0 का और बिरजाईन का, दोनों एक जगह मर्ज होकर किसी दूसरे के दरवाजे पर संचालित हो रहे हैं, तो मैंने अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि दोनों के पृथक भवन कब बनाये जायेंगे और जो जवाब आया,

उसमें था कि शौचालय है और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गयी है। तो किस पत्रांक, दिनांक से भौतिक जांच रिपोर्ट, जो विभाग से आयी है, क्या माननीय मंत्री जी वह बताने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने उत्तर में देखा होगा कि आठ महीने समय दिया हुआ है। आठ महीने में पूरा किया जायेगा।

माननीय मंत्री।

श्री गौतम कृष्ण : सर, शिक्षा विभाग ने तो यह माना है और फोटो भी दिखाना चाहता हूं, बेहद जर्जर स्थिति में है।

अध्यक्ष : सरकार तैयार है करने के लिए।

श्री गौतम कृष्ण : सरकार तो तैयार है, इसका मतलब सरकार मान रही है कि वहां विद्यालय बेहद खराब स्थिति में है। लेकिन इतने दिनों से क्यों नहीं, यह प्रश्न था मेरा।

अध्यक्ष : वह बन जायेगा। माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल–मिलाकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक 76 हजार से ज्यादा स्कूल हैं। अधिकांश स्कूलों में हम लोग बी0एस0आई0डी0सी0 से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि वहां पर जो स्थिति है, अच्छी नहीं है। इसी वजह से हमने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस को हम लोग प्राथमिकता के तौर पर लेंगे और उसमें जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको करेंगे और इसमें हम लोग निर्माण कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1136, श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या–42, पिपरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड के ग्राम–पं0 दीनापट्टी स्थित मध्य विद्यालय दीनापट्टी में कुल नामांकन–519, शिक्षकों की संख्या–09 कमरों की संख्या–09 है। 04 कमरों की मरम्मति की आवश्यकता है। ई–शिक्षाकोष के माध्यम से BSEIDC, पटना को मरम्मति हेतु सूचना अग्रसारित कर दी गयी है।

2– अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, दीपापट्टी से 1.5 से 02 कि0मी0 की दूरी पर बमगोला आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिटियाही स्थित है, जो दीनापट्टी पंचायत में स्थित है। मध्य विद्यालय, दीनापट्टी के पोषक क्षेत्र के नजदीक ही 3 से 4 कि0मी0 की दूरी पर सत्यदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिपरा एवं प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिपरा स्थित है। जहां छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन होता है।

इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमने पूछा था कि पिपरा प्रखंड के ग्राम पंचायत दीनापट्टी स्थित मध्य विद्यालय, दीनापट्टी को उत्क्रमित करके प्लस टू विद्यालय बनाना चाहेंगे। महोदय, जिसका जवाब तीन खंडों में प्राप्त हुआ है। पहला खंड स्वीकारात्मक है, वह सही भी है। लेकिन दूसरे खंड का जवाब आया है, अस्वीकारात्मक, अध्यक्ष महोदय, उसमें बताया गया है कि मध्य विद्यालय दीनापट्टी से डेढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बमगोला आवासीय उच्च विद्यालय, लिटियाही स्थित है, जो दीनापट्टी पंचायत में स्थित है। मध्य विद्यालय, दीनापट्टी के पोषक क्षेत्र के नजदीक ही 3–4 किलोमीटर की दूरी पर सत्यदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री रामविलास कामत : महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह जो जवाब आया है कि यह बमगोला उच्च विद्यालय दीनापट्टी पंचायत अंतर्गत है, यह असत्य है, गलत है, जवाब गलत है।

अध्यक्ष : आप आग्रह कीजिए माननीय मंत्री जी से।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, हम नजदीक से जानते हैं कि वह बसहा पंचायत में पड़ता है और आवासीय विद्यालय है। उसी क्षेत्र, उसी परिसर में कस्तूरबा विद्यालय भी चल रहा है और वहां बच्चों की भीड़ ज्यादा होती है। दीनापट्टी पंचायत के बच्चों का एडमिशन उस विद्यालय में नहीं हो पाता है और दीनापट्टी एक महत्वपूर्ण पंचायत है। महोदय, वहां पर अभी मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि दीनापट्टी पंचायत में प्लस टू विद्यालय का निर्माण करेंगे या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में जो अपनी बातों को रखा है, तो हम पुनः स्वयं उसकी समीक्षा कर लेंगे और अगर वास्तव में छात्र–छात्राओं की संख्या ज्यादा है और दूरी भी ज्यादा है, तो उस पर जरूर हम विचार करेंगे। कई जगहों पर हम लोगों ने पुनः विचार करके प्लस टू के विद्यालय खोले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सही पाए जाने पर उसको हम लोग नहीं खोलेंगे।

श्री रामविलास कामत : महोदय,..

अध्यक्ष : सरकार ने इतना स्पष्ट आश्वासन आपको दिया है। अब क्या बचा उसमें ?

श्री रामविलास कामत : महोदय, जब सभी पंचायतों में प्लस टू विद्यालय खोलना सरकार का निर्णय है, तो दीनापट्टी पंचायत में प्लस टू विद्यालय नहीं खुल पाया है,

उसी के बारे में जवाब में आया है कि दूसरे पंचायत के विद्यालय को बताया जा रहा है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा ही है कि इसको हम स्वयं देख लेंगे और माननीय सदस्य को भी सूचित कर देंगे कि हम लोगों ने इस पर निर्णय ले लिया है।

तारांकित प्रश्न संख्या–1137, श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या–171, अस्थावां)

(मुद्रित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1–आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा श्री राज कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आधार पर विभाग स्तर से आरोप–पत्र गठित करते हुए श्री राज कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री राज कुमार द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा से मंतव्य की मांग कर आरोप/लांछन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 237/सा0, दिनांक 9 फरवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, नालंदा श्रीमती कविता कुमारी के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई के क्रम में उप–विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष जिला निगरानी समिति/धावादल, नालंदा के द्वारा पत्रांक–763/गो0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है और अधिकारियों ने उत्तर भ्रामक दिया है। महोदय, नालंदा जिला में तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल में बेंच–डेस्क भेजने के क्रम में भारी पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की है और जिला निगरानी समिति के द्वारा और धावा दल के द्वारा भी जांच की गयी, जिसमें कि दोष सिद्ध हुआ है। महोदय, तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं। महोदय, फिर भी उन्हें रिवार्ड के तौर पर आर0डी0डी0ई0, पटना बना दिया गया। महोदय, तो क्या ऐसे पदाधिकारी को निलंबित करते हुए इन पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, जो पूर्व में कनीय पदाधिकारियों के द्वारा समीक्षा की गई, अलग से भी माननीय सदस्य ने हमको इस बारे में जानकारी दी है। वह निश्चिंत रहें, हम लोग

मुख्यालय स्तर पर पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और अगर कहीं भी गलती या गबन का मामला आएगा, तो किसी भी दोषी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसके लिए सुनिश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, एकदम स्पष्ट है। जिला के वरीय पदाधिकारी, डीएम, उप विकास आयुक्त, लोगों ने जांच की है और ये दोषी पाए गए हैं। महोदय, बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी है और फिर भी इन्हें आर0डी0डी0ई0 बना दिया गया। महोदय, तो ऐसे मामले में तत्काल उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई या वरिष्ठ स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी जांच करवाते हुए, इनके द्वारा जो वसूली की गई है, बेंच उपस्कर में, नाजायज वसूली की गई है, उसको सरकार वसूल करना चाहती है ? ये हम स्पष्ट जानना चाहते हैं।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इसे डायरेक्टर स्तर पर, मुख्यालय से ही पुनः समीक्षा जरूर करा लेंगे और वैसे भी जो डी0ई0ओ0 पूर्व में दोषी पाए गए हैं इस तरह के मामले में, उन पर हम लोगों ने एफ0आई0आर0 और सख्त कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाएगा और यह सत्र जैसे ही खत्म होता है, तो ए0सी0एस0 के स्तर पर इसकी हम समीक्षा करवाकर कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, हो गयी है बात। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल।

(व्यवधान)

सरकार ने कहा है कि कार्रवाई की जायेगी। विश्वास कीजिए। प्लीज, बैठ जाइये। सरकार कार्रवाई की बात कर रही है।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, जब दोष सिद्ध हो गया है, दोषी पाए गए हैं और कहिए कि एक लाख, दो लाख का नहीं, दस–दस करोड़ के गबन का मामला है । महोदय, फिर भी इन्हें आर0डी0डी0ई0, पटना बना दिया गया। तो तत्काल इन्हें उस पद से हटाते हुए सरकार जांच कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है कि सत्र के बाद सारे मामले की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल।

(व्यवधान)

बैठ जाइये। राज्य स्तर पदाधिकारी से, निदेशक के माध्यम से जांच करायेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1138, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या–153, गोपालपुर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1139, श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या–69, कोढ़ा (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक।

2– आंशिक स्वीकारात्मक।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में आई.सी.डी.एस. मुख्यालय स्तर से आँगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक के बैंक खाते में रू0 400/– प्रति बच्चा DBT के माध्यम से भुगतान किया गया है। मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त बच्चों की पोशाक राशि से वित्तीय वर्ष 2025–26 में जीविका द्वारा निर्मित दो सेट पोशाक आँगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसका विधिवत उद्घाटन दिनांक 18.01.2026 को किया गया है। जल्द ही सभी बच्चों को पोशाक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3–अस्वीकारात्मक।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 से पोशाक राशि की जगह जीविका द्वारा निर्मित पोशाक मंत्रीपरिषद् से स्वीकृति के उपरान्त आँगनबाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइये।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, जवाब आया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है कि सत्र के बाद मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी से इन बातों को देकर पुनः कार्रवाई की जायेगी।

माननीय मंत्री, समाज कल्याण।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया हुआ है।

अध्यक्ष : कविता जी, पूरक पूछ लीजिए।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, जवाब मिला है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं 2020 से लेकर 2024 तक, जो राशि का भुगतान नहीं किया गया है, क्या उसका भुगतान होगा ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विभागीय स्तर पर इसका निर्णय लिया है कि जीविका दीदी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे नामांकित हैं, उनको हम लोग दो–दो सेट पोशाक देंगे और उसकी शुरूआत भी हो चुकी है और अभी जो राशि 2024–25 की है, उसको भी अभी हम सभी बच्चों को देंगे।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 2020 से लेकर 2024 तक जो भुगतान नहीं हुआ है, वह कब तक होगा ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो जवाब दिये हैं न कि 2022–23 में भी हम दिये हैं, 2023–24 में भी दिये हैं और 2024–25 की राशि हम लोग 2025–26 में दिये हैं।

टर्न–5 / संगीता / 17.02.2026

तारांकित प्रश्न सं0–1140, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर' मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1– स्वीकारात्मक ।

खंड–2– स्वीकारात्मक ।

खंड–3– स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–35, दिनांक–06.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न कारणों से प्रश्नगत भूमि पर खेल मैदान का निर्माण कराना संभव नहीं हो पाया है:–

1– प्रश्नगत भूमि खेल मैदान के उपयुक्त स्वरूप में नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर गेंहूँ एवं चना का फसल लगा हुआ है।

2– प्रश्नगत भूमि पर जल–जमाव की स्थिति तथा मिट्टी भराई की आवश्यकता है। निकटवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त मिट्टी उपलबध नहीं होने के कारण मनरेगा अकुशल मजदूरों से मिट्टी कटाई कर उक्त स्थल पर मिट्टी भराई नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि को मिट्टी ढुलाई करने की आवश्यकता होगी। विदित हो कि (VB-GRAM-G) की अनुसूची–1 पैरा 22 में यह निर्धारित है कि जहाँ तक व्यवहार्य हो कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले कार्य श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित किये जायेंगे और श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। अतः प्रश्नगत भूमि पर खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना से कराना संभव नहीं है।

विभागीय पत्रांक–110, दिनांक–22.01.2026 के द्वारा निर्गत नया दिशा–निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत देव में 50 डिसमिल से एक एकड़ तक खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार की भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में ग्राम पंचायत देव में खेल मैदान की योजना को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष–2026–27 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब तो आया है । हमारा क्वेश्चन था कि विक्रमगंज में मल्टी ओपन जिम खोला जाए । सरकार का जवाब है कि विक्रमगंज में मल्टी ओपन जिम के भवन का काम चल रहा है । खिड़की लगाना है, दरवाजा लगाना है, इसके बाद स्थापित हो जाएगा । मैं इतना ही

जानना चाहता हूं कि किस जगह पर मल्टी ओपेन जिम बन रहा है ? दूसरा, इसी में है कि किस विभाग के जरिए पैसा को लोकेट किया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर' मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता जी का जो प्रश्न है यह खेल मैदान स्टेडियम बनाने का काराकाट में है और ये जिम की बात कर रहे हैं । इनका प्रश्न है कि काराकाट प्रखंड के पंचायत देव में सरकार देवभूमि ग्राम में वहां खेल मैदान के बारे में है और जो उत्तर है, उनका बाद में कोई प्रश्न होगा उसको उन्होंने बता दिया होगा महोदय ।

अध्यक्ष : यह खेल मैदान निर्माण कराने के संबंध में है ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर' मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के तहत काराकाट प्रखंड के बलदेव उच्च विद्यालय कोपा में पहले ही स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है, फिर भी सरकार खेल के विकास के लिए खेल मैदान के विकास के लिए चिन्तित है इसलिए पंचायत स्तर पर खेल का मैदान विकसित किया जाए यह योजना है, उसके लिए पहले 2 एकड़ जमीन की अनिवार्यता तय की गई थी लेकिन पंचायतों में जमीन की किल्लत है, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए उसको घटाया गया है, 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक खेल मैदान के लिए उपयुक्त जगह होगा तो उसको विकसित किया जाएगा और इस उद्देश्य से विभागीय पत्रांक–110, दिनांक–22.01.2026 के द्वारा निर्गत नया दिशा–निर्देश के आलोक में ग्राम–पंचायत देव में 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है । इस प्रकार की भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में ग्राम पंचायत देव में खेल मैदान की योजना को ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कर खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : श्री मनोज यादव, श्री मनोज यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1141, श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या–163, बेलहर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1142, श्री जयन्त राज (क्षेत्र संख्या–159, अमरपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि भदरिया में चांदन नदी के किनारे प्राप्त हुए पुरातात्विक स्थल/अवशेष को ''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976'' के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत

अधिसूचना संख्या– 257, दिनांक 12.08.2021 द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 1,10,000/– (एक लाख दस हजार रुपये) मात्र अनुरक्षण मद में दिया गया।

पुनः इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राक्कलन प्राप्त कर उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

श्री जयन्त राज : महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर मिला है न ?

श्री जयन्त राज : उत्तर मिला है सर ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री जयन्त राज : माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूरक है । माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2020 में वहां पर गए थे भदरिया पुरातात्विक स्थल पर और उसके बाद उसको संरक्षित किया गया गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और उस क्षेत्र में, चूंकि अभी तक 1 लाख 10 हजार रुपये की राशि उत्तर में आया है कि 1 लाख 10 हजार रुपये की राशि दी गई है, 1 लाख 10 हजार की राशि पिछले 4 साल में अगर दिया गया है तो कैसे उस पुरातात्विक स्थल का विकास होगा, माननीय मंत्री जी बताएं और ये बोल रहे हैं कि इस बार नहीं हैं तो कितना राशि देना चाहते हैं मंत्री जी बताएं, चूंकि मुख्यमंत्री जी भी जाकर वहां पर देखे थे, सारे अधिकारी जाकर वहां पर देखे थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 1,10,000/– (एक लाख दस हजार रुपये) मात्र अनुरक्षण मद में दिया गया। पुनः इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राक्कलन प्राप्त कर उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025–26 में प्राक्कलन प्राप्त करके हम वहां काम करायेंगे ।

अध्यक्ष : श्री कुंदन कुमार ।

श्री जयन्त राज : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : प्राक्कलन बन जाएगा तो हो जाएगा ।

श्री जयन्त राज : इस हिसाब से 20 हजार रुपया पर साल के हिसाब से राशि मिला है...

अध्यक्ष : अब तो प्राक्क्लन बनाया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष में ।

श्री जयन्त राज : अगर प्राक्कलन बनाकर...

अध्यक्ष : उसमें आप सहयोग कीजिए, प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है ।

श्री जयन्त राज : कब तक टीम बनाकर भेजेंगे माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 में इसको पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लिया ही गया है, वर्ष 2020 में कह रहे हैं और वर्ष 2021 में लिया गया । उसके बाद 1 लाख 10 हजार रुपये की राशि वहां गई है और वह कम

पड़ रहा है तो फिर हम प्राक्कलन बनवा रहे हैं । आगे जो लगेगा वह हम खर्च करेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : श्री कुंदन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–1143, श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या–146, बेगूसराय)

(मुद्रित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1– उत्तर अस्वीकारात्मक है।

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–596, दिनांक 04.02.2026 के आलोक में वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिले के बसहा स्थान अवस्थित आधुनिक मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित अधिष्ठापित है। इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ परजन सामान्य स्तर से पुजारी भी नियुक्त है।

खंड–2–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय का पत्रांक–26, दिनांक 08.03.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वीरपुर कालीस्थान एवं बसहा स्थान की मंदिर करीब 30 वर्ष पुरानी है। ध्यातव्य है कि 'बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्वस्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976' के अन्तर्गत किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को कम से कम 100 वर्ष से विद्यमान होने पर अधिसूचित किया जाता है।

खंड–3– उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में काली स्थान एवं बसहा स्थान को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में और इसमें पदाधिकारियों ने गलत जवाब दे दिया है और जवाब यह आया है, चूंकि यह मंदिर 30 साल पुराना ही है इसलिए इसको घोषित नहीं किया गया है । महोदय, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है दोनों स्थल के सामने, ये नौवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच का दोनों मंदिर है, पाल वंश के समय का मंदिर है और साथ ही साथ यह ए0एस0आई0, आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2004 में आर0जी0डी0 कॉलेज के माध्यम से वहां सर्वे कराया था, उसमें भी यही पाया गया कि नौवीं और बारहवीं शताब्दी का यह मंदिर है । तीसरा, पिछली सरकार में इसी सदन में मेरे ही प्रश्न में जवाब दिया था और उन्होंने ए0एस0आई0 को कहा था कि इसको आप लीजिए, संरक्षित करिए और इसको विकसित करिए । ये सारे जवाब हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको दे देता हूं महोदय, और ये फोटो भी है उसके बाद ये कह रहे हैं कि 30 साल पुराना है । महोदय, मेरा 2 पूरक है कि क्या ये जो तथ्य मैंने रखे हैं इसके आलोक में सरकार और मंत्री जी इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, राज्य संरक्षित धरोहर बनाना चाहते हैं ? साथ

ही साथ जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है, उस पर ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न है कला संस्कृति का, लेकिन धोखे से पर्यटन विभाग अंकित हो गया है इसमें । विधान सभा की कार्यावली में पर्यटन विभाग अंकित हो गया है । यह कला संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित करने के लिए इनका प्रश्न है जबकि वहां से जिला पदाधिकारी का जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनका स्पष्ट मंतव्य है कि यह मंदिर केवल 30 वर्ष पुराना होने की पुष्टि है, परन्तु उसके अंदर जो मूर्ति है, वह पुराना है तो 30 वर्ष जिस मंदिर का हुआ है केवल उसको 1976 के कला अधिनियम के तहत जो हम संरक्षित करते हैं, उसमें आने का प्रावधान नहीं है । उसमें 100 वर्ष से जिन मंदिरों को अधिक हो गया है, हम उसको संरक्षित करते हैं ।

अध्यक्ष : कुंदन जी, जो कागज की चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कृपया माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, समीक्षा करके देख लेंगे कि क्या इसमें करना है।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, मेरा पूरक है । मैं लगातार पिछले 5 साल से इस सदन में मुद्दा को उठा रहा हूं और अब ये कह रहे हैं धोखा हो गया है, यहां पर सवाल आ गया है इस सदन में और जवाब भी जो दिया है गलत दिया है, इसपर कार्रवाई नहीं होगा, विधायक आते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो कब तक ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसके रिसर्च के पेपर में यूनिवर्सिटी में जो सबमिट किया गया है, यह कहता है कि नौवीं और बारहवीं शताब्दी में...

अध्यक्ष : आपने सारी बातों को रखा है...

श्री कुंदन कुमार : कैसे हिंदुइज्म और बौद्धइज्म को एग्जिस्ट करता था महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर समीक्षा कर लेंगे ।

श्री कुंदन कुमार : इसका सबसे प्रबल उदाहरण है और इसको ये नहीं करना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपने जिन कागजों की चर्चा की है, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी समीक्षा करके आपको बुला भी लेंगे कक्ष में । माननीय मंत्री जी इनको बुलाकर समीक्षा करके देख लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि विभाग ने गलत उत्तर दिया है । यहां टंकण की भूल से कला, संस्कृति का आज प्रश्न का दिन है और पर्यटन के नाम पर प्रिंट हो गया है ।

अध्यक्ष : इसकी पुनः समीक्षा आप कर लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : इसीलिए भ्रम हो रहा है थोड़ा सा ।

अध्यक्ष : जिसकी चर्चा हो रही है, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस विभाग के माननीय मंत्री आप ही हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की इच्छा है, वह साक्ष्य दे दें हम फिर से उसकी जांच करा लेंगे । अगर वह 100 साल पुराना निकल जाएगा तो हम उसको संरक्षित कर लेंगे ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, दोनों मंदिर के सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, नौवीं और बारहवीं शताब्दी...

अध्यक्ष : अब बात हो गई । सरकार पुनः समीक्षा करेगी, आपके कागज के आधार पर सरकार तैयार है समीक्षा करने के लिए ।

श्री कुंदन कुमार : सर, हम साक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं...

अध्यक्ष : पेपर भेज दीजिए आप । श्री भरत बिंद ।

तारांकित प्रश्न सं0–1144, श्री भरत बिंद (क्षेत्र संख्या–205, भभुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलौटा में 500 रनिंग फीट चहारदीवारी एवं +2 उच्च विद्यालय बहेरा में 5000 रनिंग फीट चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना है ।

मापी के आलोक में जिला कार्यालय के पत्रांक–52, दिनांक–20.01.2026 एवं पत्रांक–78, दिनांक–10.02.2026 द्वारा उक्त दोनों विद्यालय के चहारदीवारी के निर्माण हेतु BSEIDC, पटना को पत्र दिया गया है ।

उक्त निर्माण कार्य BSEIDC, पटना द्वारा स्वीकृति के उपरांत आठ महीने में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

श्री भरत बिंद : पूछता हूं सर ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है आपको ?

श्री भरत बिंद : उत्तर प्राप्त है सर ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें समय ज्यादा दिया गया है, समय कुछ कम करके इसको बरसात से पहले बना दिया जाए तो अच्छा होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में हमने कहा था कि आने वाले वित्तीय वर्ष में ही हमलोग इसका निर्माण करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी बात हम मानें लेकिन इसमें जो प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, इस वजह से हमने उत्तर दिया ।

अध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर ।

टर्न–6 / यानपति / 17.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–1145, श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र सं0–73, मधेपुरा)

(मुद्रित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाइगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी एवं जीवछपुर के वार्ड नं0–07 अवस्थित पोखर का जांच कराया गया जिसमें पता चला कि मदनपुर पंचायत के श्री रामजनाकरी ठाकुरबाड़ी के पास का पोखर रामजानकी ट्रस्ट की भूमि है । ट्रस्ट के द्वारा पौधारोपण हेतु आवेदन समर्पित किये जाने पर पौधारोपण कार्य किया जा सकता है । जीवछपुर के वार्ड नं0–07 में अवस्थित पोखर निजी भूमि पर है, जिस पर जमीन मालिक के द्वारा कृषि वानिकी योजनान्तर्गत पौधारोपण किया जा सकता है एवं वन विभाग, जमीन मालिक के मांगे जाने पर आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी योजना के तहत पौधों की आपूर्ति कर सकता है ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तो सुने थे, संपूर्ण बिहार में मादक द्रव्यों का प्रदूषण चल रहा है महोदय । तो यह जो है, प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा कार्य वृक्षारोपण के माध्यम से होता है । मैंने माननीय मंत्री जी से, सरकार से यह पूछा कि इस ट्रस्ट में आप वृक्षारोपण कर सकते हैं या नहीं । मैं चाहता हूं कि इस तरह के संपूर्ण ट्रस्टों से समन्वय स्थापित कर न सिर्फ मधेपुरा का, संपूर्ण बिहार में सरकार वृक्षारोपण कार्य करना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाइगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि जो मधेपुरा प्रखंड के मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी एवं जीवछपुर के वार्ड नंबर–7 में अवस्थित पोखर के वृक्षारोपण से संबंधित था जल संरक्षण के लिए, इसकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि जो मधेपुरा जिलांतर्गत मधेपुरा प्रखंड के मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, जीवछपुर के वार्ड नंबर–7 में अवस्थित पोखर का जो जमीन है वह मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी के पास का है, पोखर है, तो ट्रस्ट की भूमि है महोदय । जहां रामजानकी ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट की भूमि है तो ट्रस्ट द्वारा पौधारोपण हेतु जो आवेदन समर्पित किया जायेगा तो वहां पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है और दूसरा जो इसमें है कि जीवछपुर के वार्ड नंबर–7 में अवस्थित पोखर पर वृक्षारोपण का तो उसकी जांच कराई गई है । वह भूमि निजी है जिस पर जमीन मालिक के द्वारा कृषि बांध की योजना अंतर्गत पौधारोपण किया जा सकता है । वन विभाग जमीन मालिक के मांगे जाने पर आवश्यकतानुसार कृषि बांध की योजना के अंतर्गत पौधों की आपूर्ति करा सकता है । एक रामजानकी ट्रस्ट की जमीन

है दूसरा जमीन निजी जमीन है तो वह चाहेंगे तो वहां वृक्षारोपण का कार्य हो सकेगा महोदय ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, इस तरह के ट्रस्ट जो धार्मिक न्यास पर्षद् से संचालित हैं, चूंकि प्रदूषण व्यापक है, देश चिंतित है, मैं यह चाहता हूं सरकार से और इसी तरह की मांग है मेरी कि इस तरह के ट्रस्टों की जमीन पर जो परती जमीन है, खेती योग्य नहीं है वैसे जमीन का सर्वेक्षण मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार में कराकर के प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण का कार्य करना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाइगर', मंत्री : महोदय, यह जो सप्लिमेंट्री है, मूल प्रश्न के इतर है । इसके लिए माननीय सदस्य अलग से सवाल कर लें तो उसका उत्तर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शिद आलम ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, सरकार संवेदनशील नहीं है । वृक्षारोपण कर देंगे...

श्री संजय सिंह 'टाइगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत संवेदनशील है और माननीय सदस्य भी संवेदनशील हैं । इसपर विचार किया जायेगा, सकारात्मक विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य के पास बहुत भूमि है महोदय, कुछ भूमि अगर उपलब्ध करवायें तो उसमें भी हमलोग वृक्षारोपण करा देंगे महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1146, मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र सं0–50, जोकीहाट)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अवर निबंधन कार्यालय, जोकीहाट के कार्यालय भवन, आवास एवं निबंधनार्थी जनता हेतु प्रतीक्षालय/शौचालय/जेनेरेटर कक्ष आदि के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक–525, दिनांक–6 जून, 2025 द्वारा निर्गत है ।

प्रस्तावित भूमि मौजा सिसौना, खाता सं0–578, खेसरा सं0–1459 एवं 1460 कुल रकबा 50 डी0 भूमि पर विभागीय स्तर से पत्रांक–4690, दिनांक–4 अगस्त, 2025 क्षरा स्वीकृति प्रदान की गयी है । तदोपरांत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया द्वारा वर्णित भूमि का निरीक्षण किया गया एवं अंचल अमीन द्वारा प्रस्तावित भूमि की नापी की गई । अवर निबंधन कार्यालय, जोकीहाट के पत्रांक–24, दिनांक–16 जनवरी, 2026 के आलोक में अंचलाधिकारी, जोकीहाट द्वारा पत्रांक–109, दिनांक–24 जनवरी, 2026 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया से साईट प्लान बनाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है चूंकि मेरा प्रश्न था जोकीहाट में जो अवर निबंधन कार्यालय किराये के भवन में संचालित है

और सरकार के पास जमीन भी है सब चीज है वह कब तक बनाने की सरकार मंशा रखती है । तो उस संबंध में एक यह है कि दिनांक 04.08. 2025 को ही सरकार से स्वीकृति मिल गयी भवन बनाने की, साईकिल स्टैंड बनाने की, प्रतीक्षालय बनाने की, शौचालय बनाने की, जनरेटर शेड बनाने की लेकिन वहां पर जो सी0ओ0 द्वारा चिट्ठी दी गई है, अभी हाल में पांच महीने के बाद 24.1.2026 से तब उन्होंने बी0सी0डी0 को, भवन निर्माण विभाग को प्राक्कलन तैयार करने के लिए भेजा गया है । इतनी लापरवाही कि पांच महीने के बाद बिहार सरकार की स्वीकृति प्रदान के बाद भी, पांच महीने के विलंब से बना है तो सरकार कब तक बनाना चाहती है, यही जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को पता है कि बीच में चुनाव भी हो गया था, जल्द ही इसका निर्माण करवाया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1147, श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र सं0–02, रामनगर)

(मुद्रित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आलोक में वर्ष 2022 में ही लौरिया प्रखण्ड में नया निबंधन कार्यालय सृजित एवं संचालित है। जिसका लाभ रामनगर प्रखण्ड के आम लोगों को भी पर्याप्त मिल रहा है।

3. विभागीय पत्रांक–1102, दिनांक–9 मई, 2013 के माध्यम से नया निबंधन कार्यालय खोलने हेतु आवश्यक मापदण्डों का निर्धारण किया गया है।

नया निबंधन कार्यालय खोलने के लिए विभागीय पत्रांक–1102, दिनांक–9 मई, 2013 में उल्लेखित निम्न मापदण्डों का पर्याप्त होना आवश्यक हैः–

(क) सभी अनुमंडल मुख्यालय में अवर निबंधन खोले जायेंगे यदि वहाँ न्यूनतम 8000 (आठ हजार) दस्तावेज का निबंधन संभावित हो। लेकिन अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में निबंधन कार्यालय है अथवा मुख्यालय से 15 कि0मी0 की दूरी किसी प्रखंड मुख्यालय में पूर्व से अवर निबंधन कार्यालय खुला हुआ है अथवा अनुमंडल मुख्यालय में अवर निबंधन कार्यालय है तो ऐसे स्थान पर नया अवर निबंधन कार्यालय नहीं खोला जायेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त प्रखंड मुख्यालय में नया अवर निबंधन कार्यालय खोला जाना है तो प्रस्तावित निबंधन कार्यालय से 15 कि0मी0 की दूरी में दूसरा निबंधन कार्यालय नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन गत तीन वर्ष के औसत दस्तावेज पर संभावित हो।

(घ) प्रस्तावित कार्यालय का वार्षिक राजस्व रू0 04 (चार) करोड़ संभावित हो।

विभागीय पत्रांक–457, दिनांक–24 जनवरी, 2022 द्वारा नये निबंधन कार्यालय के खोलने हेतु प्रस्तावित निबंधन कार्यालय सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने पर भी कुछ मापदण्डो के आधार पर जनसुविधा हेतु नया निबंधन कार्यालय खोला जा सकता है।

रामनगर प्रखण्ड में विगत 03 वर्षों में औसत 1946 दस्तावेज निबंधित हुए हैं, जिससे 3.53 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग से निर्धारित आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं करने की स्थिति में नये निबंधन कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री नंद किशोर राम : जी, उत्तर मिला है लेकिन श्रीमान् माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि मौरिया से रामनगर की दूरी 20 कि0मी0 है लेकिन गोवर्धना और गोन की दूरी 30 से 40 कि0मी0 है इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं जबकि प्रखंड मुख्यालय में निबंधन कार्यालय खोलना है तो रामनगर में निबंधन कार्यालय अगर खुल जाता है तो लोगों को राहत मिलेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य के साथ बैठकर इसपर विचार विमर्श कर लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1148, श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं0–180, बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलांतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के विधिपुर में केशव उच्च विद्यालय जो एक निजी विद्यालय है, लगभग पांच वर्षों से पूर्ण रूप से असंचालित है ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन मेरा दो पूरक प्रश्न है, एक सालिमपुर विश्वविद्यालय जो है 1949 से यह चालू है बहुत पुराना है और बहुत जर्जर स्थिति में है वहां के छात्र बाहर में बैठकर पढ़ते हैं, माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि इस विद्यालय का और सलालपुर मुशहरी विद्यालय का जितना जल्द हो इसको जीर्णोद्धार करना चाहिए, पुरानी बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है उसको तोड़कर नया कब बनायेंगे यह जानकारी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह तो एक प्राइवेट स्कूल का था जिसका हमलोगों ने उत्तर दिया और इनका नया जो इन्होंने अपनी जो मांग की है निश्चित रूप से हमलोग तो संकल्पित हैं कि सभी इस तरह के स्कूलों को और खासकर के ऐसे स्कूल जो पुराने हैं उसकी प्राथमिकता के तौर हमलोगों ने सूची भी बनाई है अगले वित्तीय वर्ष में माननीय सदस्य दे देंगे अलग से और उसको हमलोग प्राथमिकता पर देखेंगें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री देवेश कांत सिंह ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, कब तक हो जायेगा ।

अध्यक्ष : कहा तो अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अगले वित्तीय वर्ष में, हमलोगों ने सूची भी बनाई है ।

अध्यक्ष : साफ बताया गया है अगले वित्तीय वर्ष में ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1149, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं0–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत प्राथमिक और उत्क्रमित विद्यालयों में 5+3+3+4 संरचना, फाउंडेशन साक्षरता और तकनीकी एकीकरण जैसे व्यापक कदम उठाये गये हैं । वर्ष 2026–27 सत्र से कक्षा–6 से ही व्यावसायिक शिक्षा (ए0आई0, कंप्यूटर, हेल्थकेयर) शुरू करने और शिक्षकों के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें और डिजिटल कौशल पर जोर दिया जा रहा है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय उत्क्रमित विद्यालयों में कार्यालय सहायक और परिचारी का कोई प्रावधान नहीं है । प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य की अधिकता नहीं होती है, कर्मी यथा विद्यालय एवं परिचारी का पद सृजित नहीं है । केंद्र प्रायोजित लिपिक योजना तथा पी0एम0 पोषण योजना एवं समग्र शिक्षा के संचालन में सहयोग हेतु प्रखंड साधन सेवी/लेखा सहायक की व्यवस्था है ।

3. इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है । मेरा दो पूरक है इन्होंने कहा और जवाब में भी लिखा है व्यवसायिक शिक्षा (ए0आई0, कंप्यूटर, हेल्थकेयर) के शिक्षकों के लिए अनिवार्य मासिक बैठक कराई जा रही है और उसके माध्यम से लेकिन मेरा कहना यह है कि शिक्षकों को

बहाल किया गया है शिक्षा देने के लिए और हमारी मांग है कार्यालय सहायक और परिचारी बहाल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम नौकरियां देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे और बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र भी है कि शिक्षकों की बहालियां हुई हैं, डॉक्टरों की बहालियां, ए0एन0एम0, जे0एन0एम0 सब हुई हैं लेकिन वैसे स्कूल जो प्राइमरी या मिडिल हैं उसमें सरकार का विचार जवाब में है कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम कार्यालय सहायक या परिचारी लें तो क्या सरकार उन स्कूलों को कार्यालय सहायकों की जगह मास्टरों से काम करा रही है तो करा रही है तो इन्होंने कहा कि हम इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं । डाटा एंट्री या अन्यान्य चीज जितने योजना हैं वहां का सब करा रहे हैं और परिचारी का काम किससे करवायेंगे, वह किस शिक्षक से पानी पिलवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य के पूर्व के एक प्रश्न में कहा था कि इसकी हम पुनः समीक्षा करेंगे । बात सही है कि सभी जगह परिचारियों की आवश्यकता है लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ही हम करा पायेंगे । हमलोगों की भी एक सीमा है कि अभी जो टीचर्स का हमलोगों को करना है उसके बाद साथ ही साथ हमलोगों ने अभी एक अधियाचना स्पेशल टीचर्स जो दिव्यांग छात्र/छात्राओं को पढ़ायेंगे वह हमारी प्राथमिकता है । ऐसी बात नहीं है कि हमलोग कराना नहीं चाहते हैं या करायेंगे नहीं लेकिन यह प्राथमिकता के तौर पर उसके बाद तो बहुत शिकायतें आई हैं इस वजह से हमलोग नहीं कर रहे थे ।

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो जवाब दिया था वह उच्चतर और माध्यमिक विद्यालय का मामला था, वहां तो पद सृजित है लेकिन यहां इनका जवाब है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो क्या सरकार इसमें प्रावधान करके मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को भी कार्यालय सहायक या परिचारी या नाइट गार्ड यह जो व्यवस्था है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इससे कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कई नौजवान को समाहित किया जायेगा तो मेरा आग्रह है, सरकार इस पर विचार करे और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अनुपालन भी होगा । तो शिक्षा विभाग का मामला है । माननीय मंत्री जी इसपर क्या करेंगे । उन्होंने जो कहा वहां तो व्यवस्था है । उसकी बहाली बाकी है, वह आयोग से होगा, चाहे कर्मचारी आयोग से, मेरा कहना है मिडिल स्कूल, क्लास 1 से क्लास 8 इस दोनों के बीच में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इनका कहना है नहीं है तो वो व्यवस्था हो सकती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न–7 / अभिनीत / 17.02.2026

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जब अनुकंपा की नियुक्तियों की बातें आयीं तो वह पद हमें सृजित कराने पड़े । जो परिचारी का या क्लर्क का पद था वह हमें सृजित कराने पड़े तब जाकर ये नियुक्तियां हुईं, तो हमने इसी संदर्भ में कहा है न कि मिडिल स्कूल और हाईस्कूल के संदर्भ में कि इसकी हमलोग समीक्षा करा लेंगे और आवश्यकता अनुसार जो हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जो अलॉटमेंट है, सारी चीजों को दिखाकर के ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़ी है तो हमलोगों ने पदों का सृजन कराया है । हमने अनुकंपा वाली नियुक्तियों के बारे में माननीय मुख्मंत्रीजी से मिलकर के फिर कैबिनेट से कराया था साढ़े पांच हजार पद, तो यहां भी हमलोग उस पर पुनर्विचार करेंगे, आवश्यकता पड़ी जैसा वे कह रहे हैं तो निश्चित उसको हमलोग फेवरेबल तरीके से देखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव था..

अध्यक्ष : समय नहीं है । बहुत क्लीयर जवाब आया है । देवेश बाबू, बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1150, श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र सं0–25, परिहार)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, 1–स्वीकारात्मक ।

2– आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति है कि श्रीमती पूनम कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी के पद पर दिनांक– 7 जुलाई, 2023 से पदस्थापित रहकर दिनांक 30 नवम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त हुई हैं ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) संवर्ग के कुल स्वीकृत 568 पदों के विरूद्ध वर्तमान में मात्र 122 पदाधिकारी कार्यरत हैं ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–277, दिनांक–21 फरवरी, 2025 द्वारा प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त (वित्तीय प्रभार सहित) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध किया गया है । उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–3592, दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 के आलोक में श्री आनंद गौरव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाह्न से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत हैं ।

राज्य में संचालित प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों के सतत निरीक्षण, अनुश्रवण एवं शिक्षा के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विद्यालयों के स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए औसतन लगभग 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए कुल 935 पदों का सृजन किया गया है । उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, माननीय मंत्रीजी उत्तर दिए हैं । उत्तर प्राप्त है । मेरा प्रश्न यह है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में 27 पंचायत हैं तथा 250 से अधिक प्राथमिक, मध्य तथा उच्च विद्यालय संचालित हैं । इतने अधिक विद्यालयों में प्रभारी संचालन हेतु शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है । विभागीय पदाधिकारी के पदस्थापित रहने से कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन होता है ।

अतः 250 से अधिक विद्यालयों के प्रभारी संचालन हेतु माननीय मंत्रीजी शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी को कबतक पदस्थापित करेंगे, समय–सीमा बता दें ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन सबका अनुश्रवण सही तरीके से हो और कमियों को देखते हुए ही अंत में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुश्रवण, शिक्षा के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विद्यालयों के स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए औसतन लगभग 10 पंचायतों पर एक–एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए कुल 935 पदों का सृजन किया गया है । उन पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । माननीय सदस्या ने जो अपनी चिंता जाहिर की उससे विभाग अवगत है और इस बात को मानता है । इसी वजह से हमलोगों का सुपरविजन बेटर हो, इन पदों को हमने कैबिनेट से सृजित करके, माननीय मुख्यमंत्रीजी से अनुमति लेकर के और अपनी अधियाचना भी हमलोगों ने बीपीएससी को भेज दी है, तो वे जब यहां पर ज्वाइन कर लेंगे तो इस समस्या में कमी जरूर आयेगी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक....

(व्यवधान)

देंगे, मौका देंगे । बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक– 17 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री

राहुल कुमार, स0वि0स0, श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री राहुल कुमार : बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे 248 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों एवं 599 से अधिक इंटर कॉलेजों में लगभग 40 हजार से 50 हजार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं जो पिछले कई वर्षों से बिना वेतन के शैक्षणिक कार्य का संपादन कर रहे हैं । शैक्षणिक सत्र 2015–18 के बाद से राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों को देय अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक– 30.09.2025 को ज्ञापांक–2829 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था । समित को अनुदान वितरण, वेतन विसंगतियों के निराकरण और मानदेय निर्धारण पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देनी थी । महीनों बीत जाने के बाद भी समिति की अनुशंसाएं ठंडे बस्ते में है और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । अनुदान के अभाव में इन कर्मियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी और मानसिक प्रताड़ना की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है ।

अतः दिनांक– 17.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए तत्काल अनुदान देने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अत्यंत हर्ष के साथ सूचना देना चाहता हूं कि जे0ई0 मेन्स, 2026 के प्रथम चरण के परिणाम में गयाजी के शुभम कुमार ने बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है, यह अत्यंत गौरव का विषय है । उन्होंने 100 परसेंट लाकर बिहार में अव्वल आने के साथ देश भर में तीसरे स्थान पर रहे हैं । यह उनकी प्रतिभा का परिचायक है । मैं सदन की ओर से मेघावी छात्र शुभम कुमार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस मेघावी छात्र शुभम कुमार को तो बधाई देते ही हैं । साथ ही, हमलोग जो गया जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, गयाजी का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं हम उनको भी बधाई देते हैं ।

(व्यवधान)

सर्वजीत जी, हम तो गया जिला इसीलिए बोले, आप क्यों अपने को जबरदस्ती वंचित श्रेणी में बनाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । अब शून्यकाल लिए जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत खरीक प्रखंड के चोरहर पुल के नजदीक कोशी नदी के पास अवस्थित बगजान जमींदारी बांध बाढ़ के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया है ।

अतः मैं सरकार से बगजान जमींदारी बांध की मरम्मतीकरण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रजनीश कुमार ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो शिक्षा विभाग से संबंधित था, 1179 नम्बर पर इसमें अंकित है । जो प्रश्न है, यहां सही छपा हुआ है जो मैंने पूछा है लेकिन उत्तर जो शिक्षा विभाग से आया है उसमें प्रश्न भी बदल गया है और स्वाभाविक है उसका उत्तर भी बदल गया है । महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाने का निदेश देना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगली बार आ जायेगा ।

श्री रजनीश कुमार : जी महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रोहित पाण्डेय ।

श्री रोहित पाण्डेय : महोदय, भागलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 की शहरी जलापूर्ति योजना 2026 में भी अधूरी है । वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है जिससे जलसंकट बढ़ रहा है । आगामी भीषण गर्मी से पहले संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय कर हर घर तक नियमित स्वच्छ और शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।

श्री मुरारी पासवान : महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत पीरपैंती विधान सभा के पीरपैंती प्रखंड में नन्दलालपुर के बाराहाट तक जाने वाली लगभग 08 किलोमीटर जर्जर सड़क जो झारखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, का निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विमल राजवंशी : महोदय, रजौली प्रखंड अंतर्गत पंचायत हरदिया के जंगली क्षेत्र व विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के फर्जी कागजात तैयार कर अन्य राज्य के व्यक्तियों को लाभ दिया गया तथा वन विभाग की भूमि पर अवैध

निर्माण कराया गया । उच्च स्तरीय जांच तथा दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की सरकार से मांग करता हूं ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत अलीनगर विधान सभा के क्रमशः तीनों प्रखंड धनश्यामपुर, तारडीह एवं अलीनगर में कृषि रोड मैप के तहत किसानों को बेहतर भंडारण, विपणन और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि हाट (बाजार) की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती छोटी कुमारी : महोदय, सारण प्रमंडल में पूर्व में केवल गंगा सिंह महाविद्यालय, छपरा में ही लॉ की पढ़ाई होती थी जो कई वर्षों से बंद है । इससे विद्यार्थियों को अन्य जिलों में जाना पड़ता है ।

अतः छपरा में शीघ्र विधि शिक्षा पुनः प्रारंभ करने की मांग करती हूं ।

टर्न–8 / मुकुल / 17.02.2026

श्री राजेश कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत रेफरल अस्पताल मनीगाछी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनीगाछी में स्वीकृत पद के विरुद्ध कम चिकित्सक एवं नर्स पदस्थापित हैं । इनकी लापरवाही से रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलता है । अतः उक्त अस्पतालों में पांच विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं नर्स की पदस्थापन की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवटी विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड केवटी अंतर्गत खिरमा वार्ड सं0–01 में बच्चे लाल यादव के घर से लालो शर्मा के घर तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण रहने से सालों भर यहां जल जमाव की समस्या बनी रहती है। अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाए ।

श्री ललन राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखण्ड अन्तर्गत एन0एच0–139 दो मुहान पुल के पास बतरे नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, सरकार से दो मुहान पुल के पास बतरे नदी पर पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सांख्यिकी स्वयंसेवकों से दो साल सेवा लेने के उपरांत सेवा से वंचित कर दिया गया है । जिससे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । रोजगार सृजन लक्ष्य के तहत पूर्व से प्रशिक्षित एवं अनुभवयुक्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों के पुनर्स्थापन करने की मांग करता हूं।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखण्ड अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत का जवईनिया गांव 2025 के बाढ़ में गंगा नदी में समा गया था । आज पूरे पंचायत पर गंगा नदी से कटाव का खतरा है । अतः नदी के तट पर बोल्डर पिचिंग निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री मिथुन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा क्षेत्र के सबौर प्रखण्ड के बरारी पंचायत अंतर्गत वर्ष 1974–75 में चालू सिल्क मिल उद्योग, जो 1990 में बंद हो गया, वर्तमान में उक्त उद्योग की बंद पड़ी लगभग 11 एकड़ जमीन पर सिल्क मिल उद्योग चालू कराने हेतु मांग करता हूं ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधान सभा के नोखा में ग्राम डेरा के पास दहासील नारा में बने फॉल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इलाके के हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है । सिंचाई का एक मात्र साधन है । उक्त फॉल (बांध) का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिंघिया प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज, खोलने की अधिसूचना जारी हुई है । अतः के0जी0 एकेडमी प्लस–2 सिंघिया में डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने की मांग करता हूं ।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के चेरौत प्रखंड के अन्तर्गत प्लस–2 उच्च विद्यालय, अमनपुर में करीब 1350 छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक कार्य हेतु दो मंजिला भवन निर्माण कराने हेतु मांग करता हूं ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर स्थित मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में स्वीकृत 31 पदों में से केवल 3 कार्यरत हैं तथा 28 पद रिक्त हैं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं । शीघ्र चिकित्सक नर्स एवं कर्मियों की नियुक्ति कर अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ।

श्री सुजीत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत मधुबनी–रामपट्टी भाया राटी रोड पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं । विगत तीन दिनों में दो दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई है । यह मार्ग अत्यंत दुर्घटनाप्रवण बन चुका है । जनहित में बीच सड़क पर डिवाइडर निर्माण हेतु सरकार शीघ्र कार्रवाई करे ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला पलासी प्रखण्ड ग्राम पंचायत पेचैली अंतर्गत मैना बैंक से श्यामपुर जानेवाली प्रधानमंत्री सड़क में मुसहराघाट में पुल नहीं है, उक्त छोटी नदी के दोनों तरफ प्रधानमंत्री सड़क का सम्पर्क टूटा हुआ है, यह सड़क दो पंचायतों को जोड़ती है । अतः उक्त पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नवादा जिला से 22 कि0मी0 दूर रूपौ में मां चमुंडा शक्तिपीठ मंदिर अवस्थित है । पूरे भारत में शक्तिपीठ में 45वां स्थान है । यहां शुंभ–निशुंभ राक्षस का देवी के द्वारा वध किया गया था । जिसका आज भी एक अंश शक्तिपीठ के रूप में पूजा होती है । यहां अगल–बगल जिलों से लाखों श्रद्धालु रोज पूजा करने आते हैं । अतः मांग

करती हूं कि रूपौ में मां चामुंडा मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के नुआंव प्रखंड में जायसवाल प्लस–2 उच्च विद्यालय नुआंव की जमीन को स्व0 रामदास साह द्वारा दान में 8 एकड़ जमीन (भवन सहित) दी गयी है । इस कारण उक्त विद्यालय का नाम रामदास साह उच्च प्लस–2 विद्यालय नुआंव कराने तथा उक्त विद्यालय में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की सदन से मांग करता हूं ।

श्री सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के बाढ़ नगरपरिषद् के वार्ड नं0–8 स्थित कबीरपंथी मठ की भूमि पर पार्क के निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक अनुरोध बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में लंबित है । अतः पार्क निर्माण हेतु भूमि संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, रक्सौल में 1946 एवं 1954 के निबंधित केवाला और दशकों पुरानी जमाबंदी वाली पुश्तैनी रैयती भूमि को प्रशासन खास महल बताकर नोटिस दे रहा है । इन रैयतों को अतिक्रमणकारी की श्रेणी से मुक्त कर उचित राहत प्रदान की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती सोनम रानी जी, आपने शून्यकाल की सूचना 84 शब्द में दिया है, जबकि 50 शब्द में देना था । आप भविष्य में इसका ख्याल रखियेगा और 50 शब्द में पढ़ दीजिए ।

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अन्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखण्ड के ग्राम–पंचायत गुड़िया के मौजा बेलापट्टी के बेलापट्टी उ0म0 बेलापट्टी में स्वयं का 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धुर जमीन है । जिसका खाता नं0–188, खेसरा–578 कुल रकबा–1 बीघा 02 कट्ठा 18 धुर है । जोकि जमाबंदी नं0–527 मौजा बैलापट्टी थाना–जदिया–त्रिवेणीगंज में दर्ज है । जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है । जिला प्रशासन अनुमण्डल+अंचल प्रशासन क्यों नहीं अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहती है । अतः सरकार से उक्त विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करती हूं ।

श्री पुरन लाल टुडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के रेफरल अस्पताल बौंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों जी0एन0एम0, स्टाफनर्स, फर्मासिस्ट एवं लैब तकनीशियन की भारी कमी है । 23 जी0एन0एम0 के स्थान पर 4 कार्यरत हैं । एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है । सरकार से चिकित्सकों, कर्मियों की पदस्थापना एवं एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की मांग करता हूं ।

श्री उदय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी पटना के गांधी मैदान या किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर सामाजिक न्याय के पुरोधा जन–जन के नायक

पद्मभूषण स्व0 श्री रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

टर्न–09 / सुरज / 17.02.2026

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड पकरीबरावां स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमौल पंचायत–धमौल, ढ़ोढ़ा, बेलखुण्डा, गुलनी, जुरी की 60000 आबादी के बीच में है । केन्द्र का भवन जर्जर है एवं चिकित्सा कार्य बंद है।

अतः उक्त केन्द्र का भवन निर्माण एवं चिकित्सा कार्य शुरू करवाने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी, अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री राजू तिवारी, विनय कुमार चौधरी एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग / पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों से पंचायती राज एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री से जुड़ा हुआ है ।

राज्य में पारंपरिक दाह–संस्कार हेतु लकड़ियों की बढ़ती कमी, बढ़ती लागत तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गयी है । वर्तमान समय में बिहार के अधिकांश प्रखंडों में विद्युत शवदाह गृह की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । जिसके कारण आम नागरिकों को दाह संस्कार के दौरान कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा वनों पर अनावश्यक दबाव एवं पर्यावरणीय प्रदूषण भी बढ़ रहा है ।

अतः राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या है जो कि मेरे विधान सभा से लेकर पूरे बिहार में है । हरी–हरी लकड़ी काटने को लोग मजबूर हैं और बहुत गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है...

अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये मंत्री जी का ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 एवं निश्चय–3 अंतर्गत सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण किया जाना है । राज्य में कुल 264 नगर निकाय हैं । पूर्व से सात निश्चय–2 के तहत 41 नगर निकाय में योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 11 नगर निकायों में योजना पूर्ण कर ली गयी है । शेष नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम के निर्माण के लिये प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–330, दिनांक– 04.02.2026 से संबंधित नगर निकायों को निर्देशित किया गया है ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं लेकिन मामला सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या है । महोदय, पंचायती राज मंत्री मौजूद हैं आपके माध्यम से, गांव में स्थिति बदत्तर है । महोदय, लकड़ी नहीं मिल रहा है और हरा–हरा पेड़ काटने के लिये लोग मजबूर हैं । उसके बावजूद भी आस्था से जुड़ा हुआ होता है, किसी का दाहसंस्कार करने में बड़ी दिक्कत हो रही है । मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा जैसे मेरे यहां अभी अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर मतलब यहां के लोग बहुत ही परेशान हैं । अब तो बिजली भी सरकार हर घर 24 घंटे पहुंचा दी, हर जगह पहुंच गया है तो मैं आग्रह कर रहा हूं और पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था कराने की योजना रखते हैं और इसको शुरू कराना चाहते हैं ?

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विद्युत शवदाह गृह की बात कर रहे हैं । माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे कि 15वीं केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि मिलती है अनुदान के रूप में, तृस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को तीनों ही स्तर पर ग्राम पंचायत को राशि मिलती है, पंचायत समिति में मिलती है और जिला परिषद में भी मिलती है । उसमें प्रावधान है, वह अपने फंड से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करवा सकते हैं ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें बतायी, यह मामला उतने पैसे में नहीं होने वाला है, इसमें फंड की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ये अपने विभाग के द्वारा सुनिश्चित कर दें और एक गाईडलाइन निकाल दें और उसमें फंड की ज्यादा आवश्यकता है । 15वीं से और 13वीं से होने वाला नहीं है और वहां के बोर्ड में वह पास भी करें । इसको सुनिश्चित कैसे कराया जाए और इसमें फंड की ज्यादा आवश्यकता है तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि एक गाईडलाइन कर दें कि गांव के क्षेत्र में भी फंड की व्यवस्था करके सुनिश्चित हो, यह विद्युत शवदाह गृह । यह मैं जानना चाहता हूं कि इस पर गाईडलाइन करना चाहते हैं ?

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, बिल्कुल आपकी जो चिंता है उससे सहमत हैं । वित्तीय उपलब्धता में इस पर विचार किया जायेगा । साथ ही साथ इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे चूंकि बात लकड़ी से शवदाह की बात कर रहे हैं, इसमें

आपकी जो सूचना है, जो प्रस्ताव है उसका हमलोग समर्थन भी करते हैं और आगे कोशिश भी रहेगी लकड़ी के माध्यम से करने का । लेकिन साथ ही साथ इसमें आपने प्रदूषण का भी जिक्र किया है । यहां पर महोदय थोड़ी सी आपत्ति है कि अगर शवदाह को हम प्रदूषण से जोड़कर देखें, प्रदूषण के रोकथाम के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं लेकिन आपका जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, वह अच्छी बात है, उससे सहमत हैं लेकिन इसको प्रदूषण से जोड़कर देखना, उससे थोड़ा असहमत हैं ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आपकी भावना से मैं समझ गया हूं । महोदय, मैंने यह कहने का...

(व्यवधान)

महोदय, मैं भावना को समझ रहा हूं, यह हमारी भी भावना है । कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको एक गाईडलाइन अपने विभाग से करें और एक फंड की व्यवस्था सुनिश्चित करके अधिकारियों को निर्देशित करें । यह करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इनका जो विषय उठा है वह बहुत आवश्यक और जरूरी भी है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है । पूरे बिहार के अंदर प्रमुख शवदाह गृह की पहचान करेगा, परंपरागत हर क्षेत्र में वह चिन्हित है और कुछ नये जगह भी है । तो वैसे शवदाह गृह की पहचान कर जिस तरह से नगर में हमलोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उसको चिन्हित करेगी ।

अध्यक्ष : विनय जी आप पूछ लीजिये ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपने तीन पूछ लिया अब और लोगों को मौका दीजिये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, कब तक होगा ?

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

श्रीमती शीला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये काम किया जा रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है...

अध्यक्ष : आपका नाम इसमें नहीं है, बैठ जाएं । बिना अनुमति के नहीं बोलें ।

श्रीमती शीला कुमारी : ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब–गुरबों को लकड़ी नहीं मिलने के कारण गोयठा से जलाना पड़ता है तो अगर बिजली से व्यवस्था हो जाए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या बैठ जाएं । विनय जी आप पूछ लीजिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि प्रस्ताव मांगा गया है । इस संदर्भ में मुझे आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा में बेनीपुर और बहेड़ी में 9 महीना, 10 महीना पहले से प्रस्ताव

आकर विभाग में रखा हुआ है । क्या मंत्री जी उसको गंभीरता से लेकर करने पर विचार रखते हैं ?

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : आपका नाम है इसमें ?

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण में आपका नाम है ? ध्यानाकर्षण में आपका दस्तखत है ?

श्री संजय कुमार सिंह : जी महोदय होगा उसमें ।

अध्यक्ष : देख लीजिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : जी । अध्यक्ष महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा में नगर परिषद है वहां पर विद्युत शवदाह गृह की कोई...

अध्यक्ष : आपका नाम ध्यानाकार्षण में है नहीं, बैठ जाइये । सरकार के संज्ञान में आ गया है । माननीय सदस्य आप बोलिये, आपका नाम है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही सारगर्भित है । माननीय मंत्री जी ने भी जवाब बहुत जिम्मेवारी पूर्वक दिया है । लेकिन बिहार में नदियों की कोई कमी नहीं है और हिंदुओं का अंतिम संस्कार नदियों के किनारे ही किया जाता है और यदि कोई नदी का घाट अगर नगर क्षेत्र में आता है तो वहां पर नगर विकास एवं आवास विभाग बनाता है और अगर कोई पंचायत में आता है तो वहां जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग की है । लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधायक लोग अपने फंड से बना दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं बक्सर के घाट पर एक शवदाह गृह बन रहा है और आज तक वह पूर्ण नहीं हुआ। अब माननीय मंत्री जी उसको देखें कि वह कब पूर्ण होगा ? उसके बाद 2020 के मई महीने में

(क्रमशः)

टर्न–10 / धिरेन्द्र / 17.02.2026

...क्रमशः....

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नमामि गंगे द्वारा हमने गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट के नारायणी रिवरफ्रंट के बगल में, हमने वहां पर विद्युत शवदाह गृह और परंपरागत शवदाह गृह दोनों एक साथ स्वीकृत कराया, महोदय, पाँच साल हो गए और अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ और बुडको के अधिकारी उसको लेकर घूम रहे हैं तो सवाल यह है कि जहाँ पर पैसा भी भारत सरकार दे रही है वह भी नहीं हो पा रहा है और बिहार सरकार, अभी माननीय मंत्री जी ने 11 जगहों का नाम लिया और बिहार के हर नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए और हर ग्राम पंचायतों में होना चाहिए, इसके लिए सरकार जब विधायकों पर है तो विधायकों का जो विकास निधि है 04 करोड़, उसमें एक जगह भी नहीं बनेगा । महोदय, इसीलिए सरकार को जब हमारी बजट 11

गुना बढ़ गयी वर्ष 2005 के बाद तो इस मामले में सरकार को बजट उपबंध करना चाहिए या तो विधायकों के द्वारा हो तो उनका बढ़ा दीजिये और नहीं तो सरकार को नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को, ये करना ही चाहिए । महोदय, इससे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा । बिहार के जितने हिन्दु हैं सब के आस्था का प्रतीक है यह एन॰डी॰ए॰ की सरकार । महोदय, इसलिए यह होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि 41 नगर निकायों में योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, 11 पूर्ण हो चुके हैं और 264 नगर निकाय जो हैं, उन निकायों को निर्देशित भी किया गया जिसका पत्रांक, दिनांक हमने बताया और हमने कहा कि इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। जो–जो स्थल ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं तो माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग ने भी बताया है और वह तो आपको अवसर मिला कि आपका फंड बढ़े या न बढ़े, आपके पास फंड है, उस फंड पर आपको अपने विवेक से, सरकार गंभीरता से विचार करेगी, सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक लाईन । अगर माननीय विधायक को करना है तो उसमें दिक्कत होती है बिजली के बिल के पेमेंट का ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार उसको देखेगी । पंचायती राज विभाग उसको देखेगा और समीक्षा करेगी ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य आवास बोर्ड...

अध्यक्ष : मनीष जी, एक मिनट । राजू तिवारी जी, सरकार सारी बातों को...

(व्यवधान)

राजू तिवारी जी, बात आ गई । सरकार सभी सुझावों पर समीक्षा करने के बाद निश्चित तौर पर अच्छी व्यवस्था बनायेगी । माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री मनीष कुमार, जनक सिंह एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना है यह भी कार्य शिथिलता से संबंधित है। गृह विभाग से और नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी सूचना को पढ़िये ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना प्रमंडल–1 के अधीन लोहियानगर कंकड़बाग, ओल्ड बाईपास मेर रोड स्थिति भू–खण्ड संख्या–G/627 पर और G/626 एवं G/627, खेसरा नं0–775 से सटे पश्चिम स्थित आवास बोर्ड के ले–आउट प्लान के अनुसार खाली भू–खंड

का बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा किसी प्रकार का आवंटन नहीं हुआ है, इसके बावजूद आवास बोर्ड के विभागीय कर्मियों एवं भू–माफियाओं की मिली भगत से श्री अमित डालमिया नामक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भू–खण्ड पर अतिक्रमण कर मकान का अवैध निर्माण कार्य कराया गया है । सरकारी भू–खण्ड पर अवैध निर्माण होना, विभागीय संलिप्तता, विभागीय कार्य शिथिलता में लापरवाही पर भी सवाल खड़ा करता है ।

अतएव उपरोक्त भूमि पर हुए अवैध मकान निर्माण को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने एवं संबंधित भूमि को आवास बोर्ड के कब्जे में लेने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड लोहिया नगर आवासीय कॉलनी में अवस्थित भू–खंड संख्या–जी/627 से संबंधित मौजा–पृथ्वीपुर, खेसरा संख्या–775, राज्य सरकार की गजट संख्या–2635, दिनांक–27.03.1975 के द्वारा बोर्ड हेतु अंश अर्जित है तथा उक्त भू–खंड का आवंटन नहीं किया गया है । लोहियानगर पटना स्थित भू–खंड संख्या–जी/627 तथा भू–खंड संख्या–जी/626 के सटे पश्चिम आवास बोर्ड की खाली भू–खंड का स्थल निरीक्षणोपरांत पाया गया है। माननीय सदस्य ने नाम डाला था, उन्होंने लिखा था कि भू–माफियाओं की मिली भगत से श्री अमित डालमिया नाम व्यक्ति द्वारा, जिसको माननीय सदस्य नहीं पढ़ें, महोदय, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्री अमित डालमिया द्वारा इसी भू–खंड संख्या–जी/626, इसके सटे पश्चिमी आवास बोर्ड के खाली भू–खंड पर अवैध निर्माण किया गया है । उक्त भू–खंड से अवैध निर्माण हटाने हेतु आवास बोर्ड द्वारा दिनांक–25.03.2025 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अमित डालमिया एवं अन्य द्वारा वाद संख्या–6472/2025 दायर किया गया है जिसमें दिनांक–22.04.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बिहार राज्य आवास बोर्ड के दिनांक–25.03.2025 को पारित आदेश पर रोक लगा दी गयी है । महोदय, सरकार इस संबंध में वैधिक प्रावधानों के तहत समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करेगी ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्लीयर जवाब है । कोर्ट में मामला लंबित है, वेट कीजिये ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि विभाग के संज्ञान में मामला है और यह अभी न्यायालय के अधीन हो गया है लेकिन महोदय, मैं दो–चार बिन्दुवार बात को बताना चाहूँगा कि विभाग को इस बात की जानकारी सन् 2022 में, वर्ष 2022 में यह मामला आया और उसके बाद विभाग ने कार्रवाई भी किया, वर्ष 2023 में इसे रद्द करने के लिए दाखिल

खारिज जो अवैध कर लिया गया था, उसको खारिज करने के लिए विभाग ने पहल भी किया, माननीय मंत्री जी का ही विभाग है महोदय, जिसमें कि दाखिल खारिज से संबंधित मामला भी है । वर्ष 2023 से अभी तक वह मामला रद्द नहीं हो पाया है, एक तो यह मामला लंबित है । दूसरी बात कि विभाग के संज्ञान में यह था कि अवैध निर्माण कराया जा रहा है, किया नहीं गया, कराया जा रहा है और इसके बावजूद ये करा दिया गया । महोदय, इन तीन वर्षों की अवधि में विभाग ने क्या किया ? विभाग ने थानाध्यक्ष को सिर्फ एक चिट्ठी लिख दिया कि इसमें रोक का काम किया जाय, यह अवैध, बार–बार विभाग के द्वारा जो चिट्ठी निकल रहा है, उसमें इस बात का जिक्र है कि अवैध निर्माण कराया जा रहा है लेकिन महोदय, प्रश्न यह है कि यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है, उस अवधि में विभाग के द्वारा रोका क्यों नहीं गया ? इस बात को मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता उचित है कि जिस अवधि में इस तरह के गलत काम हो रहे थे तो उस अवधि में जो–जो पदाधिकारी या सक्षम जिनकी जिम्मेवारी थी उस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी और मैं जानकारी दे दूं कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के संदर्भ में सक्षम न्यायालय एवं लंबित मामलों के संदर्भ में, महोदय, जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मुझे मिला, हमारे प्रधान सचिव श्री सी॰ के॰ अनिल जी के द्वारा हमने एक पत्र जारी करवाया है जिसमें स्पष्ट तौर पर, हमने उसमें क्लीयर करवाया है कि कोई भी, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) में अंकित सक्षम न्यायालय से अभिप्रेरित दीवानी व्यावहार न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है । दाखिल खारिज अथवा अन्य राजस्व संबंधित मामले हेतु राजस्व न्यायालय डी॰सी॰एल॰आर॰, ए॰डी॰एम॰, कलेक्टर, कमिश्नर कोर्ट विधि द्वारा अधिकृत ज्यूडिशियल गजटेड न्यायालय भूमि न्यायाधिकरण बी॰एल॰टी॰वी॰, सक्षम न्यायालय समझे जायेंगे । महोदय, लंबित का अभिप्रेत, स्थगन, यथास्थिति, सक्षम न्यायालय में लंबित का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका–3 एवं 3 (ख) में उल्लेखित न्यायिक, अर्ध–न्यायिक, प्राधिकार न्यायाधिकरण के सक्षम विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा । केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन, महोदय, बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जायेगा, यह हम विभाग से ऑर्डर जारी करवाये हैं कि माननीय न्यायालय में चला गया इसके नाम पर कि उनको लाभ मिले, यह कतई नहीं होगा । उपरोक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन अथवा अंतरिम आदेश, अंतरिम ऑर्डर प्रभावी हो तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यह क्लीयरकट, जहां किसी सक्षम न्यायालय

द्वारा स्पष्ट स्थगनादेश पारित नहीं किया गया, वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेगा, महोदय, क्योंकि इसके नाम पर लंबित और विवादित मामले का लाभ जो भू–माफिया उठाते हैं, उनको उठाने नहीं देंगे । महोदय, सक्षम न्यायालय में दायर वाद के अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से अधिस्वीकारात्मक एडमिशन अंकित नहीं होगा, लंबित नहीं माना जायेगा ।

....क्रमशः....

टर्न–11 / अंजली / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, विगत वर्षों से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में देख रहे हैं कि कुछ लोग योजनाबद्ध ढंग से, महोदय, मैं कृषि मंत्री के रूप में जिस समय था, तो कृषि की जमीन लोग ऑर्डर करवाकर उसका दाखिल खारिज करके बेचने के लिए, उसको भी हमने अपील करवाया और हमने साफ शब्दों में कहा कि भू–माफिया या गलत प्रवृत्ति के लोग गरीब, निःसहाय, कमजोर व्यक्ति या सरकारी भूमि को गलत तरीके से कागज बनाकर या बलात कब्जा कर लेते हैं तथा स्वत्ववाद टाइटिल का मामला बनाकर न्यायालय में चले जाते हैं, जिससे मामला वर्षों–वर्ष लंबित रहता है तथा लोग परेशान होते हैं । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, मामले में हमने उसे रोकने की कार्रवाई पर डिटेल बताया और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि फर्जी मामले की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार मुख्य सचिव के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर नियमसंगत त्वरित कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है ।

श्री मनीष कुमार : महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रत्नेश कुमार ।

(व्यवधान)

श्री मनीष कुमार : महोदय, पूरा आप घूमा दिए । महोदय, यह मामला नगर विकास से है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नो–नो, उन्होंने कहा है कि न्यायालय में...

(व्यवधान)

श्री मनीष कुमार : महोदय, सरकार प्रतिबद्ध है । महोदय, सरकार का निर्देश हो कि उस पर अंकुश लगाया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सारी बातें स्पष्ट की हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हमने स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई करेंगे । यहां बचाव का कहीं जगह नहीं है ।

अध्यक्ष : कार्रवाई होगी । श्री रत्नेश कुमार जी, अपनी सूचना को पढ़ें । पढ़िए ।

सर्वश्री रत्नेश कुमार, संजीव चौरसिया एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रत्नेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अपने अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने अल्पसंख्यक सिख को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था और इसके बावजूद आज तक सिख समाज, जैन, पारसी, बौद्ध इनको अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र...

अध्यक्ष : आप पहले सूचना पढ़ लीजिए । जो प्रस्ताव दिए हैं, पहले उसको पढ़ दीजिए।

श्री रत्नेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ''अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.01.2014 को पारित अधिसूचना के द्वारा सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है । इसके बावजूद बिहार में सिख समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र मुहैया नहीं कराया जाता है । साथ ही साथ, आर.टी.पी.एस. के अधीन आने वाले सुविधाओं में सिख का कोई कॉलम नहीं है, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन सहित अन्य लाभ से वंचित रहते हैं ।

अतः सिख समुदाय को भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सभी तरह के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार सिख समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री मो॰ जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : यह ट्रांसफर है, इसका उत्तर बाद में होगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम जवाब दे देते हैं । महोदय, इसमें सिख समुदाय के लोगों के लिए अल्पसंख्यक होने के प्रमाणपत्र निर्गत करने से संबंधित यह ध्यानाकर्षण सूचना है । यह सही बात है कि ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है और वह नहीं है तो इसलिए नहीं है कि यहां किसी भी धर्म के नाम पर कोई प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जाता है, चाहे वे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले के लिए कि वे उस धर्म के, मानिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उस रूप में बिहार सरकार कोई प्रमाणपत्र या बिहार सरकार के किसी कार्यालय से कोई प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जाता है और दूसरी बात है सुविधा देने के लिए, तो बिहार सरकार सिखों को अल्पसंख्यक मानती ही है, ये अल्पसंख्यक हैं और नहीं तो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो अल्पसंख्यक आयोग हमलोग

बिहार सरकार की तरफ से बनाते हैं उसमें सिखों का भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, हमलोग जाति आधार पर प्रमाणपत्र देते हैं, धर्म आधारित कोई प्रमाणपत्र हमलोग नहीं देते हैं, लेकिन सिख समुदाय के प्रति बिहार सरकार की पूरी सहानुभूति है, संवेदना है, उनके लिए जो अनुमान्य लाभ है, उससे हम उनको वंचित नहीं होने देंगे, यह मैं सदन के माध्यम से पूरे सिख समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री रत्नेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरक था कि जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब लैंड का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो उसमें कॉलम आता है, उस कॉलम में सिख करके कोई कॉलम नहीं आता है, जब हम ई0डब्लू0एस0 में जैसे ई0डब्लू0एस0 में वैसे कैटेगिरी अपने जॉब के लिए आवेदन देते हैं, जो कहीं वर्ग में आच्छादित नहीं होते हैं, वह ई0डब्लू0एस0 में अपने रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं । अल्पसंख्यक के होस्टल में सिख, पारसी और अन्य समाज के लोग जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, तो उनको आवेदन करने के समय कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो सरकार इसके लिए कोई नीतिगत निर्णय लेकर और उनको किस तरीके से उनका समायोजन अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं में हो सके, इसके लिए सरकार एक नीतिगत निर्णय लेकर इसको करे । वर्ष 2021 से पत्रांक का भी ज्ञापन करना चाहता हूं, वर्ष 2021 से अल्पसंख्यक मंत्रालय और जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पत्रावली में नीति बनाने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है, परंतु उनको लाभ कैसे मुहैया कराया जाए, इस संबंध में अभी तक कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हुई है महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है और यह सही इसलिए है कि अभी सिखों के मैंने पूरे समाज का चाहे आय के आधार पर हो, जो कह रहे हैं ई0डब्लू0एस0 कैटेगिरी का, इन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना में आर0टी0पी0एस0 फॉर्म की भी चर्चा की है, तो उसमें अभी तक किसी समुदाय का नाम नहीं रहता है, इस्लाम का भी नहीं रहता है, ईसाई का भी नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है, यह तो जाति आरक्षण या कोई सुविधा जाति आधारित दी जाती है । सिख समुदाय में अभी जाति आधारित वर्गीकरण भी नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्यों का जो कहना है सरकार इसमें देखेगी और जो अल्पसंख्यक आयोग है, उन्हीं के माध्यम से सिख पूरे समुदाय में किस आधार पर इनका सामाजिक वर्गीकरण किया जा सकता है, इस पर सरकार विचार करेगी ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत प्रखंड नरपतगंज में मॉनसून के बाद नेपाल से छोड़े गए पानी एवं भारी वर्षा के कारण आई विनाशकारी बाढ़

एवं तूफान से आवास, धान एवं आलू की फसल की पूर्ण क्षति होने पर प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं राहत प्रदान करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती संगीता देवी : महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजधानी पटना के गांधी मैदान अथवा किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर सामाजिक न्याय के पुरोधा, जन–जन के नायक एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की मांग करती हूं ।

श्री आनन्द मिश्र : महोदय, बक्सर सदर अस्पताल में आई0सी0यू0 भवन और आधुनिक उपकरण उपलब्ध है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सों एवं तकनीशियनों की कमी से करोड़ों की व्यवस्था निष्क्रिय है । गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है । जनहित में आवश्यक मानव संसाधनों की तत्काल नियुक्ति कर यूनिट को अविलंब चालू करने की मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया स्थित फल्गू नदी में कलस्टर 9 के ठेकेदारों द्वारा 10 व 11 से अवैध बालू उठाओ होने से नैली, बड़की, मंडई, व पचलक पईन बेअसर और किसान बदहाल हैं । माइनिंग अफसर व स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए राजस्व हानि हो रही है ।

अतः इस संबंध में जांच एवं कार्रवाई की मांग करता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / पुलकित / 17.02.2026

श्री मंजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा अंचल के दानापुर में स्थित स्वयं भू–प्रकट प्राचीन दानेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करते हुए पर्यटकीय विकास करने और एन0एच0 27 से मंदिर को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–भंगाहा, थाना–फलका, जिला–कटिहार के राज्य राजमार्ग एस0एच–77 से नहर तक जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर है तथा वहां नाली का भी अभाव है ।

अतः सरकार से नाली के निर्माण कराते हुए उक्त सड़क के कालीकरण की मांग करती हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की शिक्षक स्थानांतरण नीति के कारण प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण स्कूलों में स्थानांतरण के बराबर अनुपात में ससमय शिक्षकों के पदस्थापना नहीं होने से विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहे हैं।

अतः स्थानांतरण के साथ–साथ ससमय पदस्थापन की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कलाधर प्रसाद मंडल जी, आपने जो शून्यकाल दिया है वह 70 शब्दों में दिया है, 50 शब्दों में नहीं है । आज आपको मौका दिया जा रहा है, भविष्य में 50 शब्दों में शून्यकाल देना है । इसका ध्यान रखिएगा । अब संक्षेप में पढ़िए इसको ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः नगर पंचायत भवानीपुर, रूपौली, बिरौली एवं ग्राम पंचायत टीकापट्टी, बड़हरा कोटी में फुटकर दुकानदारों को मजबूरन सड़क के किनारे अस्थायी दुकान लगाकर अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता है ।

अतः चलते सत्र में उक्त वर्णित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि चिन्हित कर वेंडिंग जोन का निर्माण कराकर विस्थापित दुकानदारों को दुकान सशुल्क आवंटित कराने की मांग करता हूँ ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर एवं बांका जिले में संथाली भाषा छात्र–छात्राओं की बड़ी आबादी है । जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं उच्च शिक्षा हेतु तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संथाली भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करना नितांत आवश्यक है ।

अतः वहां संथाली विभाग की स्थापना की मांग मैं सरकार से करता हूं।

श्री बबलू कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया नगर परिषद, सदर अस्पताल एवं मानसी नगर पंचायत में बारिश के दौरान भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहां पर समुचित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं है । दोनों जगह पर स्थायी जल निकासी व्यवस्था हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना शुरू करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

श्री इन्द्रदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत बड़हरिया प्रखंड के कोइरीगांवा स्थित सुप्रसिद्ध यमुनागढ़ देवी मां, बड़हरिया की ख्याति दूर–दूर तक स्थापित है । जहां श्रद्धालु पूजा एवं दर्शन के लिए आते हैं।

अतः यमुनागढ़ देवी मां, कोइरीगांवा को पर्यटक सूची में जोड़ते हुए राजकीय पर्यटक घोषित करने की मांग करता हूं।

श्रीमती सावित्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के श्री नितेश कुमार सिंह, संवेदक पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जमुई द्वारा अनियमितता किए जाने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद करीब 40 योजनाओं का निविदा कार्य आवंटित शिड्यूल पर देते हुए घटिया किस्म के चेकडैम एवं आहर निर्माण में भारी राजस्व की क्षति होने पर मैं संवेदक पर कार्रवाई हेतु मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शून्यकाल अति महत्वपूर्ण होता है ।

(व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा। लेकिन शब्द पर ध्यान रखें । आज कई, दो–तीन माननीय सदस्यों ने ऐसा किया है कि उनके शून्यकाल की संख्या 50 शब्दों से ज्यादा हो गयी है। हमारा आग्रह होगा कि 50 शब्दों के अंदर में ही शून्यकाल दें ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला में सहकारी समितियों के सी0सी0 (कैश क्रेडिट) 60 प्रतिशत दिया गया है जिसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने की मांग करता हूं एवं एफ0आर0के0 की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि की मांग करता हूं। साथ ही साथ जिले में अरवा चावल की जगह उसना चावल की आपूर्ति की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर राम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गेहूं, धान, हल्दी सहित सब्जी की खेती सबसे ज्यादा की जाती है । जबकि विभूतिपुर एवं दलसिंह सराय प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र नहीं है ।

अतः मैं सरकार से उक्त प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के पैक्सों में कार्यरत प्रबंधकों का मानदेय भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक–25.08.2025 को लोक वित समिति को अनुमोदन हेतु संचिका भेजी गई थी । मैं आपके माध्यम से संचिका की स्वीकृति कैबिनेट से हो, इसकी मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित ब्रिटिश कालीन निर्मित लोहईपुल जर्जर व क्षतिग्रस्त है । 1. सपही–विजूलपुर पंचायत के बीच धनौती नदी पर बकसवा पुल । 2. तीन प्रखंडों को जोड़ने वाली मच्छरगांवा और हरपुरराय पंचायत के बीच मखुआ नदी पर लोहई पुल।

उक्त दोनों क्षतिग्रस्त पुल जनहित में निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत पिपरा परसाइन पंचायत के लालबंदी ग्राम से होकर बहने वाली नदी पर स्लुईस गेट का निर्माण का आश्वासन पिछले सदन में मिला था । जिसका डी0पी0आर0 भी तैयार है ।

अतः सोनबरसा प्रखंडाधीन लालबंदी में स्लुईस गेट के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के मुख्य बाजार में अवस्थित महिला अस्पताल सुल्तानगंज के अपनी

पूरी क्षमता के साथ पुनः चालू कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, राजधानी पटना के गांधी मैदान या किसी महत्वपूर्ण चौराहें पर सामाजिक न्याय के पुरोधा, जन–जन के नायक, पद्मभूषण स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम शासन में स्वीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य बंद है । संवेदक के द्वारा निविदा प्रक्रिया रद्द करवा दिया गया है ।

अतः जनहित में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पुनः निविदा निकालने एवं भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग करता हूं ।

श्री अमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड–रून्नीसैदपुर, मनुषमारा स्पील चैनल हेतु वर्ष 2018 में अधिग्रहण भूमि का मुआवजा 1600 किसानों का अब तक लंबित है । जल संसाधन विभाग को 83 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त है ।

मैं सरकार से शीघ्र राशि आवंटन कर किसानों को मुआवजा भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की जांच होती है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ स्त्री रोग से संबंधित जांच होती है ।

अतः सभी तरह के रोग के लिए अल्ट्रासाउंड जांच हो ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / हेमन्त / 17.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल – 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 23701,17,90,000 / – (तेइस हजार सात सौ एक करोड़ सत्रह लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो0 कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव से

कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है।

अतएव, माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रखंड स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार यथा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकार की खामियों को छिपाने के लिए जीविका दीदियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है इसके कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण विकास विभाग की मांग 10/– रूपये से घटायी जाय।''

अध्यक्ष : श्री गौतम कृष्ण।

श्री गौतम कृष्ण : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं । सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, दूसरे अंबेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । अपनी पार्टी के युवा नेता तेजस्वी जी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति।

श्री गौतम कृष्ण : मैं महिषी विधानसभा के कौसी, कछार..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाये रखें ।

श्री गौतम कृष्ण : गरीब, कमजोर, ईमान और स्वाभिमान के वाहक सभी बड़े बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने अपने मान–सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाये रखें।

श्री गौतम कृष्ण : गरीब के इस बेटा गौतम कृष्ण को बी0डी0ओ0 से विधायक बना कर इस सदन में भेजने का काम किया है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है, मैं भावभीनी श्रद्धांजलि भी अपनी पार्टी की ओर से और गठबंधन परिवार की ओर से देता हूं, पूरे सदन की ओर से देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि जब सदन के अंदर रहता हूं, तो ऐसा लगता है कि मानो सुशासन का राज चल रहा है। जब सदन के अंदर होता हूं, तो लगता है कि रसगुल्ले बरस रहे हैं। जब सदन के अंदर रहता हूं, तो लगता है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। जब सदन के अंदर रहता हूं, तो लगता है राम राज चल रहा है। जब सदन के

अंदर रहता हूं, तो लगता है हर हाथ को काम है, हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति चिंता मुक्त है, हर व्यक्ति खुशहाल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाये रखें।

श्री गौतम कृष्ण : ऐसी परिपाटी बनाकर जिस तरह से सदन में चलते हैं, तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं, तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार का माहौल देखने को मिलता है, वही आतंक का राज देखने को मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाये रखें।

श्री गौतम कृष्ण : एक कहावत है, सुन लिया जाए।

''राजा ने कहा, रात है,
रानी ने कहा, रात है,
मंत्री ने कहा, रात है,
लेकिन यह सुबह–सुबह की बात है।''

तो ठीक उसी प्रकार, जब सदन के अंदर होते हैं, तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पर मुस्कान है, हर गरीब के हाथ में पैसे हैं, पलायन नाम की कोई चीज नहीं है, बहन–बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ढाक की तीन पात की तरह है। यानी कि बाहर और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा, रामराज और सुशासन है, उसी हां में हां बीजेपी कहती है, हां, रामराज और सुशासन है, एलजेपी कहती है, रामराज और सुशासन है। लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगलराज नहीं, महा जंगलराज में डूबी हुई सरकार है। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आर्थिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की खुशहाली से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के रोजगार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान से जुड़ा हुआ है। कल–कारखाने और उद्योग स्थापित हों, पलायन रुके, अपने परिवार के साथ रोजगार और जीवन को जीने के विषय से जुड़ा हुआ है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, इतना बेहतर विभाग, इतनी संभावनाओं से युक्त विभाग, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए के बजट वाला यह विभाग है, जो पिछले साल मात्र 16,000 करोड़ का था। ठीक है, बढ़ाइये, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जितने ज्यादा हर व्यक्ति को खुशहाल करने के एक–एक तरीके और चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर थोड़े से

हम लोग भ्रष्टाचार, थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी और थोड़े से अपनी सरकार की निगरानी में करना शुरू करें, तो शायद लगता है कि यह खुशहाल होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शोरगुल नहीं करें।

श्री गौतम कृष्ण : इस विभाग में मैं कार्यरत था। मैं पहले बी0डी0ओ0 था और हमारे माननीय मंत्री जी उस समय हमारे भी मंत्री थे। मैं कहता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी, आदरणीय श्रवण बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण बी0डी0ओ0 बन कर सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग के भ्रष्टाचार में, वहां से लड़ कर मुझे यहां पहुंचाया है। इसलिए मैं अपने महिषी और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं,..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, आसन की ओर देखें। गौतम जी, आसन की ओर देखें।

श्री गौतम कृष्ण : जिन्होंने गौतम कृष्ण जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को, स्वाभिमान को देखा और उसको अपनी नैतिकता और समर्थन दे कर बी0डी0ओ0 से विधायक बनाकर आपके साथ, आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। मैं तो कहता हूं यह विभाग कैसा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं और मेरा रिजाइन लेटर आपको नेट पर मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है और रिजाइन करते हुए, उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने का जो मेरा संक्षिप्त कार्यकाल था, 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में, जो मैंने देखा है, एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पर कुछ देखे–सुने मुझ पर कार्रवाई की थी और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते, तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी किए होते,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी, बैठ जाइये।

श्री गौतम कृष्ण : आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते, तो गौतम कृष्ण आज बी0डी0ओ0 के रूप में ही काम करता रहता। आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध कर अधिकारियों की मौज–मस्ती का एक होकर काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ खामियां गिनाने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं कि एक ईमानदारी के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गौतम कृष्ण हो या कोई और हो, उसको किस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार तो महिषी और नौहट्टा की उस जनता का हूं, जिसने अपना ईमान और स्वाभिमान हमारे मंत्री जी की तरह नहीं बेचा और उन्होंने चुनकर मुझे सदन में भेजने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रासंगिक विषय के आलोक में मैं यहां खड़ा हूं, इस विषय से कोई आदमी अछूता नहीं है।

(क्रमशः)

टर्न–14 / संगीता / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मनरेगा जब आया, एक बड़ा संकल्प लेकर आया, हर हाथ में रोजगार होगा, 100 दिन का रोजगार होगा, 15 दिन में उसको पैसे मिलेंगे, हर चीज होगा, लेकिन ये है क्या, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों में बदल गया है...

अध्यक्ष : अब बदल गया है, वीबी–जी राम जी हो गया है । मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है ।

श्री गौतम कृष्ण : नाम बदलने से काम और चरित्र नहीं बदलेगा, इसलिए हमें नाम बदलने तक ही, ये नहीं होना चाहिए उसका चरित्र बदलना चाहिए । आज जिस तरह से कोई भी इसमें माननीय सदस्य होंगे, उन सबको पता है कि भ्रष्टाचार में लगभग 60 परसेंट पैसा पहले चढ़ावा में ही चला जाता है, यह आलम है हमारे मनरेगा का । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, यह गरीब, बेघर, दलाल और बिचौलियों का...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं, सबों को मिलेगा बोलने का मौका ।

श्री गौतम कृष्ण : मालामाल करने का जगह है । यह प्रधानमंत्री आवास योजना, कागज पर तो लगता है कोई भी आदमी बेघर नहीं है । हर व्यक्ति के ऊपर में छत है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने ही विधान सभा का कि मेरा विधान सभा महिषी विधान सभा है, उसका कोसी का इलाका है, जिस कोसी के इलाका में 17 से 18 पंचायत कोसी के बांध के बीच पेट में बसता है । महोदय, एक बार किसी से दिखवा लिया जाय, किसी के घर में छत और पक्का मकान नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलेआम लूट नहीं तो और क्या है ?

कागज पर तो लगता है कि पूरी तरह से चकाचौंध है, अब कागज पर लगता है कि किसी को घर देने के लिए बचा नहीं है लेकिन हकीकत है कि 20 हजार रुपये का घूस सरेआम चलता है और 20 हजार बाद में जो मजदूरी मिलता है, वह भी लूट लिया जाता है...

अध्यक्ष : अब तो डी0बी0टी0 है न, अब डी0बी0टी0 के माध्यम से...

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो व्यवस्था डी0बी0टी0 की हो गई है । यह कांग्रेस के राज्य में था, कहते थे 100 रुपया भेजते हैं वह गरीबों को नहीं पहुंचता है, मात्र 10 रुपया पहुंचता है । जबसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आयी है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार जबसे आयी है तो आज बिहार में डी0बी0टी0 के माध्यम से गरीबों को पैसा भेजा जा रहा है ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा, यह तकनीकी बात है, यह सैद्धांतिक बात है लेकिन व्यावहारिक बात नहीं है । किस तरह से बिचौलियों के हाथ में बिना 20 हजार रुपये गए हुए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : याद करा दिए हम ।

श्री गौतम कृष्ण : किसी का काम नहीं होता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । अध्यक्ष महोदय, नल–जल योजना का क्या हाल है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट, राजू बाबू बोलना चाहते हैं ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, महिषी के विधायक जी बोल रहे हैं, यह उस समय यू0पी0ए0 के जो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया बीच में रह जाता है, मात्र 15 रुपया पहुंचता है । यह इनके गठबंधन के नेता बोले हैं । पहले का क्या था, ये इनके नेता बोल चुके हैं, इनको स्मरण करना चाहिए, उस पर भी कुछ बोलना चाहिए महोदय ।

श्री गौतम कृष्ण : महोदय, वह पैसा क्या होता था कितना पहुंचता था । आज तो सब का सब लेकर ही विदेश भाग जाता है, आपकी सरकार में महोदय, यह हो रहा है । आपका जो नल–जल योजना है, यह पूरी तरह से कहां नल है और कहां जल है, कोई तालमेल नहीं है । इसका प्रत्यक्ष सदन ने ही देखा है । हर सदस्य की चिन्ता रही है, अगर अपने–अपने छाती पर हाथ रखकर बताइए किसके विधान सभा में नल और जल चल रहा है, काम कर रहा है इसलिए ये पूरी तरह खुलेगाम लूट और महालूट का चलता है । अध्यक्ष महोदय, नली–गली योजना किस तरह से पैसे की बर्बादी है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है । मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो जन संपर्क योजना है, लेकिन मैं यह कहता हूं, यह संपर्क योजना है, लेकिन यह संपर्क योजना आज

भी फलीभूत सही रूप से नहीं हुआ है । मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा लेकिन अपनी ही विधान सभा में देखता हूं जब हमारे यहां से माननीय मंत्री जी और...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गौतम कृष्ण : मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 घंटा में हम पटना आते हैं...

अध्यक्ष : कृपया आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री गौतम कृष्ण : जब कहते हैं कि 4 घंटा में कोई भी कहीं से भी पटना आ सकता है...

अध्यक्ष : गौतम कृष्ण जी...

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । तो हम कहते हैं कि मेरे महिषी विधान सभा में एक छोर से दूसरे छोर अगर कोई 4 घंटा में जाकर दिखा दे तो मैं मानूंगा कि सरकार जो कहती है वह बात सही है...

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट सर, एक मिनट । मैं यह कहना चाहता हूं बहुत सारे हमारे साथी लोग, माननीय सदस्य लोग कहते हैं कि...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

बैठाइए इनको अध्यक्ष महोदय, बैठाइए ।

अध्यक्ष : बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बैठाइए इनको । आसन का ये सम्मान करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विजय कुमार खेमका जी, आपका 12 मिनट है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अनुदान की मांगों के समर्थन में, सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, आज भारतरत्न जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है, उस पर मैं उन्हें नमन करता हूं, सदन की ओर से भी नमन करता हूं और पूर्णिया की जनता की ओर से भी नमन करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज मैं आभार व्यक्त करता हूं आसन का, साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व राज्य नेतृत्व और पूर्णिया की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज तीसरी बार सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है । महोदय, ये जो बजट है, ग्रामीण विकास विभाग का बजट जिसमें आज ऊर्जा, मद्य निषेध, वाणिज्य कर विभाग भी उसमें संयुक्त रूप से है । यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह प्रतिबद्ध विकास का

संकल्प है । यह बजट जो है, बिहार को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है ।

अध्यक्ष महोदय, जो बी0डी0ओ0 थे, अब सदस्य बन गए, अभी चले गए हैं, उनका साहस नहीं हुआ कि हम बैठकर सुन सकें । अध्यक्ष महोदय, दो लाईन विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ वरिष्ठ भी हैं, हमारे सामने अजय जी भी हैं, चाहते हैं, जानते हैं अच्छा हो रहा है लेकिन उनकी बाध्यता है कि वे उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं । दो लाईन से शुरू करता हूं अध्यक्ष महोदय,

'नकाब हटा तो चेहरा बेनकाब हो गया
झूठ बोलने वालों का जनता ने हिसाब कर दिया ।

हिसाब तो हो गया इनका, जो रोकते थे रास्ता, जो अभी बोल रहे थे हमारे गौतम कृष्ण जी कि बी0डी0ओ0 भी, वे जो बने, एन0डी0ए0 की सरकार में ही बी0डी0ओ0 बने थे और एन0डी0ए0 की सरकार में जब बी0डी0ओ0 थे और ग्रामीण विकास में जो काम हुआ, उसी के चलते ये सदन पहुंच गए और ये उस समय रोकते थे रास्ता कि हमें नौकरी दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, जो रोकते थे रास्ता, वही आज सवाल करते हैं आज सवाल कर रहे हैं, विकास की आंधी में इनका सारा काम तमाम हो गया । अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विकास की बात कीजिए न, तो विकास तो रफ्तार के साथ चल रहा है, इतनी तेजी से रफ्तार के साथ हैं कि विकास के क्षेत्र में पूरे देश में आज नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में डबल ईंजन की सरकार में बिहार में विकास ही विकास है, लेकिन इनको नजर नहीं आता है इसलिए कि ये महागठबंधन, जंगलराज और कांग्रेस का 60 साल, उससे कौन वाकिफ नहीं है महोदय, उस शासनकाल में कैसी स्थिति थी महोदय, जब हम बात करते हैं विकास की तो वह इतिहास हमारा पीछा नहीं छोड़ता है । इनका जो इतिहास रहा है जंगलराज का, जिसने बिहार को पूरे देश में बदनाम किया, उसको लोग याद करते हैं और आगे फिर कोई ऐसी जुर्रत नहीं करें, उस दिशा में लोग काम कर रहे हैं ।

महोदय, इन्होंने तो बिहार का चारा खा लिया और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, याचिका दिए हैं कि हमारी जमानत जो है, वह रह जाए । ऐसी सोच के हैं ये लोग महोदय, कैसी स्थिति थी ? ये भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, रंगदारी, फिरौती, डकैती, हत्या, पलायन और भयपूर्ण वातावरण था ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / यानपति / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, शाम ढलते ही लोग नहीं निकलते थे और आज राम राज्य कहने पर इनको चिढ़ लग जाती है । आज सुशासन की सरकार है और आज इस सरकार पर जनता का विश्वास है । जनता का विश्वास है महोदय, और 2025 के चुनाव में जो यह लोग लेकर गए थे लोगों ने इन्हें याद दिलाया कि आपने चारा खाया है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मिया सुभान अल्लाह । बड़े मियां ने चारा खाया और उनके पुत्र ने जो नौकरी की बात करते हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम कर लिया । ऐसी सोच के ये लोग हैं और कहते हैं कि हम कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हैं । एक तरफ आप विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ आपने पूरी तरह बिहार में विनाश करने का काम किया । आज एन0डी0ए0 की सरकार और जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो बिहार में बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। आदरणीय मंत्री श्रवण बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान को बढ़ाने का काम किए हैं । आज किसान के चेहरे पर लाली है । आज हमारे बिहार की जो जीविका दीदी हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है । आज उद्योग के माध्यम से उन्हें उद्यमी बनाकर के 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपया पहुंचाया गया तो इन्होंने कोहराम मचा दिया । अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है । और यह सरकार तो कहती है महोदय, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि दो लाइन में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सपनों को सच करने का हमारा वादा है, सपनों को, कौन सा सपना बिहार को विकसित बनाने का सपना, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है उस सपने को सच करने का हमारा वादा है । हर गांव को विकसित बनाने का एन0डी0ए0 सरकार का इरादा है । अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है । बिहार में चारों ओर शांति और भाईचारे का वातावरण है । बिहार गांवों का प्रदेश है और गांवों का विकास ही बिहार व देश की प्रगति की सच्ची तस्वीर है । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जल जीवन हरियाली के अभियान को साकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की योजना से गांव के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है । महोदय, कुल सहायता जो स्वयं सहायता समूह हैं 11 लाख 45 हजार उसकी संख्या हो गई है । 11 लाख से ज्यादा गांवों में और शहर में भी 41 हजार हमारी जीविका दीदी आज जो हैं, जीविका के माध्यम से सरकार की योजना के माध्यम से आच्छादित हो रही हैं । आज शहद उत्पादन के क्षेत्र में गांव में 4340 मी0ट0 शहद का उत्पादन भी हो रहा है महोदय । अध्यक्ष महोदय, गांवों में खेल का मैदान, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है । खेलो इंडिया, मेडल लाओ इंडिया, खेलो और नौकरी पाओ आज पूरे बिहार

में अभियान चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, गांवों में शादी विवाह के लिए जो है विवाह मंडप बनाए जा रहे हैं उसका निर्माण हो रहा है । रसोई दीदी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। आज बड़ी संख्या में 469 स्थानों पर रसोई दीदी कार्यरत हैं और जिसकी रसोई का स्वाद बिहार के उन क्षेत्रों में, उन विभागों में लोग प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लखपति दीदी की योजना लाई है उसमें 31 लाख 71 हजार लखपति दीदी बिहार में चिन्हित हुई हैं और इस बार के बजट में और भी बड़ी संख्या में हमारी दीदीयां लखपति दीदी बनेंगी और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनको हमने 10 हजार रुपया दिया है उसमें वह उनका उद्योग, उनका रोजगार अच्छा चलेगा तो हम उसको 2 लाख रुपया देने का भी काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे माथे पर छत, इनलोगों ने तो माथे पर छत छीनने का काम किया है लेकिन एन0डी0ए0 की डबल इंजन सरकार ने जो है गरीबों के माथे पर छत देने का काम किया है । पक्का घर, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता सहायक आवास हो उसके माध्यम से लोगों को घर मिला है । अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के क्षेत्र में 1 करोड़ 4 हजार से ज्यादा मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण हुआ है । तालाब, पोखर, अहर, पईन का जीर्णोद्धार किया गया है और अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत जीरामजी की योजना को लाने का काम किया है और अध्यक्ष महोदय, जीरामजी सुनते के साथ ये भड़क जाते हैं, जिस तरह कि लाल कपड़े को देखकर सांढ़ भड़कता है । अध्यक्ष महोदय, इनको बर्दाश्त नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो । जीरामजी जो योजना है वह गांवों को विकसित बनाने की योजना है । गांवों में हमारे जो श्रमिक हैं, जो जॉब कार्डधारी हैं जिनको पहले 100 दिन की गारंटी मिलती थी अब 125 दिन की गारंटी मिलेगी । 125 दिन की गारंटी मिलेगी और...

(व्यवधान)

जरा शांत रहिए, आप पढ़े–लिखे हैं, मैं जानता हूं । पिछले सत्र में भी मैं देखा हूं लेकिन अध्ययन कीजिएगा, तो जानकारी सदस्य महोदय होगी । माननीय सदस्य जी, सुनिये । अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है सप्ताह में उसके पेमेंट की गारंटी दी गई है और पेमेंट में अगर देरी होगी तो उसका जो है हम साथ में हर्जाना भी उसको देने का काम करेंगे । यह है जीरामजी, केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना, जिससे कि पूरे बिहार के गांवों का विकास होगा । ए0आई0 सर्वे से उसका मूल्यांकन किया जायेगा । जो बी0डी0ओ0 साहब सदस्य बनकर आए हैं, उनको मालूम है कि उनके गड़बड़ी के कारण ही केंद्र को ये योजना लानी पड़ी और ये महोदय, चिल्लाते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से योजना हटा दी गई...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विजय कुमार खेमका : महात्मा गांधी का हम सबों ने जितना सम्मान किया है उतना किसी ने नहीं किया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : आपने तो अपमान किया है ।

अध्यक्ष : विजय जी, समाप्त कीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : शॉर्ट करना है सर । एक मिनट में समाप्त करेंगे अध्यक्ष महोदय। मेरा समय 12 मिनट है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : हो गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : वैसे चार मिनट है अभी अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं–नहीं, देख लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो अपमान करने का काम किया है । ये संविधान की किताब लेकर के पूरे देश को, बिहार को भ्रम में डालने का काम किये हैं, इसे तो बिहार के...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्या, श्रीमती कोमल सिंह ।

श्री विजय कुमार खेमका : हर कोने से, हर घर से असत्य पार्टी के रूप में कहा जाता है महोदय ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : एक मिनट में समाप्त करता हूं महोदय, दो–तीन सुझाव देते हुए मैं माननीय जो हमारे ऊर्जा मंत्री भी यहां पर हैं, हमारे जो है ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी हैं, मैं कहना चाहूंगा, गांवों में जो खेल मैदान बनाया गया है, उसमें जो उसकी सामग्री है और उसके देखरेख की जो जिम्मेवारी है...

अध्यक्ष : अलग से लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं तुरंत कंक्लूड कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : 14 मिनट हो गया आपका । श्रीमती कोमल सिंह ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानी जो भूमिगत हैं, जो आजादी की लड़ाई में काम किये, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले ।

अध्यक्ष : श्रीमती कोमल सिंह ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हो गया देखिए, आपका समय ज्यादा हो गया, और मेंबर को बोलना है न । अब लिखकर दे दीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं चार लाईन कहकर भाषण समाप्त करता हूं,

''राहे चाहे कठिन हो,
कदम नहीं रुकने देंगे,
जनता के विश्वास को
कभी नहीं झुकने देंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती कोमल सिंह ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूं । सबसे पहले मैं बिहार की महान भूमि और गायघाट की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूं । मैं गायघाट की जनता का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझे सदन में अपनी आवाज बनने का गौरव प्रदान किया ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / मुकुल / 17.02.2026

क्रमशः

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस सदन की सदस्य हूं जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है । महोदय, आज यह सदन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है । उनके सुशासन की विचारधारा ने बिहार को एक नई पहचान दी है । यह सदन गवाह है कि हमने केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया सुनहरा इतिहास लिखा है । अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का भविष्य उनके गांवों में बसता है । हमारी सरकार का भी यही मानना है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा । यह हमारी सरकार की सफलता है कि ग्रामीण विकास विभाग को पिछले वर्ष 30,150 करोड़ रुपये दिये गए थे, लेकिन गांवों की जरूरतों को देखते हुए 35,521 करोड़ रुपये खर्च किए । इस वर्ष भी 30,387 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । बिहार ने 2026–27 में अपने कुल एक्पेंडिचर का 9.4 परसेंट ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है, जो देश के अन्य राज्यों के औसत 4.8 परसेंट से लगभग डबल है । एक समय था माननीय अध्यक्ष महोदय 90 का दशक जब यहां के मुख्यमंत्री खुद को गांव और किसान का बेटा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी यह किसी से नहीं छिपा था । वो गांव से भले आते थे लेकिन गांव का विकास करना, उसी गांव की गलियों में भूल आये थे । गांव के भोले–भाले लोग लालटेन जलाकर विकास का इंतजार करते रहे, लेकिन उसी लालटेन ने पूरे बिहार को अंधकार और भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया । आज समय बदल चुका है, अब मुख्यमंत्री केवल गांव से नहीं आते हैं, बल्कि गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाते हैं । गांव में बिजली लाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्वयं सहायता समूहों को ताकत देते हैं और ग्रामीण इलाकों में सम्मानजनक

रोजगार देते हैं । हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास का वो एल0ई0डी0 बल्ब जलाया है, जिसकी चमक से आज हर गांव रोशन है और सिर्फ एक सदस्य होने के नाते नहीं बिहार की बेटी होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जज्बे को सलाम करती हूं और पूरे गौरव के साथ यह कहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो हीरा हैं जिनकी चमक से आज हमारा पूरा बिहार चमक रहा है । महोदय, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली आत्मा हमारी महिलाएं हैं । एक समय था जब बिहार की महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, लेकिन आज जीविका के माध्यम से बिहार के 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है । आज बिहार की जीविका योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है । वर्ल्ड बैंक ने माना है कि जीविका की वजह से ग्रामीण परिवारों की आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ वोट नहीं समझा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है । आज बिहार की बेटियां किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर, अपने हुनर पर आगे बढ़ रही हैं । महोदय, लगातार विपक्ष के द्वारा मीडिया हो या सदन हो, बिहार की महिलाएं जोकि बिहार की आधी आबादी है, उनका अपमान किया जा रहा है । उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिलाओं को रिप्रजेंट करती हूं इसलिए विपक्ष का ये बेबुनियादी कटाक्ष अस्वीकारणीय है । बार–बार महिलाओं के मतदान को सरकार की महिला रोजगार योजना से जोड़–जोड़कर विपक्ष ने न सिर्फ सरकार पर महिलाओं को वोट खरीदने का आरोप लगाया है, बल्कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं पर अपने वोट बेचने का आरोप लगाया है जोकि अपमानजनक है । इनकी जब सरकार थी तब महिलाओं को तो सम्मान ये दे नहीं पाए और जब एन0डी0ए0 की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है तो इनलोगों को यह हजम नहीं हो रहा है । लेकिन ये नीतीश जी का बिहार है, यहां सबके साथ न्याय होता है और सबके विकास की नीतियां बनती हैं । अगली बार महिलाओं के मतदान पर सवाल उठाने से पहले मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि ये अपनी सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की लाचारी और एन0डी0ए0 सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की मजबूती का फर्क अच्छे से तुलना कर लेंगे तो ये समझ जायेंगे कि बिहार की महिलाएं इतनी मजबूती के साथ एन0डी0ए0 के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ क्यों खड़ी है और उनका विश्वास इनके प्रति क्यों अडिग है । महोदय, लेकिन जिस सरकार ने 1990 से लेकर 2005 तक अपने 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त करना तो दूर की बात है, सम्मान तक नहीं दिया, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है ।

मैं इनको बताना चाहती हूं कि भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं लेकिन सरकार की 10 हजार वाली योजना नहीं वजह मैं आपको बताती हूं । इज्जत घर, यह एन0डी0ए0 की सरकार है, याद कीजिए 90 के दशक, यह एन0डी0ए0 की सरकार है, एन0डी0ए0 की सरकार ने महिलाओं को शौचालय दिया, सम्मान दिया, इज्जत घर दिया । अब 90 के दशक की तरह बिहार की महिलाओं को घूंघट में रात के अंधेरों में शौच करने जंगल नहीं जाना पड़ता है । जंगल राज हटाकर सुशासन की सरकार बनाकर महिलाओं को सुरक्षा दिया कि आज वह निडर होकर अपने घर के बाहर निकल पाती हैं । बिहार की महिलाओं और बेटियों को शिक्षा का अवसर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, महिला रोजगार योजना । महिलाओं को न सिर्फ जागरूक किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया । सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 परसेंट आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण । आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी कहीं हैं तो हमारे बिहार में हैं । आज हर–घर नल–जल है, घर–घर बिजली है, आज गांव–गांव को सड़क से किसी ने जोड़ने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एन0डी0ए0 की सरकार ने किया । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 लाख 8 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 216 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर गरीबों को छत दी गयी । पिछले 10 वर्षों में बिहार के गांवों में 55 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया । अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो 2005 में बिहार की क्या स्थिति थी किसी से छिपा हुआ नहीं है, केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे । आज यह संख्या 2 करोड़ 20 लाख के पार चली गयी है । 1990 के दशक में बिहारवासी बिजली को मोहताज रहते थे, जहां 7–8 घंटे भी गांव में बिजली नहीं जाती थी आज बिहार के गांव में भी 23–24 घंटे बिजली रहने का काम होता है । अध्यक्ष महोदय, एन0डी0ए0 की सरकार केवल बिजली नहीं दे रही पर्यावरण पर भी ध्यान रख रही है । जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं । सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में इसे 500 मेगावाट तक ले जाने का । अंत में महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को भी शानदार बजट के लिए बधाई देना चाहती हूं 3 फरवरी, 2026 को उन्होंने 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया । याद करिए, 2005 का बजट सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ का हुआ करता था, यह हमारी सरकार में बजट भी 15 गुना बढ़ गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदला है । उस बिहार को बदला है जो पूरे भारत देश के नक्शे में पिछड़ा माना जाता

था । आज बिहार के युवा तकनीक में, कौशल विकास में और उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं । मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10–10 हजार रुपये की सहायता देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है । महोदय, मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है । यह यात्रा हमें विश्वास दिलाता है कि बिहार अब केवल संभावनाओं का प्रदेश नहीं, बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन रहा है । बिहारियों को कल भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा था, आज भी इन्हीं पर भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं पर भरोसा रहेगा, क्योंकि युवाओं को भी प्रेरणा अपने मुख्यमंत्री से मिलती है और क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को ही अपना धन माना है, ऐसे व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एन0डी0ए0 की सरकार है, आज इनका समय है कल हमारा दौर आयेगा तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि यही सोच का फर्क है आपमें और एन0डी0ए0 में, आप हमेशा आई, मी, और माईसेल्फ की बातें करते हैं लेकिन एन0डी0ए0 के नेता बिहारवासियों की बातें करते हैं, बिहारियों की बातें करते हैं इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अगर एन0डी0ए0 की सरकार है तो यह हमारा समय नहीं बिहारियों का समय है और आगे दौर भी बिहारियों का ही आयेगा । अंत में विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूंगी कि बिहारवासियों का महागठबंधन सरकार के कार्यकाल का जो उनका अनुभव रहा है और इनका आसमान से बातें करने वाला जो घोषणापत्र रहा है, यही वजह है इनके हार का । डॉ0 लोहिया जी ने कहा था सच्चा विकास वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आज यह बजट उसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जहां नीति और नीयत साफ हो वहां नतीजे खुद बोलते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

विपक्ष को आंकड़े दिखते हैं, हमें बदलाव दिखता है । उन्हें खर्च दिखता है, हमें भविष्य दिखता है । विपक्ष के पास आरोप हैं, हमारे पास उपलब्धियां हैं ।

क्रमशः

टर्न–17 / सुरज / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती कोमल सिंह : उनके पास शोर है, हमारे पास गांव–गांव तक पहुंचती सड़कें हैं । उनके पास भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, हमारे पास विकास की स्पष्ट नीति है

। अंत में अपने नेता की तरफ से मैं विपक्ष के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी :

मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सींचा है
बंजर माटी में पलकर, मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है ।
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे
मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे

बहुत–बहुत धनयवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी । आपके पास चार मिनट का वक्त है ।

श्री मनोज विश्वास : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । आज ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का समय मिला है इसके लिये हम तमाम सदन के लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल एरिया से आते हैं, कार्य तो हुआ है यह हम सभी लोग मानते हैं लेकिन उसके साथ ही हमलोगों का विनाश भी हुआ है । उसके लिये आप...

(व्यवधान)

आप पहले सुन तो लीजिये ।

उपाध्यक्ष : टोका–टोका नहीं ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, हमलोग सीमांचल एरिया से आते हैं । वहां हमलोगों की मुख्य समस्या बाढ़ की है । काम होता है और हरेक साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है जिसके चलते किसान तबाह रहता है, वहां का मजदूर तबाह रहता है, 2016 से कंटीन्यू सर । हम पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं और हर साल बाढ़ आती है लेकिन उसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । जिसके चलते पूरे साल वहां के किसाने परेशान रहते हैं, इस पर विचार किया जाए । दूसरा, हमारे ऊर्जा विभाग में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, उनका जो काम हुआ है अभी–भी हमारे क्षेत्र में कहीं–कहीं पर अभी भी बांस के सहारे लोग तार ले जाते हैं। कई बार हमलोग विभाग को भी इसकी सूचना दिये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ । हम ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री दिये हैं, वैसे परिवार जो गरीब परिवार हैं । मगर उसके ऊपर जो बकाया राशि है 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार । हम ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उसको माफ किया जाए और गरीब का जो अभी लाईन काट दिया जाता है, बिना सूचना के । उसके पास न ही तेल है, न ही संसाधन है फिर वे लोग रहेंगे कैसे ? बिजली तो हमलोगों के शरीर का एक अंग हो गया है । इसके लिये हम ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उस पर विचार किया जाए और तमाम बिहार में यह समस्या आ रही है, बिना सूचना के उसका लाईन काट दिया जाता है । दूसरा, महत्वपूर्ण चीज है, मद्य निषेध पर

भी बोलना था । महोदय, 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया । शराबबंदी कानून अच्छा था, उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है । मगर उसका अभी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है । गांव, देहात और टोले–मोहल्ले में जो सूखा नशा होता है, आने वाला जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, वह सब विकलांग हो जायेंगे । आप कहीं पर भी पता कर लीजिये उसके चलते कई लोग परेशान हैं । बाप, बेटा, माँ सबको नहीं पहचान रहा है । इसके लिये हम सदन के माध्यम से मांग करेंगे कि इस पर रोक लगायी जा सके । दूसरा, महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहां । हमलोगों का बहुत अच्छा स्कीम था । वैसा गरीब परिवार का जो पोषाहार, आंगनबाड़ी के माध्यम से वैसे परिवार जो विकलांग हों, उसको दिया जाता था मगर उसमें क्या हो रहा है कि सरकार की सबसे नाकामी उसी जगह फेल हो रही है । विभाग के द्वारा हर सेंटर से सात से पांच हजार रुपये की उगाही की जाती है, हर क्षेत्र में उसका दलाल है जो उस पैसे को वहां भेजने का काम करता है । 80 परसेंट, जो जनता तक पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच पाता है, यह बहुत बड़ी समस्या है । दूसरा, सेविका और सहायिका जिसका मानदेय हम नौ हजार रुपया रखे हुये हैं । एक सेविका के साथ...

(व्यवधान)

आपको बताते हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री मनोज विश्वास : उसके बाद उस सेविका को जो 9 हजार रुपया वेतन दिया जाता है एक सेविका के साथ में उसका हसबैंड उसके साथ रहता है, उसका मानदेय बढ़ाया जाए । दूसरा, सर उसको जैसे जनगणना में हमलोग उसको यूज करते हैं, एस0आई0आर0 में भी उसको यूज किये तो उसका भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है । दूसरा, महत्वपूर्ण चीज है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं । माननीय सदस्य नये हैं ।

(व्यवधान)

इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पर जांच बैठाया जाए जो पैसे की उगाही होती है, श्रवण बाबू के साथ भी हम काम किये हैं, इस पर सर जांच टीम बैठायी जाए । सच्चाई है, उसका जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए । दूसरा, हमलोगों के यहां बाढ़ की समस्या है हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हुये हैं, हम कई बार मिले भी हैं । महोदय, 2016 से हम कंटीन्यू हैं वहां पर और....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाएं ।

श्री मनोज विश्वास : वहां पर बाढ़ हरेक साल आती है, उसका निदान दिलाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : यह ग्रामीण विकास विभाग का बजट है माननीय सदस्य । आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य एक समाजवादी, चिंतक, विचारक ने कहा था कि जो काम होता है उसकी भी चर्चा हो और जो नहीं होता है उसकी भी चर्चा हो । माननीय सदस्य नए हैं और संक्षिप्त भाषण में इन्होंने सरकार की प्रशंसा भी की है, अपनी बातें भी रखी हैं । बहुत धन्यवाद है आपको ।

माननीय सदस्य श्री विशुनदेव पासवान जी । आपके पास में पांच मिनट का वक्त है ।

श्री विशुनदेव पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जी का और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का और दरौली विधान सभा के देव तुल्य जनता जनार्दन को जिन्होंने मुझे इस गरिमामयी सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों की मांगों के समर्थन में पूरे दमखम के साथ खड़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना जीविका, बिहार के 01 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है ।

परिवारों की आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । पहले जो वार्षिक आय 35 हजार 968 रुपये थी, वह बढ़कर 46 हजार 758 रुपये प्रति वर्ष हो गयी है ।

शुरूआत में परिवारों का कर्ज 50 प्रतिशत था जो अंतिम सर्वे में घटकर 7 प्रतिशत हो गया है ।

अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 10 लाख 53 हजार स्वंय सहायता समुहों के बचत बैंक खाता खोले गए हैं और कुल मिलाकर 62 हजार 628 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है ।

ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जाने की योजना के तहत कुल 06 हजार 459 बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केन्द्र खुलवाये गये हैं ।

ग्रामीण परिवारों के जीवन बीमा हेतु अब तक कुल स्वंय सहायता समूहों से जुड़े 91 लाख 11 हजार सदस्यों का बीमा कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में करीब 1.29 लाख समूहों को बैंक द्वारा 07 हजार 52 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । महिलाओं की उद्यमशिलता को और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्था बिहार राज्य

जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) का गठन किया गया है।

आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं–विपक्ष को ग्रामीण विकास से समस्या नहीं है, इन्हें सरकार की सफलता से समस्या है । जिनके शासन में गांवों की पहचान, टूटी सड़कें, अंधेरें घरों और पलायन से होती थी । आज वहीं लोग विकास की परिभाषा पढ़ा रहे हैं।

मैं विपक्ष से सीधा प्रश्न पूछता हूं – क्या यह सत्य नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिला ? क्या यह सत्य नहीं कि मनरेगा के तहत करोड़ों मानव दिवस सृजित हुए और मजदूरों का पैसा सीधे खाते में गया ? क्या यह सत्य नहीं कि जीविका से जुड़ी एक करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक ताकत मिली ?

यदि यह सब झूठ है तो सदन में कहें ! और यदि सच है तो स्वीकार करें !

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की राजनीति ''विकास रोको, भ्रम फैलाओ'' पर चलती है :

जिन्होंने सालों तक दिया नहीं उजाला,
वो आज चिरागों की लौ पर सवाल उठाते हैं ।
जिनके राज में गांव था बदहाल,
वो हमसे विकास का हिसाब मांगते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हजारों किलोमीटर सड़कें बनीं । ''हर घर नल का जल'' योजना से ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचा । स्वच्छ भारत मिशन से लाखों शौचालय बने । पहले ग्रामीण माँ–बहनों को अंधेरे में रहना पड़ता था । आज उन्हें सम्मान मिला है । क्या यह विकास नहीं है ?

गरीबों के मसीहा पद्मभूषण आदरणीय स्व0 रामविलास पासवान जी कहा करते थे, राजनीति का धर्म है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना । आज ग्रामीण विकास विभाग वही काम कर रहा है । अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में ला रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / धिरेन्द्र / 17.02.2026

....क्रमशः....

श्री विष्णु देव पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नारा है–'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'। इसका मतलब साफ है कि बिहार का विकास बिना भेदभाव के । बिहार का पैसा, बिहार के गरीबों के लिए है लेकिन कुछ लोगों को जाति की राजनीति से

फुर्सत नहीं है । उन्हें गरीब की झोपड़ी नहीं दिखती, उन्हें केवल अपनी कुर्सी दिखती है । विपक्ष कहता है योजनाओं में कमी है । मैं कहता हूँ, आईए, सुझाव दीजिये लेकिन विकास रोकने की राजनीति मत कीजिये । सिर्फ आलोचना से इतिहास नहीं बदलते, इरादे आर हिम्मत से हालात बदलते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अब पारदर्शिता से सब कुछ हो रहा है । आज भुगतान डी॰बी॰टी॰ से हो रहा है । बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं, यही सबसे बड़ा दर्द है विपक्ष का । पहले कमीशन की राजनीति थी, आज कमिटमेंट की राजनीति है । उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की अनुदान राशि पर सवाल उठाना दरअसल गाँव के गरीब पर सवाल उठाना है । यह बजट केवल कागज का आंकड़ा नहीं, यह किसान की उम्मीद है, यह मजदूर की रोजी है, यह महिला की आत्मनिर्भरता है और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हम विकास के रास्ते पर अडिग हैं । न दबेंगे, न रूकेंगे, न झुकेंगे । जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है वह हमारे साथ आए, जो बाधा बनेगा जनता जवाब देगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों की मांगों का जोरदार समर्थन करता हूँ और सदन से इसे पारित करने का आग्रह करता हूँ । जय सिवान, जय बिहार, जय भारत ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद । आपने कम समय में अपनी बातें रखी । माननीय सदस्य मो॰ तौसफी आलम जी, अपना पक्ष रखें । आपके पास चार मिनट का समय है ।

मो॰ तौसीफ आलम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूँ । सबसे पहले मैं अपने नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दुआ से हमने यहां पांचवी बार विधान सभा पहुँचा ।

(व्यवधान)

सुनिये न ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं कीजिये ।

मो॰ तौसीफ आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र खासकर बहादुरगंज की जनता मुझे पांचवी बार जीतायी है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ । महोदय, हमने वर्ष 2005 से देखा है विकास हुआ है इसमें सच्चाई है लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे सरकार भाग नहीं सकती है । महोदय, तमाम महापुरुषों ने कहा है कि भारत गाँव का देश है, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा । आज जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, लोहिया स्वच्छ अभियान या जल–जीवन–हरियाली योजना हो, सभी में लूट मची हुई है । महोदय, कौशल विकास के नाम पर ट्रेनिंग एण्ड लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं लेकिन युवा को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है जिससे बिहार के

लाखों युवा बेरोजगार हैं तथा अन्य राज्य में रोजगार हेतु पलायन कर रहे हैं । महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट बता रहे हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास की प्राथमिकता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार के प्रावधान करने में विफल रही है । महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है लेकिन ग्रामीण विकास में एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास में मैं नाम जोड़ने की, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गाँव में लोग परेशान हैं, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं । महोदय, जब जाति आधारित जनगणना हुई तब एक आंकड़ा आया था जिसमें वर्णन था 94 लाख लोग 06 हजार आमदनी वाले हैं, 06 हजार से 10 हजार आमदनी 81 लाख लोग हैं तथा 10 हजार से 20 हजार आमदनी वाले 50 लाख लोग हैं, उनके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । महोदय, आज गरीबों की बात नहीं हो रही है जिसे चप्पल और साईकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, वैसे गांव के गरीब मजदूरों के विकास की बात सरकार नहीं सोच पा रही है । महोदय, आज जब हमलोग प्रखंड में जाते हैं तो पता चलता है कि इंदिरा आवास में लूट–खसोट हो रहा है । नाम चढ़ाने के नाम पर दो हजार लिया जाता है और जब फर्स्ट पेमेंट होता है तो 12 हजार लिया जाता है फिर सैकेंड पेमेंट में दौड़ा–दौड़ा कर उसको परेशान किया जाता है । महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा । खासकर मनरेगा में, मनरेगा में लूट–खसोट है । खासकर दिघलबैंक प्रखंड में एक नदी है, जिसे कालोपरी कहते हैं, उस नदी के कछार में तलाबनामा खोद कर मनरेगा से पैसा निकाला गया है । मैं चाहूँगा कि दिघलबैंक प्रखंड में जो भी मनरेगा का काम हुआ है उसमें जाँच हो । वर्ष 2024–25 का और 2025–26 का, इसकी जांच हो और मैं बिजली के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में बनगमा पंचायत है जहाँ अभी भी बांस के खंभा में बिजली का पोल लगा हुआ है । बनगमा पंचायत के वार्ड नं॰–13 एवं 14 में, दुलाली सिंघिया और बनगमा पंचायत यानी दोनों वार्ड में, आज के डेट में भी बिजली बांस के खम्भे पर लगा हुआ है । मैं चाहूँगा कि वहां भी जांच हो और एक, खासकर दिघलबैंक में जो पदस्थापित हैं आपका एस॰डी॰ओ॰...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं।

मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, वह लगातार चार साल से एक ही जगह में एस॰डी॰ओ॰ है और बगल का प्रखंड जो टेढ़ागाछ है उसमें भी वह एस॰डी॰ओ॰ है । चार साल हो जाने के कारण वह स्थानीय नेतागिरी में लिप्त है और स्थानीय नेतागिरी में रूचि लेता है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण करें ।

मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, हम चाहेंगे कि ये चार साल से...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया ।

मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, ये चार साल से एस॰डी॰ओ॰ बना हुआ है, उसकी भी जांच की जाय कि....

उपाध्यक्ष : तौसीफ साहब, आपका समय हो गया ।

मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, एक ही स्थान पर किस आधार पर वह रह रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी ।

मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, मैं श्रवण बाबू से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसे हैं । मैं चाहूंगा कि जो बिंदु पर हमने कहा है, मनरेगा पर तो उसकी जांच करा दी जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपकी बात को गंभीरता से सुन लिये हैं।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जीविका को लेकर बड़ी–बड़ी बातें कही है और उन बातों में अगर हकीकत है तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि आखिर आज बिहार के तमाम ग्रामीण ईलाकों में महिलाएं जो हैं वह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन से और मनमाने सूद से क्यों पीड़ित है ? महोदय, गांव का गांव, परिवार का परिवार उजड़ रहा है तो सरकार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण लगाये । महोदय, दूसरी बात कहेंगे कि जीविका में इनिशियल कैपिटलाइजेशन फण्ड आई॰सी॰एफ॰ होता है जो जीविका से चलता है और ग्राम संगठनों तक पहुँचता है, उसमें एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के पैसे का गबन हुआ है जिसके बारे में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने भी जिक्र किया है और जीविका का एम॰आई॰एस॰ जो पोर्टल है या साईट है वहां पर भी दिख रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है । हम कहेंगे कि सरकार इस पर जाँच कराये और दोषी जीविका के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करे । महोदय, दुल्हीन बाजार पालीगंज विधान सभा में, वहां जीविका के बी॰पी॰एम॰ द्वारा केवल आंदोलन और हड़ताल में शामिल होने के कारण जीविका कैडरों जिनमें सुधा देवी, वीणा देवी, निशा देवी, सगुफ्ता प्रवीण, कंचन देवी तथा बैंक मित्र ममता कुमारी, नीलू कुमारी और बूक कीपर मोहन कुमार, वृदा कुमार और सुबोध कुमार, महोदय, इनको बिना कारण, बिना नोटिस के हटा दिया गया है । सी॰एल॰एफ॰ पदाधिकारियों का नकली साईन कर इनको हटाया गया है । हम सरकार से मांग करेंगे कि बी॰पी॰एम॰ पर जांच हो और जो गलत तरीके से हटाये गये हैं, उनको सरकार वापस काम पर रखवा ले और महोदय, आधा मिनट और चाहेंगे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, जीविका स्टोर प्रबंधक होती हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, आठ हजार इनको वेतनमान मिलता है, सरकार उनका वेतनमान बढ़ाये, जब सबका वेतनमान बढ़ रहा है । महोदय, यह हम सरकार से मांग करना चाहेंगे । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय बाबू । आपका एक मिनट का वक्त है । अजय बाबू, अच्छा सुझाव दीजिये ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं सुन रहा था खेमका जी का, बुजुर्ग साथी बोल रहे थे और सुनने के लिए जवाब तैयार नहीं हैं, भाग गए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माईक पर बोलिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं माईक पर ही बोल रहा हूँ । महोदय, चूंकि उन्होंने मेरा नाम कोट किया था इसलिए मैं चाहता था कि वे मेरी बातों को भी सुनें । महोदय, आज जो चर्चा हो रही है, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ और कटौती प्रस्ताव मैं इसलिए रखा हूँ कि आवास योजना से गरीबों को वर्ष 2018 से जो पहली किश्त मिली थी उसके बाद दोबारा किश्त नहीं मिल रही है, पैसे क्या हो रहे हैं । दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आवास का सर्वे कराया गया था और उसके सत्यापन के लिए गए लेकिन सत्यापन के समय जिनका सर्वे में नाम आया, उसका नाम सत्यापन की सूची में नहीं है, यह कहां गड़बड़ी हो रही है । फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई प्रावधान तो कीजिये जिनके नाम छूट गए, उनके नाम को फिर से सत्यापन के लिए स्पेशली कराया जाय ।

....क्रमशः....

टर्न–19 / अंजली / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री अजय कुमार : फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जिस जीविका के बारे में संदीप जी बोल रहे थे, 1 लाख 75 हजार जीविका दीदी सी0एम0, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी और कई स्तर से चुनाव में आपने कहा था कि उसका मानदेय हम 30 हजार करेंगे, तो इसके बारे में आज प्रोविजन इसमें कर दिया जाता वह नहीं किया गया है । फिर हम आपसे कहना चाहते हैं कि मनरेगा एक बड़ी सच्चाई है कि बिहार के अंदर मनरेगा, मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, पीठ जितना थपथपाइए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन सब का दिल कबूल करता है इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है । अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप 248 रुपया जो मजदूरी रखे हुए हैं, कहीं मजदूरी नहीं मिलती है, आप इसको 400 रुपया मजदूरी कीजिए और चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो तो इसको एग्रीकल्चर से जोड़िए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री अजय कुमार : एग्रीकल्चर से जोड़ दीजिएगा तो दाम भी मिलेगा और कृषि का भी विकास होगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता जी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका दीदी समूहों का गठन किया गया है । जीविका दीदिओं के अंदर सी0एम0 दीदी, एच0एन0एस0एम0आर0पी0, सी0एन0आर0पी0, बैंक मित्र दीदी, पशु सखी कार्य करती हैं । साथ ही, कैडर के रूप में बुककीपर, एस0जे0वाई0एम0आर0पी0, स्लैप के अध्यक्ष, सचिव एम0बी0 के कार्य करते हैं । ये प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य करते हैं लेकिन इनका मानदेय तीन हजार से नौ हजार के बीच में होता है । साथ ही, इनकी जो नियुक्ति है यह अस्थाई होती है, जिसके कारण जो जिले के अधिकारी होते हैं, डी0पी0एम0 होते हैं, ब्लॉक के बी0पी0एम0 होते हैं इनको बार–बार हटाने की धमकी देकर इनको प्रताड़ित करते हैं । मैं सदन से मांग करता हूं कि इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए और साथ ही, इनको स्थाई किया जाए, ये लोग 10–10 साल, 12–12 साल से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इनको सम्मानजनक वेतन के साथ, मानदेय के साथ इनको स्थाई किया जाए । साथ ही महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास देने की व्यवस्था है लेकिन जो गरीब भूमिहीन हैं, उनको सरकार भूमि देकर आवास योजना में शामिल करने का प्रावधान है, अधिकारियों द्वारा भूमि तो आवंटन कर दी जाती है, लेकिन उनको दखल नहीं कराया जाता है, उसमें आना–कानी करने के कारण भूमिहीन आवास योजना से वंचित रह जाते हैं । महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरत भूमिहीन गरीबों को है आवास पक्के मकान की, तो इसके लिए ठोस कदम उठाया जाए और ठोस योजना बनाई जाए कि दखल देकर भूमिहीनों को आवास योजना में शामिल किया जाए । साथ ही, महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, बस दस सेकंड दिया जाए । ऊर्जा की बात कर रहा हूं, बहुत–से गांवों में 11 हजार का हाई टेंशन जो तार है, गांव के बीचों–बीच बस्तियों से होकर गुजरा है । माननीय ऊर्जा मंत्री जी अभी नहीं हैं, हमारे यहां भानपुर हो गया, इटई हो गया, बदौरा गांव हो गया, तियारा गांव हो गया, तमाम ऐसे गांव हैं जो गांव की बस्तियों के बीचों–बीच गुजरा है इसके लिए हमलोग एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, कार्यपालक अभियंता से बात करते

हैं तो उनका कहना है कि हमारे स्तर से यह तार नहीं हटाया जा सकता है, बार–बार घटनाएं होती हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जाएं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : इसके लिए भी कोई ठोस नियम बनाया जाए । गांव के 11 हजार वोल्ट के तार को हटाया जाए । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : जानकारी के लिए माननीय सदस्यगण, सरकार बैठी हुई है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सबिलिटी होती है, कोई एक मंत्री नहीं होते हैं, तो दूसरे मंत्री आकर इस चीज को ग्रहण करते हैं । माननीय सदस्य, श्री ललन राम जी । आपके पास में 4 मिनट का वक्त है ।

श्री ललन राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है मैं कोटि–कोटि नमन करता हूं ।

आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग ने लगातार गरीब–गुरबा के लिए आवास, जीविका सहित बहुत कार्य किए हैं । 4 मिनट समय होने के कारण हम संक्षिप्त में बहुत कुछ बातें रखना चाहते हैं । महोदय, पहले भी आवास योजना का कार्य होता था, जिसमें श्मशान घाट बनाया जाता था । श्मशान घाट की जहां जमीन रहती है, जहां गरीब–गुरबा मुसहर, भुइयां, डोम, मेस्तर जहां उस आवास में जाने से भी कतराते थे, वहां आवास बनता था । हम पहले और अब में थोड़ा तुलनात्मक कर दे रहे हैं और पहले जो आवास बनाया जाता था, वह ऐसा आकार का बनाया जाता था, हमलोग के गांव देहात में लोग कहता था कि सुअर का बखोर है, बखोर कुछ लोग समझते नहीं होंगे लेकिन यह मगही भाषा है, तो सुअर जहां रहता है, वैसा हमलोग का पहले समझा जाता था, पहले की सरकार गरीब–गुरबा को किस भाव से देखती थी यह परिकल्पना करने के और कल्पना के योग्य है । महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार है । प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे ढंग से जहां गरीब–गुरबा रहते हैं, जहां अवस्थित हैं, वहां बनाया जाता है, आज माननीय नीतीश कुमार जी लगातार परिश्रम करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि वे गरीब–गुरबा के हित में हमेशा सोचते हैं और साथ ही साथ, माननीय मंत्री श्रवण बाबू को भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमेशा गरीब–गुरबा के हित में सोचते हैं । हम तो यूं हीं कहेंगे कि हमारे बीच में समाजवाद के नेता यहां बहुत बैठे हुए हैं । पहले भी हमलोग समाजवादी नेता का नाम सुनते थे डॉक्टर लोहिया जी, जननायक कर्पूरी जी और हमारे बहुत–से जो पुरोधा हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, समाजवादी नेता थे, आज भी सदन में समाजवादी नेता हैं, स्पीकर साहब भी बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी समाजवादी

नेता हैं, आदरणीय बिजेन्द्र बाबू, श्रवण बाबू बहुत ही यहां समाजवादी नेता हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को संवारने का काम किया है, सजाने का काम किया है, हमलोग गरीब–गुरबा उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं । हम त्याग की बात करना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी किस प्रकार के त्यागी हैं । जब मुख्यमंत्री के पद से वे नैतिक कारण से हटना चाह रहे थे कि लोकसभा में उनका सीट कम आया, 2 सीट कम आया तो कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफ दे देना चाहिए । हमने उस समय भी कहा था कि नैतिकता का आधार क्या, अभी तो जनादेश बिहार आपको दिया है लेकिन उन्होंने ठान लिया, माननीय नीतीश कुमार जी के त्याग की बात मैं कर रहा हूं । माननीय नीतीश कुमार जी ने त्याग किया और एक गरीब–गुरबा के बेटा, मुसहर का बेटा को माननीय मुख्यमंत्री जीतन बाबू को बनाने का काम किए, तो त्यागी पुरुष हमारे बीच आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और पहले उन लोगों को भी मौका मिला । मुख्यमंत्री जब कुछ केस में फंस गए, घोटाला में पकड़ा गए, तो वे लोग किनको बनाए, तो अपनी पत्नी को बनाए । पहले और अब में परिवर्तन देख लीजिए कि हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार की सोच, नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं, हमलोग के लिए, गरीब–गुरबा के लिए, मुसहर, भुइयां, डोम, मेस्तर के लिए बाबा दशरथ मांझी का नाम हमलोग सभी जानते हैं । पूरा बिहार नहीं, पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में विख्यात करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है । कोई नहीं जानता बाबा दशरथ मांझी को और उसमें हमारे आदरणीय नेता जीतन बाबू ने उनको लेकर पहाड़ काट रहे थे और माननीय नीतीश कुमार जी के पास आए थे, तो हम अपने नेता आदरणीय जीतन बाबू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे–ऐसे हमारे यहां महापुरुष हैं । हमारे नेता भी आदरणीय समाजवादी नेता हैं और...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री ललन राम : महोदय, थोड़ा–सा समय दिया जाए । महोदय, हमलोग की पार्टी छोटी पार्टी है, हमेशा 4 मिनट मिलता है, तो कम से कम एक–दो मिनट और बढ़ाया जाए । अभी हम तो कुछ कहे ही नहीं हैं । अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है । माननीय नीतीश कुमार जी जितना काम किए हैं हमलोग घंटो कह सकते हैं लेकिन अभी शुरू किए थे और समय खत्म हो गया । महोदय, माननीय मंत्री श्रवण बाबू जी से हम एक और आग्रह करना चाहते हैं कि आवास योजना में सभी माननीय विधायक लोगों को एक लेटर जाए कि जो अभी सर्वे चल रहा है और प्रकाशित होने के पहले सभी माननीय विधायक लोग एक बार एक नजर समीक्षा कर लें उसके बाद प्रकाशित हो, यह मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी । एक अनुरोध है कि आवास योजना ।

टर्न–20 / हेमन्त / 17.02.2026

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्री ललन राम : आवास योजना में टोला सेवक विकास...

उपाध्यक्ष : आप चार मिनट के बदले, छः मिनट बोल चुके हैं। अब आप बैठ जायें।

श्री ललन राम : बहुत कम पैसा है, मानदेय है। तो उन लोगों को आवास बनाने के लिए लेटर जाय और टोला सेवक, शिक्षा मित्र, तामिली मरकज के विकास मित्र....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी। तीन मिनट का वक्त है आपके पास।

श्री माधव आनंद : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के बजट 2026–27 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मधुबनी की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस सदन का हिस्सा बना हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनायें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री माधव आनंद : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ''भारत की आत्मा गांव में बसती है।'' जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की असली संस्कृति, परंपरा, सादगी और आत्मनिर्भरता ग्रामीण जीवन में जीवित है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में 65 से 70 प्रतिशत लोग रहते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और मैं तो अपने चुनाव के दरमियान हमेशा बोलता रहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम बिहार के लिए किये हैं, अगर उसको लिखा जाए, तो एक लंबी–चौड़ी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किये हैं। पहला काम जो उन्होंने किया कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और दूसरा, बिहार को लालटेन युग से भी बाहर निकालने का काम किया है। इन दो कामों के कारण मैं हमेशा से उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वह युग भी हम लोगों ने देखा था जिस समय लालटेन की आवश्यकता थी और वह टाइम भी देखा था जब जंगल राज था।

उपाध्यक्ष महोदय, टाइम कम है, क्योंकि तीन मिनट का ही आपने वक्त दिया है, लेकिन आज जितने काम ग्रामीण इलाकों में हुए हैं, हम सब लोगों ने उसको देखा है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो। आज वह काम दिख रहा है ग्रामीण इलाकों में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने सारे

काम हुए हैं। पहले जब हम लोग ग्रामीण इलाकों में जाते थे, तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह टोला दलित का टोला है, यह टोला सवर्ण का टोला है, लेकिन अब जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तो यह डिफरेंस बहुत कम हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम हो गया। अब गांव में जाते हैं, तो दलित टोला में भी जाते हैं, तो उनके घर में भी बिजली मिलती है, उनके यहां भी जाते हैं, तो उनके यहां भी पक्का मकान मिलता है और इसका सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। चाहे जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से, इतनी सारी महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दस हजार और दो लाख की जो योजना चलायी, मुझे लगता है कि जब दो लाख रूपया जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा, जो बिहार में महिलाओं की 50 प्रतिशत आबादी है, उसमें अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से काफी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए और कई सारी नीतियां भी बनायी हैं और नीतियों की उन्होंने समीक्षा भी की है। चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, उन्होंने कई सारी नीति बनाईं, नीति में सुधार भी हुआ और हम लोगों ने भी मांग की थी अपनी पार्टी की तरफ से, जब हम लोगों की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी कि शिक्षकों की बहाली बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से की जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है।

श्री माधव आनंद : बस एक मिनट, उपाध्यक्ष जी। मैं अपने आसन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है, बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं अपनी सरकार है, कि सर, वह वक्त आ गया है, जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पर काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े, संशोधन करते रहिए। सर, आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह जी।

श्री देवेश कांत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ग्रामीण विकास के बजट के पक्ष में मुझे बोलने का आपने समय दिया। साथ ही, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता, गोरेयाकोठी विधान सभा की उस महान जनता और देवतुल्य जनार्दन को, जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में चौथी पीढ़ी के रूप में लगातार 100 वर्ष, 1926 से 2026 तक उस परिवार को आशीर्वाद देती रही, वह जनता, जिसकी बदौलत आज एक मजबूत आवाज लेकर आपके बीच खड़ा हूं। अपने नेता और विशेष रूप से बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, माननीय उप सचेतक विनोद नारायण झा जी और जिन मंत्री जी का आज बजट है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री श्रवण कुमार जी, आप सबों के आशीर्वाद से और आपकी सहमति से आज बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन बजट के पक्ष में जब हम लोग बोलने के लिए और सुनने के लिए यहां आए थे, तो एक बड़ा दुखद क्षण हुआ और मैं वह विषय रखना चाहता हूं, ऐसे तो वह सदस्य चले गए, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी की तुलना एक ऐसे आदमी से कर दी, जो खुद सजायाफ्ता हैं और अपने इस्तीफे की बात की कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देकर, आज ग्रामीण विकास की नौकरी छोड़कर इस सदन में हूं और उस व्यक्ति के साथ हूं, जो भ्रष्टाचार का मसीहा है, जो बिहार के नाम पर एक कलंकित समय रहा है, वह दुखद क्षण आज इस सत्र में आया। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि इसकी भर्त्सना सदन में होनी चाहिए कि बाबा साहब की तुलना आप किसी से कैसे कर सकते हैं? आज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है, उनको आज हम लोग नमन करें। लेकिन तुलना आपने ऐसे व्यक्ति से कर दी, तो दुख का दिन भी है। क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं और निकल भागते हैं। ऐसे भी इनकी आदत हो गई है, कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, विषय पर चर्चा कम करेंगे, राजनीति की चर्चा करने से पहले और विषय का जवाब सुनने से पहले भाग जाएंगे। आज ग्रामीण विकास की बात करते हैं।

(व्यवधान)

आप नहीं सुनिएगा, तो आप भी जाइए। सवा चार बजने आएगा, तो आप भी चले जाइएगा, भूजा के टाइम पर।

महोदय, जब बिहार सरकार बजट रखती है, तो उसका कुछ तथ्य होता है और तथ्य सुनने की आपको आदत नहीं, आपको आदत है सिर्फ राजनीति की बात करने की। लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि जिस गांव से निकलकर आप और हम आए हैं, वह ग्राम कहां है? आज सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं, पूरे बिहार के हर विभाग में विकास दिखता है। आज गांव जाने में

लोगों को डर नहीं लगता, सड़कों में जाने में कोई कष्ट नहीं होता, रहने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, वह पूर्ण हो गई, लालटेन से छुटकारा मिल गया, जंगल राज का भय समाप्त हो गया। महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जीविका दीदी के माध्यम से हो, बिहार मजबूत हो रहा है, बिहार का विकास दिख रहा है। बिहार के गांव को जाकर देखिए। एक वह भी दिन था जब आप साइकिल से सड़क पर नहीं चल सकते थे। अब बिहार की सड़कें ऐसी हैं कि अधिकतम दूरी से भी आप पांच घंटे में पहुंच जाते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वह दिन देखा है कि पंखे तोड़ दिए गए थे, क्योंकि बिजली नहीं होती थी। आज हमारे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था होने से स्मार्ट क्लासेज चल पा रही हैं। आज हमारे पंचायती राज के माध्यम से, आप जाकर देखिए, एक छोटा सचिवालय गांव का खड़ा हो गया है। जहां कार्यपालक सहायक, रोजगार सहायक, आवास सहायक, विकास मित्र, आपको कैसे नहीं दिखता? यह बिहार सरकार का काम है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की डबल इंजन की सरकार के साथ हम जब काम करते हैं, तो गौरव महसूस होता है कि हम उस समय में विधायक बनकर आए हैं, जब बिहार विकास की तरफ उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहा है। अभी डाटा पढ़ने का विचार मैंने त्याग दिया, चूंकि डाटा लगातार पढ़ा जा रहा है और वह सत्य है, और केवल डाटा को पढ़ना ही विषय नहीं है, लेकिन हमको इस सदन को प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा कि बिहार जब विकास कर रहा है, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए।

(क्रमशः)

टर्न–21 / संगीता / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री देवेशकान्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ कि बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे सारे उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, इन्होंने जो व्यवस्था की, चर्चा होती है ग्रामीण विकास की, ग्रामीण विकास में आप जाइए स्वास्थ्य विभाग में, हमलोगों ने देखा है कि वहां डॉक्टर नहीं थे...

(व्यवधान)

आपको नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं दिखेंगे । आज के दिन में 39 मरीज से 11 हजार मरीज जा रहे हैं उस अस्पताल में । ढ़ाई सौ से ऊपर दवाएं मिल रही हैं, बिजली में 125 यूनिट फ्री होने से गरीबों के लालटेन की व्यवस्था समाप्त हो गई । आप जिस–जिस घर में जायेंगे, कोई न कोई व्यवस्था से आज माधव आनंद जी चर्चा कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने कहा कि देश की आत्मा, भारत की आत्मा, गांवों में बसती है तो आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को संतुष्टि

मिल रही होगी कि बिहार की आत्मा सही में आज गांवों में खुश है । जिस तरह से चर्चा हुई प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, कहां 20 हजार रुपये मिलते थे इंदिरा आवास के नाम पर, आज 1 लाख 20 हजार से और मनरेगा के माध्यम से और मजदूरी के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये के सहयोग से अच्छे–अच्छे सुंदर मकान बन रहे हैं । आप जाइए, आपके गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अब सुंदर हो गई कि आपके कचरे को आपके घर से उठाने के लिए, आपके दरवाजे पर साइकिल–ट्राइसाइकिल से आकर कचरा लेकर जा रहा है । तरह–तरह की व्यवस्था की गई है, कचरा प्रबंधन से लेकर, आपके यहां पानी लग जाता था, छोटी–छोटी नलियों–गलियों की व्यवस्था की गई है । ग्रामीण विकास विभाग ने अपने हर विषय को पंचायती राज के सहयोग से हो, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हो, ऊर्जा विभाग के सहयोग से हो, सारे विभागों ने मिलकर जो बिहार के गांवों को सजाया है, संवारा है, वैसे गांवों को देखने की जरूरत है । सिर्फ समीक्षा के नाम पर, सिर्फ उसकी आलोचना करना, आप बिहार के गांवों की तुलना दूसरे गांवों, प्रदेशों में भी जाकर आप करिए । एक समय था कि बिहार के गांवों में सही में डर लगता था रहने में, लालटेन जलता था, रात में लोग रोशनी में नहीं रह पाते थे, भय होता था किसके घर में कौन पहुंच जाएगा, किसके घर में कहां हत्या हो जाएगी, हम शहर को भागते रहे तो शहर सुरक्षित नहीं था और आज बिहार एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित है कि ग्रामीण विकास बिहार का सामूहिक विकास है । हर सर पर, चाहे गांवों में कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बच्चे–बच्चियों की शादी के लिए भवन बन रहे हों, चाहे दलितों के टोलों में छोटे–छोटे सामुदायिक भवन, उनके काम करने के लिए जो शेड है, जो व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था हुई है और मैं बिहार सरकार को इसके लिए बधाई भी देता हूं क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कुछ न कुछ इसपर चर्चा करते हैं अपने मंत्रियों के बीच में और बिहार को रोज कुछ न कुछ मिल रहा है । कल 25 लाख महिलाओं को, इसी ग्रामीण विकास विभाग ने 10–10 हजार रुपया पुनः देने का काम किया और फिर से 25 लाख महिलाओं को, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में, उनको रोजगार योजना के लिए वह पैसा मिला, वह भी देखने की जरूरत है । 01 करोड़ 50 लाख महिलाओं को चुनाव पूर्व यह पैसा मिला था, अब 2–2 लाख रुपया उन जीविका दीदीयों को जिस दिन मिल जाएगा और जीविका दीदी, जो व्यापार बढ़ा रही हैं, उससे बिहार की नारी शक्ति तो समृद्ध होगी ही, हर घर समृद्ध होगा, हर घर मजबूत होगा । मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री को, पूरे मंत्रिमंडल को और माननीय प्रधानमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सहयोग से डबल इंजन की सरकार मजबूती से चल रही है, वैसी सारी चीजों के लिए धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि बिहार ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास करे । आप

सबों का आशीर्वाद हमलोगों के साथ रहेगा और मैं, एक–दो विषयों को अपने माननीय, चूंकि बैठे हैं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, ये 2–3 विषय हैं जो कि हमारे क्षेत्र के विषय हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे यहां मॉडल ब्लॉक बनने जा रहा है, लेकिन हमारे दो ब्लॉकों में जो मॉडल ब्लॉक बनने जा रहा है, गोरैयाकोठी और बसंतपुर को पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की उसमें जोड़ने की आवश्यकता है । लकड़ीनवीगंज में जुट गया है, उसका टेंडर हो गया है लेकिन गोरैयाकोठी और माननीय विधायक बगल में कह रहे हैं सुगौली, तो ऐसे सारे विधायकों से सूचना ले लिया जाय । गोरैयाकोठी और बसंतपुर को भी, मॉडल ब्लॉक में कर्मचारियों और पदाधिकारियों के रहने की अच्छी व्यवस्था हो और जो भी सुगम व्यवस्था के माध्यम से...

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं माननीय सदस्य । आपका समय हो गया माननीय सदस्य ।

श्री देवेशकान्त सिंह : जो हमारे बने हैं पंचायत सरकार भवन, उसकी व्यवस्था थोड़ी और मजबूत हो जाएगी तो जो ग्रामीण हैं, उनको ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं कृपया । माननीय सदस्य श्री सुबेदार दास जी ।

श्री देवेशकान्त सिंह : और कचरा प्रबंधन की जो व्यवस्था है, उसको थोड़ा और साइंटिफिक कर देने से वह और सफल हो सकेगा, मैं यही आग्रह करते हुए पुनः बिहार सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं ।

श्री सुबेदार दास : बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय । मैं सबसे पहले गरीब–गुरबा के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं । साथ ही साथ, मखदुमपुर विधान सभा की महान जनता, कार्यकर्ता...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं ।

श्री सुबेदार दास : नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि मखदुमपुर की महान जनता ने मुझ पर विश्वास रखकर दूसरी बार सदन में भेजने का काम किया है । महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग में खास करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में जो लाभान्वितों का, जो 50 हजार रुपया दिया जाता है तो उस पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि उसमें राशि को बढ़ाया जाए । मुझे याद है कि 1998 में विशेष पैकेज जहानाबाद जिला के लिए, इंदिरा आवास के लिए आया था और उस समय में करीबन जहानाबाद जिला में करीब–करीब 2 हजार इंदिरा आवास का निर्माण हुआ था और आज जो स्थिति है, सब जीर्ण–शीर्ण अवस्था

में है, लोग उसमें नहीं रह पा रहे हैं इसलिए खास करके हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि उस पर विशेष नजर रखते हुए उसमें राशि को बढ़ाया जाए । दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में खास करके अभी जो जीरो टैग के माध्यम से लोगों का, लाभान्वितों का नाम जो जोड़ा जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है । उसमें नाम जोड़ने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है । ये सब जो है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है । साथ ही साथ, आज मनरेगा की बात उठी, बहुत से हमारे साथी, माननीय सदस्य लोगों ने बड़े विस्तारपूर्वक उस पर चर्चा करने का काम किए हैं लेकिन जो खास करके जो आपका मनरेगा में लूट–खसोट का है, 40 से 45 परसेंट उसमें कमीशन वसूला जाता है और जो कार्य होते हैं, उसमें दिन–दहाड़े लूट–खसोट किया जा रहा है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / यानपति / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री सुबेदार दास : उपाध्यक्ष महोदय, जीविका दीदी की बात है, जीविका दीदी के 10 हजार रुपया पर व्यक्ति को मिला लेकिन उसमें मात्र दो बकरी भी नहीं खरीदा जा सका । आज जो है, चूंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम भी गांव–ग्राम में निवास करते हैं, जीविका दीदी जो हमारे अगल–बगल के लोग हैं, 10 हजार रुपया मिला लेकिन उसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है इसलिए महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आपका जो शेष, जो खासकर के 1 लाख 90 हजार राशि जो जीविका दीदी को देना है तो मुख्य रूप से उसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लाभान्वितों को विशेष रूप से पहली प्राथमिकता में राशि का भुगतान किया जाय और खासकर के जो जीविका दीदी का संगठन है उसमें हर गांव में दो–तीन संगठन बनाया गया है, समूह बनाया गया है । हर गांव में 50 की संख्या में लगभग 50–40 की संख्या में महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, रोजगार की तलाश में हैं, इन सारी बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है । महोदय, हम एक बात और, ऊर्जा विभाग के प्रति, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जी जो खासकर के पूरे बिहार को लेकर, हम जहानाबाद जिला के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, विकास हुआ है, रोशनी मिल रही है लेकिन उसमें कनेक्शन मिला, जो आवास में कनेक्शन दिया है । लेकिन उसका बिल जो गरीब गुरबा अगर कनेक्शन लिये हैं तो उसका एक महीना सालभर होते–होते उसको कम से कम 50 हजार, 60 हजार, 10 हजार, 20 हजार की राशि उसमें विशेष रूप से लगाया जाता है । फ्री तो है, 125 यूनिट फ्री आप दे रहे हैं लेकिन फिर

भी जो पुराने कंज्यूमर हैं, जो कनेक्शन लिये हुए हैं उनपर वह बिल उठ रहा है । हम आपका माननीय मंत्री महोदय जी, हम एक बात चर्चा करना चाहते हैं कि एक काको प्रखंड अंतर्गत जो खासकर के जो छापा मारा जाता है विभाग के द्वारा, उसमें एक काको प्रखंड के अंतर्गत गांव है, निसरपुरा, वहां एक मिल चलाता था उसपर छापामारी किया गया जबकि उस गांव में दो फेज लाइन है । तीन फेज भी नहीं है और उसपर छापामारी करके उसको 7 लाख 16 हजार 596 रुपये किया, तब इसपर एफ0आई0आर0 और वसूली का और एफ0आई0आर0 किया गया है, इसपर भी विचार करने की जरूरत है । छापामारी मारा जाता है, विभाग से जो जाते हैं, टीम बनकर जाते हैं, तो वहां पर परिधि जो है उस तरह का है, इसपर भी ध्यान देने की जरूरत है । साथ ही सभापति महोदय, हम एक बात की और चर्चा करना चाहेंगे महोदय, कि जो खासकर के बिजली में, जहां–तहां जो गांव में है, अभी कुछ माननीय सदस्य अपनी बात को रख रहे थे कि जो खंभा या पोल के भी अधीन, जहां–तहां अभाव है, वहां पोल गड़ा हुआ है, तार जर्जर स्थिति में है उसको बदलने की जरूरत है ताकि बहुत सी ऐसी घटना घट रही है कि तार टूट जाने से मौत हो जा रही है । इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है और जो भी बिजली के प्रति है, बिजली हर जगह गांव में पहुंचा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय मंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बिजली मिल रही है लोगों को लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत है महोदय । महोदय, हम एक बात अब, हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं मद्य निषेध विभाग पर । महोदय, हम जिस समय, 2015 में जब सदस्य चुनकर आए थे तो उस समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के माननीयों ने, सभी ने एक स्वर में मुखर संकल्प लिया था कि हमलोग न ही शराब पियेंगे और न शराब छुएंगे । इस तरह का कानून बना था, लेकिन कानून तो बना, लागू भी हुआ, लागू भी है । लेकिन उसमें जो महोदय, स्थिति है पूरे क्षेत्र का, कि शराब महंगा हो गया हुजूर । शराब महंगा हो गया, पहले अगर 500 की बोतल मिलती थी, एक प्वाइंट कहिए, लेकिन 500 रुपया में मिलता था महोदय । लेकिन आज जो है होम डिलीवरी हो गयी है । होम डिलीवरी से शराब घर पर पहुंच जाती है । यह जो है, खासकर के जो है, लोगों के प्रति...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुबेदार दास : शराब पीते हैं और वह कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में चाहे टोला हो, बड़ी– बड़ी बस्ती हो, नदी के किनारे जो शराब की भट्ठी...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विशाल कुमार ।

श्री सुबेदार दास : आज भी महोदय उस तरह के हैं उसपर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है।

श्री विशाल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर मिला है । मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे उस सदन का सदस्य बनने का अवसर मिला जहां नव बिहार के विश्वकर्मा माननीय नीतीश कुमार जी और ऐसे महान नेता बिहार की गाथा लिख रहे हैं । मैं भी आज उसका एक हिस्सा बना हूं और मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी और अपनी पार्टी जिसने ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को यह अवसर दिया और नरकटिया की महान जनता को बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने अपनी आवाज बनाकर सदन में भेजने का काम किया । उपाध्यक्ष महोदय, जब तक बिहार की 50 प्रतिशत आबादी सबल और मजबूत नहीं होगी, विकसित बिहार की कल्पना करना बेमानी है । महोदय, जीविका के माध्यम से हमारी 50 प्रतिशत आबादी को सबल करने का काम हमारी सरकार कर रही है और जीविका का नाम सुनते ही लाल कपड़ा देखकर जैसे सांढ़ भड़क जाता है, वैसे ही हमारे विपक्ष के लोग भड़क जाते हैं लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी जीविका का मुख्य चार उद्देश्य है, चार हमारे काम हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्र के सामानों को बाजार उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश की क्षमता प्रदान करना, सूक्ष्म एवं कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना । महोदय, जीविका के पहले क्या स्थिति थी गांव में महिलाओं की, यह हम बताना चाहते हैं । खासकर के उनको जो जीविका का नाम सुनते भड़क जाते हैं । महोदय, गांव में जब पुरुष कमाने के लिए बाहर चला जाता था तो 200, 500, 1000 रुपये की जरूरत जब महिला को पड़ती थी और उसका पति बाहर से पैसा नहीं भेजता था तो महिला अपना जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चे का इलाज करवाती थी और अपने परिवार का खर्च चलाती थी । मौका मिला, बिहार के एक मुख्यमंत्री को मौका मिला, उन्होंने भी एक कागज पर दस्तखत किया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी को मौका मिला, इन्होंने 2006 में 6 प्रखंडों के साथ जीविका समूह का विकास किया जिसका अब विस्तार होकर के पूरे बिहार के अंदर में 11 लाख 3 हजार 627 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों 11477 यानी कि कुल 11 लाख 45 हजार 104 समूह का गठन किया । अब हम इनको कहेंगे कि हमारी जीविका दीदियों को, एक करोड़ 40 लाख लोगों को हमने लाभ पहुंचाया, फिर यह भड़क जायेंगे, फिर इनके पेट में दर्द होगा । लेकिन इसका इलाज हमारे पास नहीं है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का अभाव है, आप अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या सरकार के सामने रखें ।

श्री विशाल कुमार : मुझे 10 मिनट मिला है महोदय । तो जीविका दीदियों के माध्यम से हमने गांव की महिलाओं को सबल किया और सिर्फ जीविका ही नहीं, जब इनको मौका मिलता है तो यह अपने परिवार से बाहर सोच ही नहीं पाते, राज्यसभा बेटी जायेगी, लोकसभा बेटी जायेगी और हमारे नेता को मौका मिलता है तो उन्होंने शुरूआत की साइकिल योजना, कहां से...

(क्रमशः)

टर्न–23 / मुकुल / 17.02.2026

क्रमशः

श्री विशाल कुमार : महिला कैसे हमसे जुड़ी और कैसे हमारे साथ आयी, हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि साइकिल एक योजना नहीं थी, यह महिलाओं / लड़कियों को पंख दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, साइकिल मिला तो जहां एक के अनुपात में 10 लड़के मैट्रिक उत्तीर्ण होते थे 2005 के पहले और 2005 तक, अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, यह 10 गुना का फर्क साइकिल योजना ने मिटाया । महोदय, इस योजना से सिर्फ यही नहीं हुआ, इस योजना से यह हुआ कि अब बेटे और बेटी का फर्क मिट गया । अब लड़कियां उसी साइकिल से स्कूल भी जाती हैं, ट्यूशन भी जाती हैं और शाम में अपने घर का सामान भी खरीदकर के परिवार में लेकर के आती हैं, इसलिए मां जो है या पिता जो है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना सुझाव ग्रामीण विकास पर रखें, समय का अभाव है ।

श्री विशाल कुमार : अब सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है । महोदय, मैं उसी विषय पर हूं चूंकि महिलाओं के लिए सिर्फ जीविका ही नहीं है, हमारी सरकार ने चौथी क्लास में, जब यह सर्वे करवाया मुख्यमंत्री जी ने कि लड़कियां ड्रॉप–आउट क्यों हो रही हैं तो पता चला कि गरीब की बेटी पोशाक के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती है तो मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना देकर के गरीब की बेटियों को स्कूल भेजने का काम किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया और जिसको कुछ नहीं दिया, जिसके लिए कुछ नहीं कर सकें उसके लिए जीविका लाए और जीविका के माध्यम से उनको स्वरोजगार देने का काम किया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें, समय का अभाव ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मुझे 10 मिनट का समय मिला है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का कुछ अभाव है अभी आसन को, आप अपने भाषण को कन्क्लूड करें ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं । ऊर्जा के क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे कि हमलोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, हमलोग वह दौर भी देखे थे और यह दौर भी देख रहे हैं, हमलोग ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने उनका

भी दौर देखा था 1990 से 2005 तक और यह दौर भी हमलोग देख रहे हैं । एग्जीविशन रोड जैसे पटना के पॉस इलाके में 8–8 घंटे बिजली नहीं रहती थी, गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए और आज गांव में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहती है महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को समय का अभाव है ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मैं सुझाव दूंगा अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि आपने बहुत काम किया है, आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, आपने बिहार से लालटेन को समाप्त कर दिया है आज किसी घर में लालटेन खोजने से भी नहीं मिलता है । महोदय, हम आग्रह करेंगे कि बिजली विभाग में एक समस्या है कि आम उपभोक्ता जब ऑनलाइन अपना आवेदन कर देता है उसके बाद उसके हाथ में कोई काम नहीं रहता है फिर विभाग का काम है उसको मीटर लगाकर के देना, लेकिन विभाग अगर किसी कारण से मीटर नहीं लगाता है तो चूंकि अब बिहार के लोग बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं इसलिए समय निश्चित किया जाए कि एक सर्टेन टाइम में उनको मीटर उपलब्ध हो और मीटर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, बल्कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो जो उनको समय से मीटर उपलब्ध नहीं कराते हैं, यह एक मेरी मांग है, आपसे आग्रह है कि आप इसको करवाने का काम कीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि हमारा भी दौर आयेगा तो हम उनको कहना चाहते हैं कि जो बीत गए वह दौर न आयेगा और बिहार में एन0डी0ए0 के सिवा कोई और न आयेगा । बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रकाश चंद्र जी । आप दो मिनट में अपनी बात को रखें, गागर में सागर भरें ।

श्री प्रकाश चंद्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । मैं आज इस सदन में ओबरा की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं आदरणीय चिराग पासवान जी का हमारे नेता का जिन्होंने मुझे इस सदन का सदस्य बनने का मौका दिया । पद्म विभूषण राम विलास पासवान जी को स्मरण करते हुए, मैं नमन करता हूं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का जिनकी 38वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है । आज बिहार बदल रहा है और ग्रामीण विकास विभाग उस बदलाव का सबसे सशक्त इंजन है । मैं कुछ ठोस तथ्यों के साथ इस कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं । महोदय, इस बार सरकार ने

ग्रामीण विकास के लिए 23,701.18 करोड़ का ऐतिहासिक बजट रखा है, पिछले साल के 16,043 करोड़ से लगभग 47 परसेंट ज्यादा है । यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सरकार के संकल्प को जाहिर करता है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं हमारी एन0डी0ए0 गठबंधन सरकार द्वारा सोमवार को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ भेजा गया । संकल्प सभागार से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला के खाते में 10 हजार की राशि भेजी गयी, अब तक कुल 1.81 करोड़ लाभुकों के खाते में 18,100 करोड़ हस्तांतरित किये गये हैं इससे पहले 1.56 करोड़ के खाते में 15,600 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं । इस बजट में सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2–2 लाख की आर्थिक सहायता देने का जो संकल्प लिया है वह क्रांतिकारी है। अब जीविका दीदियां इतनी आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो गयी हैं कि पुरुष अब उन पर अपने निर्णय नहीं थोंपते, बल्कि उनकी सहमति से कार्य करते हैं और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा हो नहीं सकता ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण संक्षिप्त करें, समय का अभाव है ।

श्री प्रकाश चंद्र : महोदय, हम अपने भाषण को संक्षिप्त करते हुए यह कहना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जब मैं चुनाव के दौरान घूमा करता था तो एक तरफ हम ओ0डी0एफ0 कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांव की स्थिति बदतर है जहां भी दलित समुदाय के लोग रहते हैं उन सब इलाकों में जरूरत है कि सरकार एक बार शौचालय की ऑडिट कराए किसी थर्ड पार्टी से ताकि अगर कहीं शौचालय बना है या राशि दी गयी है और शौचालय नहीं बनाया गया है तो उसके बारे में सरकार को पता चल सके कि स्थिति क्या है और दूसरी तरफ अगर ओ0डी0एफ0 होने के बावजूद लोग शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार जागरूकता का कार्यक्रम चलाए । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, श्री सुजीत कुमार जी । आप तीन मिनट में अपनी बात को रखें ।

श्री सुजीत कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है साथ ही, मिथिलांचल और बिहार के सारे लोग खास करके हमारे क्षेत्र गोड़ाबौराम के सारे जनता–जनार्दन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार भी देता हूं जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद की बदौलत मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास विभाग के बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं स्पष्ट कर दूं कि कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष

महोदय, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था बिहार के गांवों के लिए । गांव आत्मनिर्भर हो, गांव में संपन्नता आये और गांव में एक समरसता का माहौल बना रहे, लेकिन उस समय के विदेश के पढ़े हुए जो नेतागण थे, उन्होंने औद्योगीकरण और शहरीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया, महात्मा गांधी के टाइटिल को तो हथिया लिया गया लेकिन उनके विचारों को दरकिनार करके शहरीकरण और औद्योगीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया, ग्रामीण विकास के काम को पूरी तरह लगभग छोड़ दिया गया । बिहार में भी उन्हीं लोगों की सरकार थी, कुछ बहुत ज्यादा काम तो हुआ नहीं । 1990 में बिहार में एक सपना जगा था, जब बिहार के एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग मुखिया बने थे, लेकिन उन्होंने भी अपना विकास करना ज्यादा जरूरी समझा और गांव का विकास नहीं किये, बल्कि पूरे बिहार को जंगल राज के अंधकारमयी युग में झोंक दिया था । महोदय, हमलोग जो बिहार में 2005 के बाद विकास की गति देख रहे हैं और खास करके अपने गांव में जो हमलोग विकास देख रहे हैं, हम सब लोग कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों । गांवों की स्थिति जो 2005 में थी और 2025 आते–आते जो गांवों के परिवेश में बदलाव आया वह अतुल्य है । महोदय, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुखिया, हमारे नये बिहार के विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी इन लोगों के द्वारा कुछ कार्य शुरू किया गया है, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । माननीय महोदय, सबसे पहले हमारे यहां पर गांव को एक स्वच्छ वातावरण मिले इसके लिए इस सरकार ने कार्य किया । कई सारे मिशन लाये गए, एक लोहिया स्वच्छता मिशन था साथ में महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में इज्जत घर या शौचालय का भी निर्माण किया गया और लाखों की संख्या में किया गया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार की सोच की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उस योजना से कुछ लोग जो छुटे हुए थे, जो वंचित रह गये थे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

टर्न–24 / सुरज / 17.02.2026

श्री सुजीत कुमार : अभी फिर से उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है । उनको फिर से पैसे दिये जायेंगे ताकि वे भी अपने यहां पर शौचालय का निर्माण करवा सकें । हमारे यहां पर...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, मुझे लगता है 10 मिनट का समय है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन को समय का अभाव है ।

श्री सुजीत कुमार : जी महोदय, जल्दी खत्म करूंगा ।

उपाध्यक्ष : कम समय में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सुजीत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को और देश में एक नई नीति लायी गयी, एक नया कानून बनाया गया विकसित भारत जी राम जी योजना । हाल–फिलहाल के दिनों में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं । वह यह नहीं समझ रहे हैं कि पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, अब 125 दिन...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाएं ।

श्री सुजीत कुमार : रोजगार का गारंटी मिल रहा है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री सुजीत कुमार : 100 ज्यादा है या 125 ज्यादा है । यह भी कुछ लोग समझने में गलती कर रहे हैं...

उपाध्यक्ष : आप आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, इस योजना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे लोग शायद ग्रामीण परिवेश में नहीं रहे हैं...

उपाध्यक्ष : अब बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री सुजीत कुमार : कोलंबों के गलियों में और थाइलैंड के बाजारों और गलियों में घुमने वाले लोग इस योजना का ही विरोध कर रहे हैं, गांव के किसी लोग को हमलोग नहीं देख रहे हैं कि हमारी योजनाओं का किसी तरह से विरोध कर रहे हैं...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री सुजीत कुमार : जी महोदय । मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से । हमारे क्षेत्र में दो जगह पर गौड़ाबौराम ब्लॉक और कीरतपुर ब्लॉक में अभी तक भवन नहीं बना है । कीरतपुर ब्लॉक में ब्लॉक का जो भवन निर्माण होने का जो पारित हुआ है, वह एक बहुत ही एक लो–लाईन लैंड में है...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी नोट कर रहे हैं, आपकी समस्या को लिख रहे हैं ।

श्री सुजीत कुमार : आशा करते हैं कि भवन को ग्राउंड लेवल से काफी ऊंचा करके...

उपाध्यक्ष : अब बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री सुजीत कुमार : स्टील्थ पर बनाया जाए और गौड़ाबौराम में...

उपाध्यक्ष : आसन को समय का आज अभाव है ।

श्री सुजीत कुमार : जी । गौड़बौराम ब्लॉक में जहां पर सरकार जमीन उपलब्ध है, वहां पर बनवाया जाए न कि सरकार का पैसा प्राईवेट लोगों से जमीन खरीद करके न बनवाया जाए । उसका सरकारी जमीन उपलब्ध है 52 बीघा का, वहीं बनवाया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बैठ जाएं ।

श्री सुजीत कुमार : धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : अरूण बाबू ग्रामीण विकास, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आज बहस चल रही है और मुख्य विपक्षी दल के एक भी सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं । माननीय सदस्य सदन की अपनी मर्यादायें हैं । ग्रामीण विकास और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आज बहस चल रही है । माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर जी । तीन मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री सुधांशु शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस अद्भुत बजट के लिये धन्यवाद देता हूं । साथ ही मैं श्री श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी, माननीय ऊर्जा विभाग, मद्य निषेध तथा वाणिज्यकर विभाग को भी धन्यवाद देता हूं । जिनके अथक प्रयास से ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा, मद्य निषेध तथा वाणिज्यकर विभाग द्वारा एक मजबूत बजट सदन में रखा गया ।

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग और नारी शक्ति जीविका दीदी के विषय पर बात करना मेरे लिये गर्व की बात है । जीविका दीदीयां जो पटना से लेकर हर पंचायत तक लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, इस विभाग की सबसे बड़ी पूंजी है । जीविका दीदी ग्रामीण विकास की धुरी है, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है । इस बजट से जीविका कार्यक्रम को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई नीति मिलेगी । जिससे बिहार का समावेशी विकास होगा । जीविका बिहार के 01 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है । जीविका द्वारा सामाजिक समावेशन के लिये उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं तथा वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी को मिलाकर स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 11 लाख 45 हजार 104 है । जीविका द्वारा वित्तीय समावेश के लिये अद्भुत कदम उठाये गये हैं तथा अब तक विभिन्न बैकों द्वारा 10 लाख 53 हजार स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोले गये हैं । कुल मिलाकर 62 हजार 628 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है । दीदी की रसोईयां के माध्यम से अस्पतालों, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । हमारे जीविका दीदीयों के द्वारा सिलाई, हस्तलेख, मधुबनी पेंटिंग और लघु उद्योग जैसे–आचार, पापड़, सत्तु उत्पादन से जुड़ी दीदीयां न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं बल्कि रूढ़ियों को तोड़कर समाज में पहचान बना रही हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री सुधांशु शेखर : बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद जी । तीन मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 2026–27 के आय–व्यय के ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं पेंशन के मांग के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । लेकिन मात्र आप तीन मिनट दिये हैं और कहा गया है कि अंत भला तो सब भला । मतलब अंत वाले वक्ता पर समय–सीमा समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, यह मेरा निवेदन होगा । महोदय, आज गरीबों के मसीहा, लाचारों, बेचारों के जुबान....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखे ं।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि भी है, जिनको हमलोगों की वर्षों से मांग रही थी भारत रत्न उपाधि देने की । लेकिन पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हमारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये और एन0डी0ए0 सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दिया । उस भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं । महोदय, जब भी मैं ग्रामीण विकास की बात करता हूं तो हमें अपने पुरखें याद आते हैं । महात्मा गांधी उनका सपनों का भारत, वह भारत कैसा बने, उसका सपना देखते थे और उनका सपना था कि ग्राम स्वराज्य बने....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : ग्राम स्वराज्य, जो गांव में रहने वाले लोग अपने विकास की नीतियां खुद बनायें और हमें कहते हुये हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पंचायत सरकार भवन बने हैं, जिस तरह से पंचायत सरकार का गठन किया है इन्होंने और पंचायती राज व्यवस्था में जो पुरूष प्रधान समाज की पहले की जो सोच थी कि सिर्फ पुरूष कमायेगा, महिला बैठकर सिर्फ घर में रहेगी इस सोच को बदला और देश के विकास, समाज के विकास में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया है ग्राम स्वराज्य के माध्यम से और उन्होंने पचास प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान किया है । इतना ही नहीं आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबन बने, इसके लिये भी ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है । इसके लिये हमारे कई पुरखों ने सपना देखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी सपना देखा था अंत्योदय का, कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो । हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भी सपना देखा था, उनका भी मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा, गांव के लोग यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं

होंगे तो हम विकसित भारत और विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं । हमारे डॉ0 लोहिया भी कहते थे, सपना देखे थे कि जब तक ग्राम स्वच्छ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं. ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से आग्रह है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : और निश्चित रूप से ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहे हैं निश्चित रूप से हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था ।

(क्रमशः)

टर्न–25 / धिरेन्द्र / 17.02.2026

....क्रमशः....

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, आने वाले दिनों में और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2047 का जो विकसित भारत बनाने का और हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार को बनाने का संकल्प लिये हैं निश्चित रूप से ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, इसको पूरा करने का काम करेगी । महोदय, हम विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं चूंकि आपने बहुत कम समय दिया है, डाटा तो बहुत है, मैं गिनाने लगूं तो लगता है कि घंटों लगेंगे । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ । महोदय, इसी के साथ और कई विभाग हैं, हमारा जो मनरेगा है, मनरेगा में मात्र 100 दिनों के काम की गारंटी देता था, उसकी जगह पर जी–राम–जी योजना लायी गयी है जो 125 दिनों के काम की गारंटी देता है और इतना ही नहीं जो किसानों के गांव में रबी के समय खरीफ फसल के समय जो काम होता है उससे वंचित न हो, उसका काम बाधित न हो, उसके लिए जी–राम–जी में 60 दिन अलग से व्यवस्था की गई है । उन कामों को छोड़ कर यदि 60 दिन 125 में जोड़ा जाता है गांव के किसानों के काम के लिए तो सोचिये 185 दिनों की गारंटी होती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि केन्द्र सरकार के सामने प्रस्ताव जाना चाहिए कि जी–राम–जी को यदि किसानी से जोड़ दिया जाय तो निश्चित रूप से 365 दिनों के काम की गारंटी मजदूरों को मिल जायेगी और गांव आत्मनिर्भर बनेगा । महोदय, यह प्रस्ताव जाना चाहिए । महोदय, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं ऊर्जा विभाग की तरफ भी आना चाहता हूँ, मैंने देखा है उस दौर को भी कि जब बिहार में बिजली क्या होती थी, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि बिजली कैसी होती है । जब हम 1990–91 में देखते हैं तो समृद्ध बिहार था, उस समय मात्र 1724 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति होती थी । महोदय, आज जब बिहार बंट गया और जब उसी समय बिहार बंटने का आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा

के लोग चला रहे थे, झारखंड वाले लोग चला रहे थे तो हमको लगता था कि जो भी पॉवर प्लांट हैं सब झारखंड में है । कांटी और बरौनी में दो पॉवर प्लांट है वह भी मरणाशन पर है यदि बिहार बंट जायेगा तो क्या होगा लेकिन उस समय के चर्चित नेता लालू जी कहते थे कि बिहार मेरे सीने पर बंटेगा, मेरी छाती पर बंटेगा तो थोड़ा राहत महसूस हुआ था लेकिन बाद के दिनों में वर्ष 2000 में बिहार बंट गया और उस समय के नेता लालू जी के छाती पर एक खरोंच तक नहीं आयी, महोदय, वह हमारा बंटा हुआ बिहार, आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी को मिला और....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, लालू प्रसाद जी के ही पहल पर दोनों हाउस लोवर हाउस और अपर हाउस, दोनों हाउस में प्रस्ताव पास कराया गया था बिहार बंटवारे को लेकर, मैं जानता हूँ महोदय, दोनों हाउस लालू जी के पहल पर उस समय आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी और दोनों हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था । इसके बाद जब बिहार बंटा तो जो दो पॉवर प्रोजेक्ट थे वह भी बंद थे, वहां से बिहार चला है और....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, वर्ष 2005–06 में मात्र 700 से 750 मेगावॉट की बिजली आपूर्ति होती थी बिहार में और आज के डेट में सिर्फ पटना जैसे महानगर में 500 मेगावॉट की बिजली रोज आपूर्ति हो रही है । उस समय पूरे बिहार में 750 मेगावॉट बिजली और आज सिर्फ पटना जैसे शहरों में 500 मेगावॉट बिजली है और आज पूरे बिहार में करीब–करीब 8,850 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति हो रही है और अगले साल तक करीब 09 हजार, 9.5 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा और बिहार को मिलेगा और इतना ही नहीं थर्मल पॉवर से तो बिजली मिल ही रही है, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हम सोलर प्लांट से भी काम कर रहे हैं, सोलर के क्षेत्रों में भी हमारी सरकार काम कर रही है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, सरकारी भवनों पर तो सोलर प्लांट लगाये जा रहे हैं, सोलर पैनल लगाये जा रहे हैं....

उपाध्यक्ष : उपेन्द्र बाबू, आसन ग्रहण करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, निजी भवनों में भी लगाये जा रहे हैं और जो हमारे विरोधी हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बिनीता मेहता ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बिनीता जी, आप एक मिनट रूक जाइये ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सूर्य जब पृथ्वी पर निकलता है तो प्रकाश देने में कोई भेद–भाव नहीं करता है, हर जगह वह

रौशनी देता है । आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी भी जब बिहार में बिजली आयी तो चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, सभी के घरों में रौशनी फैलाने का काम किये हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, इसी के साथ मैं मांग के समर्थन में अपनी बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ । जय हिंद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्या श्रीमती बिनीता मेहता जी ।

श्रीमती बिनीता मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस सदन के माध्यम से मुझे ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है । मैं अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ एवं पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी सहृदय नमन करती हूँ । साथ ही मैं गोविंदपुर विधान सभा क्षेत्र की भगवानरूपी जनता को नमन और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया । मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और मेरे पार्टी के विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी को ग्रामीण विकास विभाग के जनकल्याणकारी बजट के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ । जिनके शासनकाल में गांवों की पहचान टूटी सड़कें, अंधेरे घरों और पलायन से होती थी । आज वही लोग विकास की परिभाषा पढ़ा रहे हैं । मैं विपक्ष से सीधा प्रश्न पूछती हूँ कि क्या यह सत्य नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिला । क्या यह सत्य नहीं कि मनरेगा के तहत करोड़ों मानव दिवस सृजित हुए है और मजदूरों का पैसा सीधे खाते में गया है । क्या यह सत्य नहीं कि जीविका से जुड़ी एक करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक ताकत मिली है । विपक्ष की राजनीति विकास रोको, भ्रम फैलाओं पर चलती है । जिन्होंने सालों तक दिया नहीं उजाला वे आज चिरागों की लौ पर सवाल उठाते हैं । जिनके राज में गांव था बदहाल वे हमसे विकास का हिसाब मांगते हैं । विपक्ष कहता है योजनाओं की कमी है । मैं कहती हूँ आईये सुझाव दीजिये लेकिन विकास रोकने की राजनीति मत कीजिये । सिर्फ आलोचना से इतिहास नहीं बदलती है, इरादे और हिम्मत से हालात बदलते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं । आसन को समय का अभाव है ।

श्रीमती बिनीता मेहता : महोदय, ग्रामीण विकास की अनुदान राशि पर सवाल उठाना दरअसल गांव के गरीब पर सवाल उठाना है । हमारे विधान सभा में पर्यटक की अपार जनसंभावनाएं हैं, जहां लोकनायक जय प्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे थे तो सोखोदेवरा जंगल में वर्षों तक....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका समय हो गया है ।

श्रीमती बिनीता मेहता : महोदय, एक मिनट । पहली बार बोल रही हूँ, बोलने का मौका दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

श्रीमती बिनीता मेहता : महोदय, सोखोदेवरा जंगल में वर्षों तक एक बड़ा चट्टान पर बैठे थे । वह चट्टान अभी भी जे॰पी॰ चट्टान के नाम से जाना जाता है । वहीं सिपुर जलाशय डैम है अगर वहां गुजरात में स्थापित लौह पुरुष सरदार पटेल की तरह लोकनायक जय प्रकाश नारायण की विशाल प्रतिमा की स्थापना होती है तो लोकनायक जय प्रकाश नारायण की सच्ची श्रद्धांजलि होगी । महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगी कुछ पंक्तियां–

जहां मिट्टी में पसीना मिलकर सोना बन जाता है,
वही गांव हमारे देश का कोना–कोना जगमगाता है ।
जो विकास की रोशनी हर घर तक पहुँचाए,
वही सच्चा जनसेवक कहलाता है ।

धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार मंडल जी । तीन मिनट में अपनी बात रखें।

श्री राजेश कुमार मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत आभार । हम आभार प्रकट करना चाहते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय मंत्री बिजली विभाग आदरणीय श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी और मुख्य सचेतक ग्रामीण विकास विभाग के आदरणीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी का, इस विधान सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण । आपलोगों का अभिनंदन, चंदन, वंदन और प्रणाम । साथ में, दरभंगा ग्रामीण विधान सभा के जनता मालिक, मतदाता मालिक उनका भी इस सदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, चंदन, वंदन और प्रणाम ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष जी आ गए । महोदय, आज हम ग्रामीण विकास विभाग के पक्ष में सरकार की ओर से अपनी बात रखने के लिए तो खड़ा हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि बात पर तो विवाद भी होती है जो विपक्ष का काम है लेकिन विपक्ष, प्रतिपक्ष के नेता सहित सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए हैं, ये लोग आते ही अपनी बात कुछ रखकर और बिना कुछ कहे सदन से बाहर हो जाते हैं । यह इस मंथ का सबसे बड़ा बजट सत्र चल रहा है, फरवरी माह और इस पूरे माह में

देखा गया है कि विपक्ष सदन में नहीं रहते हैं, इनका काम है सिर्फ विवाद करना और निकल जाना ।

(व्यवधान)

हम बोलेंगे, बात पर अगर विवाद होता है तब बजट का महत्व समझा जाता है और हमलोग जो हैं ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो सिर्फ काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं ।

...क्रमशः....

टर्न–26 / अंजली / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री राजेश कुमार मंडल : महोदय, हम कहना चाहेंगे कि वर्ष 2005 कि जहां चर्चा होती है सदन में, तो कुछ लोग ऐसे भड़कते हैं जिससे सभी लोग अवगत होंगे । बहुत सदस्य कहे हैं, कभी–कभी हमलोग सड़क पर देखते हैं कोई मुसाफिर लाल सूट–बूट में सड़क के किनारे चलते हैं और उनको नंदी बाबा खदेड़ना शुरू करते हैं, उसी तरह 2005 की जहां चर्चा होती है सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता हों, सदस्य हों, सभी भड़क जाते हैं । यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार है । यह बिहारियों का बिहार है, यह आपका बिहार है, यह मेरा बिहार है । हमलोग बिहारियों के लिए काम करने आते हैं, न कि अपने परिवार के लिए काम करने आते हैं । शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ग्रामीण विकास विभाग की बात हो, वर्ष 2006 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विश्व बैंक से अनुदान लेकर जीविका समूह का गठन, सहायता समूह का गठन जिसका नाम जीविका रखा गया । हुजूर, हम बताना चाहेंगे कि उस समय कमजोर वर्ग की परिवार की महिला चाहे वह अतिपिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते थे, वे उस गांव के सूदखोर, ब्याजखोर के यहां जाकर अपना जमीन, अपना बर्त्तन, अपना गहना रखकर उधार लेते थे, ब्याज दर होता था दस परसेंट, पंद्रह परसेंट लेकिन जब से जीविका समूह का गठन हुआ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस दिन से वही परिवार एक प्रतिशत ब्याज पर, आसान किस्त पर पैसा लिया करते थे और आज उसका रिजल्ट यह है कि हर परिवार में...

अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार मंडल : उसकी संख्या, जिनके ब्याज तले दबे हुए रहते थे, वह आज मुक्त हैं । उनके पास सेविंग है । आज मुख्यमंत्री जी दस हजार रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं और वैसे उद्यमी, घरेलू महिला जिनका रोजगार आगे बढ़ रहा है उनको 2 लाख रुपया और देंगे । करीब 25 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपया दिया गया, पूरा बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया देख रहा

है। महोदय, अगर नारी सशक्तिकरण की बात होगी, तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में...,

अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार मंडल : बिहार पहला नंबर पर आएगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी ''न भूतो न भविष्यति'', न कोई किया था, न कोई करेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया । इसी के साथ पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन–मंदन और प्रणाम करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज ग्रामीण विकास विभाग का बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है, इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं । महोदय, कुल 21 माननीय सदस्यों ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं । लेकिन जो इनके विचार प्रस्तुत हुए हैं, सिर्फ सदन में अपनी बातों को घुमाते रहे, विपक्ष की तरफ से जो मुझे आशा थी, उम्मीद थी, उसके अनुरूप ये लोग कुछ नहीं कह पाए, कोई सुझाव नहीं रख पाए, सिर्फ और सिर्फ बातों को घुमाते रहे और घुमाते–घुमाते तो एक–एक करके चले गए । यह पहली बार देख रहे हैं, एक नई परंपरा शुरू हुई है । पहले तो देखते थे कि अंसतुष्ट हो जाते थे तब चले जाते थे, इस बार तो पता ही नहीं चला कि संतुष्ट हैं कि अंसतुष्ट हैं, तो नई परंपरा की शुरूआत मुख्य विपक्ष की तरफ से किया गया है महोदय और बाकी अजय बाबू, सौरभ जी ने कुछ सुझाव रखा है । हमको तो ताज्जुब तब होता है, अजय बाबू पिछली बार भी मेंबर थे, इस सदन के सदस्य थे महोदय और ये प्रधानमंत्री योजना का सवाल उठा रहे हैं कि बहुत–से गरीब लोग छूटे हुए हैं । हम आपके माध्यम से सदन को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि मैंने पत्र लिखा था सभी विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो बिहार से हैं उनको भी पत्र मैंने लिखा था और नीचे जिला परिषद और प्रमुख को भी मैंने पत्र लिखा था और आग्रह किया था कि सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे का काम जो शुरू हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें आप अपनी दिलचस्पी दिखाइए, तो अगर माननीय सदस्य दिलचस्पी दिखाए रहते और गरीबों से इनका बहुत लगाव रहता है, धनी और धरती बंटकर रहेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अजय बाबू, बैठ जाइए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

''धनी और धरती बंटकर रहेगा,
अपना–अपना छोड़कर,
लाल झंडा गाड़कर,
धरती कब्जा करने की बात करते हैं''

अगर गरीबों से लगाव रहता तो आज ये सवाल नहीं उठाते, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 20 लाख ऐसे लोग हैं इस राज्य में जिन्होंने खुद ऑनलाइन आवेदन दिया है और कहा है कि हमको आवास चाहिए, तो 20 लाख लोग जब आवास मांग रहे हैं और सदन के माननीय सदस्य को इस बात की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालत है, इसको समझना चाहिए । महोदय, और भी माननीय सदस्यों ने जो इस सदन के सदस्य हैं, उस समय नहीं थे, उन लोगों ने भी यह सवाल उठाया है, तो पूरे बिहार में 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार लोगों का नाम जो नए सर्वे हमने कराया है भारत सरकार के निर्देश पर 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार लोगों का नाम, आवास सब तैयार है, भारत सरकार जैसे ही हमको स्वीकृति देगी, उन आवासों का निर्माण हम बिहार में करवाएंगे । महोदय, आज यह कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं और कटौती प्रस्ताव पेश तो कर देते हैं, कागज में कहीं से मिल जाता है दस्तख्त करके दे देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, तो इनको बात को सुननी चाहिए और इनके जो सार्थक सुझाव होंगे उस सुझाव को भी हम अमल करेंगे । ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात सुनकर के अनसुनी करेंगे, पहले भी मैं सुनता रहा हूं और हमको जब–जब मौका मिलता है तो सत्ता पक्ष की बात सुनते हैं और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों की बात सुनता हूं । लेकिन माननीय सदस्य को यह बताना चाहिए था कटौती प्रस्ताव में कि ग्रामीण विकास की कौन–सी योजना को बंद कर दिया जाए जिसके लिए कटौती लाए हैं, तब हम उस पर विचार करते, तो संपूर्ण योजना पर कटौती करना चाहते हैं, अगर कोई खराब योजना है, कोई गड़बड़ी की योजना है, तो सुझाव देना चाहिए कि उस पर हमको यह सुझाव देते तो हम उस पर अमल करते । महोदय, जीविका के बारे में विपक्ष के लोग रहते हैं तो थोड़ा और अच्छे ढंग से सुनते भी और जानकारी भी इनको होती । विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं इनको महिलाओं से बड़ी दिक्कत हो रही है । राज्य में जब हम इनकी तरक्की की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, उनको सहनीय नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना चलाई जिसका नाम है महिला रोजगार योजना और महिला रोजगार योजना जब हमलोगों ने शुरू की तो ये लोग भी गांव–गांव घूमने लगे । पहले तो कम घूमते होंगे, पहले तो ऐसे ही झांसा देकर निकलना चाहते होंगे कि

लेकिन जब धरातल पर हमलोगों ने इसको उतारा, तब ये गांव में घूसें और अपने लोगों को भी लगाया और कुछ लोग तो फॉर्म भी भरवा रहे थे, कुछ लोग गारंटी कार्ड भी बांट रहे थे, तो गांरटी कार्ड वाले को भी बिहार की जनता ने सबक सिखाया और जो 200–300 फॉर्म भरवा रहे थे और हमारे विधायक, संदीप जी बैठे हैं इनको तो देख रहे थे माईक लगाकर गाड़ी में, मैं गया था पालीगंज तो गाड़ी में भोंगा लगाकर क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकार लगाकर प्रचार कर रहे थे, लग रहा था कि लूट सकें सो लूट । यानी छूट जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी । इन्होंने पूरा प्रचार भी किया, इनको धन्यवाद देते हैं कि योजनाओं का प्रचार कर रहे थे लेकिन जो हमलोगों ने काम किया, कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टी बिहार के, एक तो कांग्रेस के लोग, पता नहीं हैं कि चले गए और दूसरे आर0जे0डी0 के लोग, ये लोग फॉर्म भरवा रहे थे, कह रहे थे कि हम इसको 30 हजार रुपया देंगे, कोई कह रहे थे ढाई हजार देंगे और महिलाओं को वहां पर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे, कहते थे कि यह जो दस हजार मिला है यह पैसा वापस हो जाएगा, तो इन लोगों से महिला कम चालाक है हुजूर, महिलाओं ने क्या किया कि सब पैसा बैंक से खींच लिया, निकाल लिया और कहा कि इन लोगों का असत्य वायदा है, यह असत्य वायदा इनका चलने नहीं देंगे, बेनकाब करेंगे ।

(क्रमशः)

टर्न–27 / पुलकित / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, दस–दस हजार रुपया निकाल लिया । बैंक में भारी भीड़, बैंक वाले अलग परेशान । महोदय, दूसरा जब पैसा निकल गया तब दूसरी बात ये लोग क्या प्रचार किये ? ये लोग कहे कि इस पर अब सूद लगेगा तो ये सूद वाली बात बोलकर के दिग्भ्रमित करने का काम किया और हमारी महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये इन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पैसा वसूल लिया फॉर्म भरने के नाम पर । महोदय, अब तो इनको लोग खोज रहे हैं । दूसरी बात बोलते थे कि अब ये आगे पैसा देने वाले नहीं है । अभी सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि उनको कब मिलेगा ? अभी तो कल 25 लाख महिलाओं को दस–दस हजार रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे उप–मुख्यमंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में उनके खाते में भेजा गया है । महोदय, और भी जो छूटे हुए लोग हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे । सब के खाते में, जो–जो आवेदन दिए हैं और जिनका काम सही लगेगा, सब के खाते में दस–दस हजार रुपया देने का काम अभी तत्काल कर रहे हैं ।

महोदय, उसके आगे भी चलेंगे । ये लोग तो पूरा भड़काए । ये लोग कहे कि आगे मिलने वाला नहीं है और कई नेता, कई अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पर बात चलती रहती है, छपती रहती है । कहते हैं कि आगे नहीं मिलेगा, हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं । अखबार में, टेलीविजन में आंदोलन करिएगा ? धरातल पर आंदोलन करने जाइएगा, तो गांव की महिलाएं आप लोगों को खोज रही हैं । जहां भेटा जाइएगा, तो ऐसी दवाई करेगी कि फिर लौट के गांव जाने का हिम्मत आपको नहीं होगा । असत्य और झूठ का सहारा लेकर किसी को गुमराह करना ठीक नहीं है । राज्य की जनता के लिए, बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कमिटेड हैं । जो वादा करते हैं, एक–एक करके धरातल पर उतारने का काम करते हैं । ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री में क्षमता है ।

श्री संदीप सौरभ : माइक्रो फाइनेंस पर बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माइक्रो फाइनेंस पर भी आएंगे, आप बैठिए ।

अध्यक्ष : बैठिए संदीप बाबू ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माइक्रो फाइनेंस पर भी बोलेंगे । धैर्य रखिएगा, हम नोट किए हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरूण जी, कृपया बैठ जाइये । सुनिए, सरकार का उत्तर हो रहा है । सरकार की बातों को सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो फरेब करने वाले हैं, जो जालसाज लोग हैं, चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों न हो, वे बचने वाले नहीं हैं । उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और भी एक–दो सवाल इन्होंने उठाये हैं, उसकी भी जांच कराएंगे । लेकिन आपको एक सलाह देना चाहते हैं। सलाह इसलिए देना चाहते हैं अरूण बाबू, कि महिलाओं को भड़काइए नहीं। महिलाओं को गलत रास्ता मत बताइए । सही रास्ते पर चलने दीजिए और उनको रोजगार के क्षेत्र में आप उनको आगे बढ़ाइए । यह बात आपसे मैं कहना चाहता हूं ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम), सी0पी0आई0(एम0एल0)(एल0) दल के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

महोदय, ये लोग जाना चाह रहे हैं ? महोदय, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि महिला रोजगार में 1 करोड़ 81 लाख हमने जीविका की दीदियों के खाते में दस–दस हजार रुपया दिया है और कुल 18,100 करोड़ की राशि उनके खाते में हमारी महिलाओं के रोजगार के लिए भी हम लोगों ने दी है । ये तो जीविका के बारे में जब बताने लगे, अभी तो और बताते, लेकिन ये लोग चले गए । महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं । प्रधानमंत्री आवास

में हम भारत देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं । महोदय, वर्ष 2024–25 में हमको जो आवास मिला, वर्ष 2024–25 में हमको 12 लाख 19 हजार लक्ष्य मिला । इतना लक्ष्य अभी तक बिहार को कभी नहीं मिला था और ये कहते हैं कि बिहार के गरीबों की चिंता हमको नहीं है । बिहार के गरीबों की चिंता हमको भी है, नीतीश कुमार जी को भी है और भारत सरकार को भी है । उन्होंने पैसा हमको दिया है उनका आवास बनाने के लिए । इस समय मुख्यमंत्री आवास योजना भी बिहार में हमने शुरू की है । इसलिए देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हमने शुरू की थी । जो प्रधानमंत्री आवास में छूटे लोग थे, उनके लिए यह योजना हमने शुरू की थी ।

दूसरी योजना एक और हमने शुरू की बिहार में– मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना । ये लोग चले जाते हैं, गरीब का रिप्रेजेंट कहते हैं, करते हैं, लेकिन गरीबों से ममता इनको नहीं है । यह बात सुनते और अभी कई माननीय सदस्य ने कहा कि गरीब को जमीन मिल जाती है और उस पर काबिज नहीं होता है । बिहार में जो हमारी सरकार है, गरीबों के लिए हम 5 डिसमिल जमीन देते हैं । अगर जमीन वहां पर नहीं है सरकारी और आवास पाने के हकदार हैं, तो उनको राज्य के खजाने से एक लाख रुपया देते हैं । यह बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में योजना हमारे जैसी नहीं है ।

महोदय, उनको घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपया, उनको 12 हजार रुपया शौचालय बनाने के लिए, 90 दिन और 95 दिन की मनरेगा से मजदूरी देते हैं । 1 लाख 55 हजार से भी ज्यादा राशि एक गरीब को घर बनाने के लिए हम यहां पर देते हैं । मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना भी एक है महोदय, जो 1 मार्च 2010 से पहले जिनके आवास बने हैं और आवास खराब हो गए हैं, उसके अलावे आवास पूर्ण नहीं हुए हैं । उनको राज्य के खजाने से हम 50 हजार रुपया देते हैं । इसमें 41 हजार से ज्यादा गरीबों को हमने ये आवास बनाने के लिए पैसा दिया है और उनके आवास पूर्ण हो रहे हैं ।

महोदय, जल–जीवन–हरियाली अभियान में बिहार देश का पहला राज्य है जहां दुनिया में जब जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि सभी राजनीतिक दल और दोनों सदनों के सभी सदस्यों के साथ बैठक की। महोदय, बैठक करके फैसला लिया कि बिहार में हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 2019 को इस अभियान की शुरुआत हमने की ।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनी । 5 करोड़ से ज्यादा बिहार की सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि बिहार से हर हालत में हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे ।

महोदय, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बिहार में जल–जीवन–हरियाली योजना हमने जो चलायी ।

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दुबई के सी0सी0पी0–28 सम्मेलन में, जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत किए गए प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है ।

चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार बिहार को मिला ।

20वां सी0एस0आई0ई–गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ ।

तुलनात्मक दृष्टिकोण से राज्य के भू–जल स्तर में बढ़ोतरी एवं हरित आच्छादन में वृद्धि हुई ।

महोदय, ये लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, इनको कुछ बुझाता नहीं है ? इसी प्रकार से जल–जीवन–हरियाली योजना में हमने आहर को, पईन को, पोखर को उसमें जो गाद थी, उसको भी ठीक करने का काम किया । वैकल्पिक फसलों के लिए टपकन सिंचाई योजना, खेती एवं नई तकनीक का उपयोग करके जलवायु अनुकूल कृषि हेतु कार्य हम लोगों ने किये हैं ।

महोदय, इसी प्रकार से राज्य भर में 21 करोड़ 13 लाख पौधे भी हमने लगाये और बड़े पैमाने पर पौधशाला का भी हमने निर्माण कराया है । 3 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा आज हमारी पौधशाला में पौधा वहां पर है।

महोदय, इसी प्रकार से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम काफी तेजी से बिहार में हो रहा है । राज्य सरकार इसको प्राथमिकता में लेते हुए हर घर में सौर ऊर्जा लगाने की सरकार की योजना है । अब हर गरीबों के घर के ऊपर सौर ऊर्जा की रोशनी मिलेगी ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मनरेगा 2025–26, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त मानव दिवस के जो हमारे लक्ष्य हैं । महोदय, 21 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है । अब तक 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हमने मानव दिवस सृजन किया है । मनरेगा से खेल मैदान का निर्माण कराया है । हम लोग बच्चों के लिए गांव के स्तर पर हर पंचायत में खेल मैदान बनाने का काम मनरेगा योजना से कर रहे हैं । हमने 5,324 लक्ष्य रखा है, जिसमें 5,100 से ज्यादा खेल मैदान हमारे पूर्ण हो गए हैं ।

आज पशु शेड हम जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ाते हैं, 44 हजार से भी ज्यादा यहां पर हमने पशु शेड बनाया है। जीविका भवन की स्वीकृति दी है । मनरेगा योजना से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया है ।

उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मार्च के बाद हमारी वी0वी0 रामजी योजना शुरू हो जाएगी । महोदय, सात निश्चय–3 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दुगना रोजगार, दुगनी आय सुनिश्चित करने हेतु....

(क्रमशः)

टर्न–28 / हेमन्त / 17.02.2026

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 2025–26 में महात्मा गांधी मनरेगा में ग्रामीण हाट विकसित किये जाने की हमारी योजना है। महोदय, इसी प्रकार से हमारी वी0बी0 जी राम जी योजना, जो भारत सरकार द्वारा मार्च में शुरू होगी। वी0बी0 जी राम जी अधिनियम में चार प्राथमिकताओं पर विचार किया गया है– जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका, जलवायु लचीलापन पर केन्द्रित कार्य सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

महोदय, इसी प्रकार से बिहार में हम लोहिया स्वच्छ अभियान में प्रथम चरण में, जिसकी चर्चा हमारे लोजपा के माननीय सदस्य कर रहे थे, कह रहे थे कि जो गरीबों के शौचालय बने हैं, उसको ठीक से फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से समीक्षा हम करेंगे। महोदय, प्रथम चरण में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हमने शौचालय का निर्माण कराया है। 9 हजार 435 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई राज्य के सभी ग्राम पंचायतों, घर–घर से कचरा का उठाव की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य को सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में पहल है तथा बीमारियों से मुक्ति के लिए भारत और बिहार की सरकार काम कर रही है। सामुदायिक सोकपीट 1 लाख 96 हजार से ज्यादा निर्माण कराया है। जक्शन चेंबर 82 हजार 661 से भी ज्यादा हमने किया है। बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। द्वितीय चरण में 5 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है।

महोदय, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय की बात हमारे माननीय सदस्य गैर सरकारी संकल्प और तारांकित प्रश्नों के माध्यम से करते रहते हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि अब बिहार में मात्र 49 ऐसे स्थान हैं, जहां पर कुछ विवाद है और 32 ऐसे स्थान हैं, जहां जमीन उपलब्ध नहीं हुई है, उसको भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। कुल 486 हमारे भवन, आज प्रखंड और अंचल कार्यालय के भवन बन रहे हैं।

महोदय, आधार पंजीकरण का काम भी करते हैं। आज 18 वर्ष से ऊपर के 8 करोड़ 47 लाख 63 हजार 72 से ज्यादा लोगों का हमने आधार

कार्ड बनाया है। 5 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के 3 करोड़ 32 लाख 68 हजार से ज्यादा का आधार कार्ड बनाया है। जीरो से 5 आयु वर्ग के 27 लाख 31 हजार, राज्य में कुल 12 करोड़ 7 लाख 63 हजार, हम लोगों ने आधार का पंजीकरण कराया है।

महोदय, इसी प्रकार, विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार की सरकार द्वारा देश एवं विशेषकर राज्य में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धन परिवार तक पहुंचाने में बड़ी संख्या में विकास संबंधी पेशेवर को तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्च ज्ञान प्रदीप शिक्षण संस्थान के रूप में किया गया है। पटना के बिहटा में 250 करोड़ की लागत से भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, कार्य प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय, हम सामाजिक अंकेक्षण का भी काम करते हैं। हमने 2018–19 से लेकर 2026 तक 72,292 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रही कई योजनाओं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना, नल जल योजना एवं लोहिया स्वच्छ अभियान जैसी योजनाओं का हमने सामाजिक अंकेक्षण कराया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, चूंकि विपक्ष के लोग तो सब चले गए हैं, कटौती प्रस्ताव वापस लें।

(व्यवधान)

आ गए हैं ? धन्यवाद। माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और अध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या 42 को गांव, गरीब, महिला के रोजगार, गरीबों के आवास पूर्ण कराने, मजदूरों को रोजगार दिलाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कराने के लिए 23701,17,90,000/– (तेइस हजार सात सौ एक करोड़ सत्रह लाख नब्बे हजार) रूपये की राशि सदन से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रूपये से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 23701,17,90,000/– (तेइस हजार सात सौ एक करोड़ सत्रह लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–45 (पैंतालीस) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजिविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम–2025 जिसे सामान्यतः भी0बी0 जी राम जी कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है, विकसित भारत गांरटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) मनरेगा अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करता है।

अध्यक्ष महोदय,

भी0वी0 जी राम जी अधिनियम में चार प्राथमिकताओं पर विचार की गयी है:–

1. जल सुरक्षा, 2. ग्रामीण अवसंरचना, 3 आजाविका, 4 जलवायु लचीलापन पर केन्द्रीत कार्य सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से टिकाउ विकास सुनिश्चित करते हैं।

भी0पी0 जी राम जी अधिनियम में ग्राम पंचायत आधारित उपकरणों और पी0एम0 गति शक्ति लेयर्स का उपयोग कर योजना तैयार करेगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPV) को पी0एम0 गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकृत किया गया है। ग्रामीण कार्यो की स्थानीक अनुकूल सुनिश्चित करता है तथा चयनित योजनाऐं विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VBNRIS) में एकत्रित है।

अध्यक्ष महोदय,

भी0बी0 जी राम जी ग्रामीण विकास कार्यो की स्थानीक अनुकूल सुनिश्चित करता है तथा चयनित योजनाओं में विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VBNRIS) में एकत्रित होते है, तथा विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPY) से उत्पन्न सभी ग्रामीण सार्वजनिक कार्य का एकीकृत डिजटल रजिस्टर है।

अध्यक्ष महोदय,

तकनीकि हस्तक्षेप अनिवार्य कर अधिनियम में पारदर्शिता निगरानी और फर्जीवाड़ा को रोकथाम सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रावधान डिजिटल इको–सिस्टम पर आधारित है, जिसमें श्रमिकों की उपस्थिति का बायो–मैट्रिक प्रमाणीकरण जी0पी0एस0 ट्रैकिंग और ए0आई0 का उपयोग शामिल किया गया है। किसानों की रोपनी, बुआई, कटनी के समय 60 दिन तक भी0वी0 राम जी का काम बन्द रखा गया है, क्योंकि किसान की खेती के समय श्रमिक की कमी नहीं हो तथा किसानों का कृषि कार्य बाधित नहीं हो।

जीविका

ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल समुहो की संख्या– 11 लाख 45 हजार से भी ज्यादा है। कुल परिवार 01 करोड 40 लाख से भी ज्यादा जोड़ा गया है। विभिन्न बैंकों में स्वयं समूह सहायता को बचत खाता खोला गया उसकी संख्या 10 लाख 53 हजार है।

रोजगार के लिए बैंको से 62 हजार 628 करोड़ रूपये ऋण दिलाया गया तथा रोजगार देने के लिए बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण देकर 6 हजार 459 ग्राहक सेवा केन्द्र खोला गया है। जीविका से जुड़ी दीदी का बीमा कराया गया है ताकि संकट की

घड़ी में बीमा हमारा सहारा बन कर सामने आ सके। इसमें 91 लाख 11 हजार से ज्यादा जीविका दीदियों का बीमा किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारंभिक पुंजी (आई0सी0एफ0) में 7 हजार करोड़ 566 हजार 90 हजार
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में आर0एफ0 में 3 हजार करोड़ 89 लाख 94 हजार
- अब तक कूल अनुदान के रूप 2006 अबतक 15 हजार करोड़ रूपया आर्थिक सहायता दी जा गयी है। ये राशि महिलाएँ सशक्त और आत्म निर्भर बनी है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में दीदियों को रोजगार को बढ़ावा और जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025–26 में 1 लाख 29 हजार समूह को बैंकों से 7 हजार 52 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया साथ ही महिलाओं की उद्यमशिलता को और अधिक बढ़ावा प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्थान बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड जीविका निधि का गठन किया गया।

राज्य में 2006 से अबतक बैंको से ऋृण के रूप में जीविका दीदी को स्वय सहायता से मात्र 1 रूपया में ऋण उपलब्ध करायी जाती है। अबतक बैंकों से ली गयी ऋण को समय पर 99 प्रतिशत राशि चुकता करती है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य भर में बकरी पालन एवं पशुपालन से जुड़कर जीविका दीदी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें अबतक 09 लाख 78 हजार परिवार से ज्यादा सशक्त हो रही है।

अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादन कम्पनी बनाकर 19 हजार 956 परिवार को जोड़ा गया। आज हमारी दीदियॉ काफी तरक्की कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

- कृषि से जोड़कर रोजगार का अवसर नई तकनीक से खेती के कार्य में 42 लाख 54 हजार किसान दीदी काम कर रही है।
- राज्य में जीविका दीदी के द्वारा 61 उत्पादक कम्पनी बनाकर दीदी उत्पादकों बाजार से जुड़कर उनकी आमदनी बढ़ रही है।
- राज्य में 520 कस्टम हायरिंग सेन्टर चालित किया जा रहा है।
- जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 6 हजार 876 किसानों को जोड़ा गया।
- वर्ष 2025–26 में 3 लाख 31 हजार से ज्यादा दीदी किसानों को कृषि से संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया।
- वर्ष 2025–26 में 1 करोड़ 53 लाख लीटर नीरा का उत्पादन एवं बिक्री की गयी।

अध्यक्ष महोदय,

दीदी का रसोई निम्नलिखित संस्थानों में संचालन की जा रही है।

- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में कैन्टीन, राजगीर
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के हास्टल कैन्टीन
- मेडिकल कॉलेज में केन्टीन एवं कपड़ा धुलाई का काम
- जिला अस्पताल में कैन्टीन
- अनुमंडल अस्पताल में कैन्टीन
- सभी प्रखंड कार्यालयों में कैन्टीन एवं सफाई का काम
- परिवहन विभाग के बस सटैण्ड में कैन्टीन

अध्यक्ष महोदय,

- मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर बनाकर रोजगार का अवसर के साथ–साथ 29 लाख बैग का निर्माण।
- कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला में दीदी का रसोई, कपड़ा धुलाई साफ सफाई, कपड़ा सिलाई प्रशिक्षण।
- बिहार पुलिस एकैडमी, राजगीर में प्रशिक्षण पा रहे हैं पुलिस के लिए पोशाक सिलाई का काम।
- कोईलवर एवं गोरौल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है।

राज्य भर में 1 हजार 365 सिलाई मशीन में माध्यम सिलाई कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में सिलाई केन्द्र खोली जा रही है, जिसके 40 हजार से ज्यादा जीविका दीदी को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 51 हजार से ज्यदा दीदी को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024–25 एवं 2025–26 में डबल इंजन की सरकार में 12 लाख 19 हजार लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया गया है और हर गरीबों के पास अपना पक्का मकान हो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीबों का अपना पक्का मकान हो इसके लिए भारत सरकार ने जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में किसी कारणवस छूट गया था उसे जोड़ने के लिए सर्वे कराने का निदेश मिला और आज 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार का नाम जोड़कर भारत सरकार को भेजा गया है, जैसे ही बिहार को लक्ष्य प्राप्त होगा इन गरीबों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति शीघ्र दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से छुटे लाचार और परेशान लोगों को राज्यभर में लगभग 91 हजार से ज्यादा गरीबों के लिए आवास की स्वीकृति दी गयी है।

इसके लिए बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ।

मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी बिहार के गरीबों की चिन्ता करते है।

जिन गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है और आवास के पात्र हैं तो उन्हें राज्य सरकार के तरफ से 5 डिसिमल जमीन दी जाती है और जहॉ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है वहॉ एक लाख रूपया जमीन खरीदने के लिए, 01 लाख 20 हजार रूपया मकान बनाने के लिए तथा 12 हजार शौचालय बनाने एवं जो मनेरेगा मजूदर उन्हें 250 रूप्या प्रति दिन 90 दिन एवं 95 दिन तक की मजदूरी भी दी जाती है। इस तरह एक लाभुक को कुल राशि 1 लाख 55 हजार 750 रूपया मिलता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहॉ इस तरह की चिंता गरीबों के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय,

हमारे नेता, श्री नीतीश कुमार जी गरीबों की चिंता करते हैं और उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना राज्य में चलाकर वैसे परिवार जिनका आवास 01 मार्च, 2010 के पूर्व स्वीकृति मिली है जो किसी कारणवश नहीं हो सका या जर्जर है उनके घरों को पूरा करने के लिए सरकार 50 हजार रूपया राज्य के खजाने से दने का फैसला लिया गया है, जो देश का पहला राज्य बिहार है। इसमें 41 हजार से ज्यादा गरीबों को इसका लाभ दिया गया तथा 216 करोड़ 61 लाख से अधिक राशि दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 72 हजार से जयादा "**महिला संवाद**" किया गया है। मैनें 18 जिला में जाकर जीविका दीदीयों की बात को सुना है तथा उनके सुझाव को समेतिक कर मुख्यमंत्री जी को भेजा गया।

जीविका दीदियों के सुझावों को बिहार की सरकार एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दीदी के सुझाव को एक एक कर मान ली और आज बिहार में एक एक योजना लागु की गयी है तथा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय,

दीदियॉ सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि समाज के हर तबके एवं हर वर्ग के लोगों की चिन्ता करती है। दीदी के सुझाव की देन है कि वृद्धजनों के पेंशन के लिए 1 हजार राशि का सुझाव दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने 11 सौ कर दिये।

देश का पहला राज्य बिहार जहॉ घर–घर में बिजली कनेक्सन संबंध दिया गया, लेकिन गरीब लोगों को बिजली बिल के भुगतान में समस्या आने लगा थी, उनके घरों की बिजली काटी जा रही थी। जीविका दीदी के सुझावों पर 1 सौ 25 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गयी।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के हर ग्राम पंचायत में जीविका भवन हर ग्राम पंचायत में विवाह मंडप निर्माण, हर प्रखंड में दीदी की लाईब्रेरी, दीदी अधिकार केन्द्र की स्थापना एवं राज्य के हास्पिटल में 45 स्वास्थ्य सहायता केन्द्र की स्थापना करने का फैसला लिया गया जिसे धरातल पर उतारा जा रहा है।

विपक्ष के नेताओं के समझ से परे हैं ये सिर्फ सरकार की आलोचना और कमियों को ढुंढने में पुरा समय बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय,

जीविका के माध्यम से राज्य के प्रत्येक प्रखंड में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे है। पटन जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड के जीविका दीदी की बेटी हवाई जहाज में एयर होस्टेज का काम कर रही है।

1. ईशा कुमारी, ग्राम– पीरही, पंचायत– नारीपिरही, प्रखंड– दुल्हिन बाजार जो हैदराबाद के एयरपोर्ट पर कार्यरत है जिनका सैलरी 60 हजार रूपया प्रति महीना है। 2. वही दूसरी बेटी, राधा यादव, ग्राम– सिंघरा कोपरा, प्रखंड– दुल्हिन बाजार जो वर्त्तमान में दुबई में कार्यरत है इनका सैलरी 80 हजार रूपया प्रति महीना है।

अध्यक्ष महोदय,

हाल ही में पटना जिले के बेलछी प्रखंड में रोजगार मेला में रोजगार पाने वाले पटना जिले के 3. सुमित कुमार, 4, गोविन्द कुमार दोनों एक ग्राम– जगजारण, प्रखंड– बेलछी जो वर्त्तमान में पेटीएम कंपनी में 3 लाख सलाना रूपया कमा रहे हैं।

लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान

अध्यक्ष महोदय,

- स्वच्छ भारत मीशन (ग्रामीण) प्रथम चरण
- अब तक राज्य में 1 करोड़ 22 लाख शौचालय का निर्माण कराया गया ।
- 9 हजार 435 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई राज्य के सभी ग्राम पंचायतों घर–घर से कचरा का उठाव की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में पहल है तथा विमारियों से मुक्ति के लिए भारत सरकार बिहार सरकार चिन्हित है।
- सामुदायिक सोकपीट 1 लाख 96 हजार से ज्यादा निर्माण
- जक्शन चैम्बर का निर्माण 82 हजार 661 से ज्यादा किया गया है।
- वायो गैस उत्पादन के लिए गोर्बधन योजना की सुरूआत की गयी जिसकी 36 जिलों में काम किया गया।
- द्वितीय चरण में व्यक्तिगत शौचालय 5 लाख बनाने का लक्ष्य रखा गया ।

सतत जीविकोपार्जन योजना

अध्यक्ष महोदय,

बिहार देश का पहल राज्य है जहॉ शराब, ताड़ी बेचकर परिवार को चलाने वाले को चिन्हित कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु राज्य के खजाने से 2 लाख रूपये तक आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया।

राज्य में एक ऐसे परिवार को चिन्हित किया जिसके घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं हैं तथा उनके घर में वृद्ध सास–ससुर एवं दो–दो बच्चे हैं। एक महिला पॉच लोगों की रोटी, कपड़ा एवं दवाई का प्रबंधन कर सकेते उनके लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।

बिहार देश का पहला राज्य है जहॉ सतत् जीविकोपार्जन योजना चलायी जा रही है।

आज राज्य में 31 लाख 71 हजार से ज्यादा महिलाएँ लाखपति दीदी बन गयी है, समाज में खुशहाली है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान योजना

अध्यक्ष महोदय,

पूरी दुनिया जब जलवायु परिवर्त्तन से परेशान था तब देश और राज्यों के सामने बड़ी चुनौतियॉ थी वैसे समय में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधान मंडल के सभी सदस्यों के साथ दलगत भावना से उपर उठकर जलवायु परिवर्त्तन से मुकाबला की तैयारी आरम्भ की गयी और राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2019 को जल–जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत की गयी। इस अभियान में कई महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार को प्राप्त हुआ

बिहार देश का पहला राज्य है, जहॉ जलवायु परिवर्त्तन को रोकने के लिए मानव ऋृखंला बनाया गया और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और पूरे देश को संदेश दिया के इस खतरे से निजात नहीं पया गया, तो लोगों को इसके दृष्परिणाम भुगतने होंगें।

अध्यक्ष महोदय,

1 बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दुबई के सी0सी0पो0– 28 सम्मलेन में जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत किये गये प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है।

3. चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ट राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला।

4. 20वॉ सी0एस0आई0–ई गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एकसेलेश प्राप्त हुआ है।

5. तुलनात्मक दृष्टि से राज्य के भू–जल स्तर में बढ़ोतरी एवं हरित अच्छादन में वृद्धि हुआ है।

अध्यक्ष महोदय,

सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं तालाब/पोखर, आहर, पईन को चिन्हित कर गाद की सफाई की गयी।

1. 26 हजार 310 तालाबों एवं पोखर के गाद सफाई की गयी
2. 78 हजार 30 आहर एवं पईन की गाद सफाई कराई गयी
3. 38 हजार 255 सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार कराया गया।
4. 30 हजार 843 सार्वजनिक कुऑ के किनारे सोखता का निर्माण कराया गया ।
5. 2 लाख 22 हजार 284 सार्वजनिक चापाकल के किनारे सोखता का निर्माण कराया गया।
6. 75 हजार 16 नये जल श्रोतों का सृजन कराया गया।
7. 13 हजार 184 छोटी–छोटी नदियों चेकडैम का निर्माण कराया गया ।
8. 14 हजार 621 सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण गया।

अध्यक्ष महोदय

वैकल्पिक फसलों टपकन सिंचाई जैविक खेती एवं नई तकनीकों का उपायों से जलवायु अनुकूल कृषि के तहत की जा रही है। खेती 2 लाख 71 हजार 571 एकड़ में

- कृषि योग भूमि 1 करोड़ 43 लाख 85 हजार 389 है।
- जैविक खेती 86 हजार 152 एकड़ में की जा रही है।
- टपकन सिंचाई चिन्हित की जा रही है खेती 51 हजार 968 एकड़ में।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य भर में 21 करोड़ 13 लाख पौधा लगाया तथा बड़े पैमाने पर पौधाशाला का निर्माण कराकर 3 करोड़ 83 लाख 34 हजार से ज्यादा पौधा रखने की क्षमता है।

- सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों के जन्मदिवस, माता–पिता के पूण्य तिथि तथा त्योहारों के अवसर पर एक पौधा लगाये साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करें इससे जलवायु परिवर्त्तन पर जल्द नियंत्रण पाया जा सकता है।
- सौर उर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा दी जा रही है, तथा राज्य सरकार इस प्राथमिकता को प्रदान कर रही है। हर घर में सौर उर्जा लगाने की सरकार की योजना है। अब हर गरीबों के घर में सौर उर्जा से रौशनी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय,

महात्मा गॉधी मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2025–26 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त मानव दिवस का लक्ष्य 21 करोड़।

अबतक 19 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजन किया जा चुका है। लक्ष्य के 94.04 प्रतिशत है।

वर्ष 2025–26 में पौधारोपण

- पौधा रोपन का लक्ष्य – 1 करोड़ 93 लाख
- अब तक पौधारोपन – 1 करोड़ 4 लाख
- वन पोषण की संख्या – 39 हजार 683
- नर्सरी की संख्या – 326 है।

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण क्षेत्र में खेल का बढ़ावा तथा ग्रामीण प्रतिभा उच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना से प्रत्येक पंचायत में जहॉ सरकारी जमीन उपलब्ध है वहॉ खेल मैदान का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

बिहार देश का पहला राज्य है जहॉ एक साथ इतने बड़ी तादात में एक साथ खेल मैदान बनाने का निर्णय लेकर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है।

- खेल मैदान लक्ष्य– 5 हजार 324
- पूर्ण खेल मैदान – 5104
- अपूर्ण खेल मैदान – 220
- मनरेगा से पशु शेड का निर्माण– 44 हजार से भी ज्यादा जीविका भवन की स्वीकृति 350 है।
- मनरेगा योजना से ऑगनवाड़ी भवन का निर्माण– 1 हजार 904 कराया गया ।

अध्यक्ष महोदय

भी0वी0 राम जी योजना के तहत सात निश्चय– 3 में ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार, दोगुना आय सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 2025–26 में महात्मा गॉधी मनरेगा से ग्रामीण हाट विकसित किये जाने की योजना ली गयी है।

प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में जीर्ण–शीर्ण प्रखंडों के भवन एवं आवासीय परिसर तथा निरीक्षण कमरा का निर्माण में प्राथमिकता कुल– 82

पूर्ण करा लिया – 71

कार्य प्रगति पर – 11

वर्ष 2024–25 में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के साथ आवासीय परिसर निर्माण मोडल प्राक्कलन के आधार पर 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार लगात से निर्माण जिसमें 62 की स्वीकृति दी गयी।

- सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र – 1 सौ 1 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण स्वीकृति दी गयी।
- सूचना प्रौधोगिकी बनकर तैयार– 99 एवं 2 जमीन नहीं
- प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं परिसर निरीक्षण कमरा सहित – 71, 11 विवादित
- वर्ष 2024–25 में प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं परिसर निरीक्षण कमरा सहित– 62

241 – 4 विवादित

32 भूमि उपलब्ध नहीं

कुल– 473, विवादित 49

486 विवादित भूमि उपलब्ध नहीं 49

आधार पंजीकरण

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में जातिगत गणना 2023 में करायी गयी इसके अनुसार आधार सृजन की संख्या– 12 करोड़ 8 लाख

- 18 वर्ष से उपर व्यस्क – 8 करोड़ 47 लारख 63 हजार 72
- 5 वर्ष से 18 वर्ष आयुवर्ग – 3 करोड़ 32 लाख 68 हजार 836
- 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग बच्चें – 27 लाख 31 हजार 909
- राज्य में कुल 12 करोड़ 7 लाख 63 हजार 747
- 0 से 5 वर्ष वाले बच्चों का समाज कल्याण विभाग से सहयोग की जा रही है।

आधार सेवा संबंधी कार्य का अनुश्रवण सुचारू रूप से चले इसके लिए जिलास्तर पर आधार अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

राज्य भर के सभी प्रखण्ड, सभी अनुमंडल, सभी नगर पंचायतों, सभी नगर परिषदों एवं जिला मुख्यालय में 1 हजार 10 स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

अध्यक्ष महोदय,

विकास प्रबंधन

विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार सरकार द्वारा देश एवं विशेष कर राज्य में विकास संबंधी कार्यो के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धन परिवार तक पहुँचाने में बड़ी संख्या में विकास संबंधी पेशवर को तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्च ज्ञान प्रदीप शिक्षण संस्थान के रूप में किया गया।

पटना के बिहटा में 250 करोड़ की लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ये कार्य प्रगति पर है।

समाजिक अंकेक्षण (सोसाईटी)

अध्यक्ष महोदय,

सामजिक अंकेक्षण से योजनाओं में लोकभागीदारी पारदर्शिता एवं जबाबदेही सुनिश्चित हुई तथा जागरूकता से मनरेगा योजना की मॉग में वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2018–19 में 255 ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2 हजार 667 ग्राम पंचायतों मनरेगा प्रधानमंत्री आवास एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जनवितरण प्रणाली के दूकान की अंकेक्षण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 38 जिलों के 5 हजार 372 ग्राम पंचायत, मनरेगा आवास, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा जन–वितरण प्रणाली के दुकाने का समवर्त्ती सामजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 38 जिलों के मनरेगा अंतर्गत 2 हजार 131, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 7 हजार 126, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 4 हजार 320, हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत 3 हजार 211 ग्राम पंचायतों एवं जन–वितरण प्रणाली के 5 हजार 50 दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में मनरेगा अन्तर्गत 7 हजार 184, प्रधानमंत्री आवाय योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 4 हजार 315, हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत 441, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत 3 हजार 343 ग्राम पंचायतों एवं जन–वितरण प्रणाली के 7 हजार 6 दुकनों का सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण कर लिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में मनरेगा अन्तर्गत 7 हजार 976 ग्राम पंचायतों में, राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम का 4 हजार 159 ग्राम पंचायतों में तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का 553 विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में मनरेगा का दिनांक– 20.01.2026 तक 7 हजार 256 ग्राम पंचायतों में एवं 1 हजार 422 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

- 2018–19 से लेकर अबतक जनवरी, 2026 तक 72 हजार 292 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रही योजना मनरेगा प्रधानमंत्री आवास, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना, नल जल योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान इत्यादि।

अध्यक्ष महोदय,

देश का पहला राज्य बिहार है, जहॉ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक दृष्टि की से सशक्त को शासक बनाने में बहुत बड़ी पहल की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।

राज्य की 1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10–10 हजार रूपये की राशि भेजी गयी है। उक्त राशि से एव स्वःरोजगार की शुरूआत की है। जिन दीदियों ने रोजगार आरंभ कर दी है, रोजगार विस्तार हेतु उन्हें पॉच किस्तों में 2 लाख तक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अभी और इसके पूर्व में जो विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य इस योजना पर गॉव–गॉव जाकर महिलाओं को योजना के विरूद्ध भड़काने काम कर रहे थे, लेकिन महिलाओं ने किसी की बात नहीं सुनी और विपक्ष का सफाया कर दिया।

आज 1 करोड़ 81 लाख दीदियॉ विपक्ष के नेताओं को खोज रही है जब येलोग क्षेत्र में जायेगें तो ऐसा ईलाज करेगे कि फिर कभी भड़काने और अन्य बात बोलकर परेशान नहीं करेंगे।

अबतक 18 हजार 100 करोड़ की राशि दीदियों के खाते में भेजा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज मुझे ग्रामीण विकास की मांग प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग गाँव और गाँव के गरीबों से जुडा हुआ विभाग है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सफल नेतृत्व में राज्य के हर चुनौतियों का सामना कर बिहार को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य भर में महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन

- महिला रोजगार योजना
- सत्तत् जीविकोपार्जन योजना
- प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण
- मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना
- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना
- जल–जीवन–हरियाली योजना
- लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार योजना
- प्रखंड भवन–सह–अंचल एवं परिसर निर्माण योजना
- विकास प्रबंधन संस्थान योजना
- मनरेगा (भी0वी0 रामजी योजना)